मेरी खेती

Page No. 1-46 नवंबर 2022

खेत खलियान

सब्ज़ी

फूल

सरकारी नीतियां

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव

किसान समाचार

औषधीय खेती

पशुपालन-पशुचारा

प्रगतिशील किसान

सलाहकार मंडल

श्री छेदालाल पाठक
(संरक्षक मार्गदर्शक)

डॉ. एमसी शर्मा,
सेवानिवृत्त निदेशक एवं कुलपति आईसीआरआई इज्जतनगर

प्रो. ए पी. सिंह
पूर्व कुलपति वेटरनरी विश्वविद्यालय मथुरा

डॉ.एस.के.गर्ग
कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस

डॉ.ओमवीर सिंह
निदेशक बीज प्रमाणीकरण (सेवानिवृत्त) उत्तर प्रदेश

डॉ. उदय भान सिंह
डीन कृषि महाविद्यालय कुम्हेर भरतपुर राजस्थान

श्री सुधीर अग्रवाल
(प्रगतिशील किसान)

दिलीप यादव
(विशेषज्ञ,मेरीखेती)

तेजपाल सिंह
(प्रगतिशील किसान)

कृष्ण पाठक
(विशेषज्ञ,मेरीखेती)

बागवानी किसानों के लिए समस्या बनती जलवायु परिवर्तन, कैसे बचाएं अपनी उपज

औद्योगिक क्रांति के बाद से पूरे विश्व भर में ग्लोबलवार्मिंग (GLOBAL WARMING) और जलवायु परिवर्तन (CLIMATE CHANGE) केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (ECOSYSTEM) के लिए एक समस्या बनकर उभरा है।

एक समय जिस स्थान पर अच्छी बारिश होती थी आज वहां हर वर्ष सूखा पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण जलवायु में परिवर्तन ही है। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर रहने वाले हर प्रजाति को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ता है, इसी नुकसान की वजह से पिछले कुछ वर्षों से फलों के लिए बागवानी खेती करने वाले किसान भाइयों को उपज में काफी कमी देखने को मिली है। उत्तरी भारत के राज्यों में फल उगाने वाले किसान अब नई वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से कुछ उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत में लगभग 7 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में फल उगाए जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 93 मिलियन टन फल प्राप्त होते हैं।भारतीय बागवानी कृषि विश्व भर के उत्पाद में लगभग 10% हिस्सेदारी निभाती है। आम, केला और अमरूद तथा अनार, अंगूर और पपीता जैसे प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।

वैश्विक तापमान में परिवर्तन और बारिश के पैटर्न में हुए बदलाव की वजह से फलदार पौधों में निम्न नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिले हैं :

तापमान में वृद्धि होने के कारण किसी भी पौधे पर लगने वाले फलों की परिपक्वता का समय कम हो जाता है। इसकी वजह से वह जल्दी तैयार हो जाते हैं और इन्हें बाजार में जल्दी बेचना पड़ता है, इससे फलों के भंडारण की संभावना कम हो जाती है और उन्हें तुरंत भेजना पड़ता है। इस वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते और उनका मुनाफा कम हो जाता है।

इसके अलावा किसी स्थान पर अधिक वर्षा या सूखा पड़ने पर फसल की उत्पादकता पूरी तरीके से कम होने के साथ ही वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है, जिस कारण फसल की गुणवत्ता पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिला है।

अधिक कार्बन-डाइऑक्साइड की वजह से फलों में स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे इन फलों के सेवन से रक्तचाप और शुगर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है।

अधिक ग्लूकोज संचित करने वजह से इन फलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है।

इसके अलावा विश्वत रेखा (EQUATORIAL AREA) के आसपास वाले क्षेत्रों में आसमान में अधिक समय तक बादल छाए रहने की वजह से वहां पर उगाए जाने वाले आम और अमरूद के फलों में एस्कोरबिक अम्ल (ASCORBIC ACID) की मात्रा घट जाती है, जिस वजह से फल में पाई जाने वाली मिठास कम हो जाती है और फुल पूरी तरह से फीका लगता है। इस कारण उसकी बाजारू मांग में भी कमी देखने को मिलती है।

बदली हुई जलवायु परिस्थितियां नए प्रकार के रोगों को जन्म दे रही है, तापमान में बढ़ोतरी होने से कई सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया पौधों की जड़ों और तने को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा इन बैक्टीरिया की वर्द्धि दर भी तेज हो जाती है, जो बाद में सीधे फलों को ही खाने लगते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो लागत को बढ़ाकर आर्थिक दबाव पैदा करते हैं।

हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक विधियों की मदद से इसे कम भले ही किया जा सकता है।

गर्मी के मौसम में पेड़ों की कटाई-छंटाई कम करनी चाहिए और पेड़ के तने और उसकी मोटी शाखाओं को सफेद रंग से पुताई कर देने पर सूरज से आने वाली किरण का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे फल के पकने में लगने वाला समय अधिक हो जाता है और किसान को अच्छी उपज के साथ ही अच्छा मुनाफा हो पाता है।

अधिक गर्मी पड़ने से बाग के क्षेत्र में नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी को बरकरार बनाए रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्र की नमी की जांच करनी चाहिए और बाग की नियमित और उचित सीमित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए।

यदि आप के बाग में पिछले सीजन के कुछ पौधे बचे हुए हैं और उनसे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें काटकर उनकी पलवार बना देनी चाहिए, जिससे बाग के क्षेत्र के तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद का इस्तेमाल करने से पौधों में नमी बनी रहती है और उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। इससे रासायनिक उर्वरक खरीदने का खर्चा भी बच जाता है।

अधिक ठंड पड़ने वाले क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए पतझड़ के समय पौधों के नीचे गिरी हुई सूखी टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा कर जलाने से भी फायदा हो सकता है।

इसके अलावा पत्तियों को जलाने से होने वाले धुआं की वजह से कई प्रकार के छोटे कीट और फल मक्खी पौधों से दूर भाग जाते हैं, इससे आपकी फलों की निरन्तर सुरक्षा भी हो पाती है।

फलों की छोटी पौध को हमेशा पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए लगाना चाहिए, इससे सूरज की किरणों का कम प्रभाव पड़ता है।

दिलीप यादव
मेरी खेती

विषय सूची

खेत खलियान PAGE NO. 1-3

1.सरसों की खेती से होगी धन की बरसात, यहां जानिये वैज्ञानिक उपाय जिससे हो सकती है बंपर पैदावार
2. जल्द ही शुरू होगी चना की बुवाई, जानिए बुवाई से लेकर कटाई तक की जानकारी
3. किसान अफीम की खेती से कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा, कैसे ले सकते हैं लाइसेंस? जानें

सब्ज़ी PAGE NO. 4-7

1. टमाटर की इन किस्मों की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल, जानें टमाटर की खेती की पूरी विधि
2. ब्रोकली की नई वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक का सहारा लेकर पहाड़ी राज्यों के किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा, आप भी जानिए पूरी प्रक्रिया
3. ठंडी और आर्द्र जलवायु में रंगीन फूल गोभी की उपज कर कमायें अच्छा मुनाफा, जानें उत्पादन की पूरी प्रक्रिया

फूल PAGE NO. 8-9

1. कैमोमाइल फसल के फूल उगाकर एलोपैथी विज्ञान में योगदान दे रहे पंजाब और महाराष्ट्र के युवा किसान, आप भी जानें क्या है कैमोमाइल की फसल और इसके फायदे

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव PAGE NO. 10-16

1. ICAR ने विकसित की नींबू की नई किस्म, तीसरे ही साल लग जाते हैं फल
2. बागवानी की तरफ बढ़ रहा है किसानों का रुझान, जानिये क्यों?
3. सही लागत-उत्पादन अनुपात को समझ सब्ज़ी उगाकर कैसे कमाएँ अच्छा मुनाफ़ा, जानें बचत करने की पूरी प्रक्रिया
4. सोयाबीन की तीन नई किस्मों को मध्य प्रदेश शासन ने दी मंजूरी
5. उर्वरकों के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं और निपटान के लिए आई नई वैज्ञानिक एडवाइजरी : उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूर करें पालन
6. भारत में पहली बार जैविक कपास की किस्में हुई विकसित, किसानों को कपास के बीजों की कमी से मिलेगा छुटकारा
7. अब एक ही पौधे पर लगेंगी दो तरह की सब्जियां, पढ़िए पूरी खबर

सरकारी नीतियां PAGE NO. 17-25

1. 66 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी यह राज्य सरकार, मिलेगी हर प्रकार की सुविधा
2. अगर बरसात के कारण फसल हो गई है चौपट, तो ऐसे करें अपना बीमा क्लेम
3. कृषि लोन लेने के लिए किसानों को नहीं होगी ज्यादा दिक्कत, रबी की फसल होगी जबरदस्त
4. स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है सरकार
5. सरकार से मिल रहा ड्रोन लेने पर 100 % तक अनुदान, तो क्यों न लेगा किसान
6.हरियाणा राज्य में कृषि सम्बंधित उपकरणों पर मिल रहा 80 % सब्सिडी, समय से करलें आवेदन
7. भंडारण की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, फ्री कूलिंग यूनिट के लिए 18 लाख रूपये देगी सरकार
8. गाय-भैंस की देशी नस्लों का संरक्षण करने वालों को मिलेगा 5 लाख का ईनाम, ऐसे करें आवेदन
9. बिहार में मशरूम की खेती करने पर सरकार दे रही 90 फीसदी अनुदान
10. देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करेगी सरकार, देश भर में बांटेगी मिनी किट
11. भारत सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये तीन नए उत्कृष्टता केंद्र

प्रगतिशील किसान PAGE NO. 44-46

1. मोती की खेती से बम्पर कमाई कर रहा है बिहार का आईटी प्रोफेशनल
2. युवक की किस्मत बदली सब्जियों की खेती ने, कमाया बेहद मुनाफा
3. महाराष्ट्र में पिता के अथक परिश्रम से प्रेरित बच्चे ने बनाया कम खर्च वाला ड्रोन
4. भंवरपाल सिंह : वकील से लेकर सर्वश्रेष्ठ आलू उत्पादक अवॉर्ड पाने तक का सफर
5. किसान ने डंक मारने वाले जहरीले बिच्छुओं को बनाया कमाई का साधन, लाखों की हो रही आमदनी

किसान समाचार PAGE NO. 26-36

1. दीवाली से पहले पीएम मोदी ने करदी किसानों की बल्ले बल्ले, खातों में भेजी पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त
2. दीवाली पर अधिक मांग की वजह से मिलावटी हो रहे तेल, दाल और मसाले
3. मध्य प्रदेश: लहसुन की फसल को खेत में जलाने पर मजबूर हुए किसान, वहीं चीन से आयात हो रहा लहसुन
4. मुख्यमंत्री योगी ने दी प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन को हरी झंडी – यूपी कैबिनेट बैठक में अहम फैसला
5. मक्के की फसल से बिहार में बढ़ेगा एथेनॉल का उत्पादन
6. बारिश ने मचाई तबाही, किसानों ने अपनी जान गंवाई
7. अब नहीं होगी किसानों को उर्वरकों की कमी, फसलों के लिए प्रयाप्त मात्रा में मिलेगा यूरिया और डी ए पी
8. गन्ना किसानों को दिवाली के तोहफे के रूप में मिलेंगे सरकार से 900 रूपए प्रति हेक्टेयर
9. पराली से प्रदुषण नहीं अब बढ़ेगी उर्वरकता
10. मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिली सहायता, 202 करोड़ रूपए हुए जारी
11. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश ने फेरा किसानों की उम्मीद पर पानी
12. देश में 5G हुआ लॉन्च, किसानों की बदल जाएगी इस तकनीक से किस्मत
13. पंजाब सरकार सिचाई पर करेगी खर्च कम, लेगी सौर ऊर्जा की मदद
14. बरसात की मार से त्रस्त हुए मौसम्बी के बाग़, किसानों में हाहाकार
15. अब इस राज्य में भी MSP पर होगी धान की खरीदी, सरकार खोलेगी 23 नई मंडियां
16. हाइवे में हजारों ट्रकों के फंसने से लाखों मीट्रिक टन सेब हुआ खराब
17. राजस्थान में लंपी के वेरिएंट बदलने की आशंका से पशुपालको में चिंता
18. भारत सरकार के सामने नई चुनौती, प्रमुख फसलों के उत्पादन में विगत वर्ष की अपेक्षा हो सकती है कमी
19. बिहार में खाद की भयंकर कमी, मांग के मुकाबले यूरिया की आपूर्ति में 22 फीसदी की कमी
20. फसल खराब होने पर किसानों को मिली क्षतिपूर्ति, सरकार ने जारी की 3 हजार 500 करोड़ की मुआवजा राशि
21. पराली मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने उठाये आवश्यक कदम, तीन राज्यों को दिए 600 करोड़ रूपये

औषधीय खेती PAGE NO. 37-39

1. ईसबगोल को जैविक खाद से तैयार करने पर दोगुनी हो गई गुजरात के किसानों की आय
2. भारतीय बाजार में बढ़ी पिपरमिंट ऑयल की मांग, ऐसे करें पिपरमिंट की खेती

पशुपालन-पशुचारा PAGE NO. 40-43

1. ये राज्य सरकार दे रही है पशुओं की खरीद पर भारी सब्सिडी, महिलाओं को 90% तक मिल सकता है अनुदान
2. मधुमक्खी पालन को बनाएं आय का स्थायी स्रोत : बी-फार्मिंग की सम्पूर्ण जानकारी और सरकारी योजनाएं
3. भारतीय स्टेट बैंक दुधारू पशु खरीदने के लिए किसानों को देगा लोन

SONALIKA
LEADING AGRI EVOLUTION

MERIKHETI

New SIKANDER DLX

DELUXE ISKI HAR BAAT

DI 50 RX

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

New Holland 5500 Turbo Super

खेत खलियान

सरसों की खेती से होगी धन की बरसात, यहां जानिये वैज्ञानिक उपाय जिससे हो सकती है बंपर पैदावार

सरसों (Mustard; sarson) भारत में एक प्रमुख तिलहन की फसल है, इसकी खेती ज्यादातर उत्तर भारत में की जाती है। इसके साथ ही उत्तर भारत में सरसों के तेल का बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि भारत तिलहन का बहुत बड़ा आयातक देश है, इसलिए सरकार भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में सरसों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है ताकि भारत को तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

सरसों की खेती रबी सीजन में की जाती है, इस फसल की खेती में ज्यादा संसाधन नहीं लगते और न ही इसमें ज्यादा सिंचाई की जरुरत होती है। एक आम और छोटा किसान कम संसाधनों के साथ भी सरसों की खेती कर सकता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय को देखें तो जलवायु परिवर्तन और मौसम की भीषण मार का असर सरसों की खेती पर भी हुआ है, जिसके कारण उत्पादन में कमी आई है और खेती लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि किसान सरकार द्वारा बताये गए वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस घाटे की भरपाई आसानी से कर सकते हैं।

किन-किन राज्यों में होती है सरसों की खेती

भारत में कुछ राज्यों में सरसों की खेती बहुतायत में होती है। इनमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात का नाम शामिल है। इन राज्यों की जलवायु और मिट्टी सरसों की खेती के अनुकूल है और राज्य के किसान भी खेती करना पसंद करते हैं।

मिट्टी की जांच किस प्रकार से करें

किसी भी फसल की खेती में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए किसान को चाहिए कि सबसे पहले वह अपने खेत की मिट्टी की प्रयोगशाला में जांच करवायें, ताकि उसे मिट्टी की कमियों, संरचना और इसकी जरूरतों का पता चल सके। मिट्टी की जांच के पश्चात किसानों को इसका रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) कहते हैं। इसमें मिट्टी के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सम्पूर्ण जानकारी होती है। कार्ड में दी गई जानकारी के अनुसार ही निश्चित मात्रा में खाद-उर्वरक, बीज और सिंचाई करने की सलाह किसानों को दी जाती है। यह वैज्ञानिक तरीका सरसों की पैदावार को कई गुना तक बढ़ा सकता है।

सरसों की बुवाई

भारत में सरसों की बुवाई प्रारम्भ हो चुकी है। वैसे तो सरसों की बुवाई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जा सकती है। लेकिन यदि इस फसल की बुवाई 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य की जाए, तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सरसों की बुवाई करने के पहले खेत को पर्याप्त गहराई तक अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद हैप्पी सीडर या जीरो टिल बेड प्लांटर के माध्यम से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों के उन्नत बीजों की बुवाई करनी चाहिए।

बाजार में उपलब्ध सरसों की उन्नत किस्में

भारतीय बाजार में वैसे तो सरसों की उन्नत किस्मों की लम्बी रेंज उपलब्ध है। लेकिन इन दिनों आरजीएन 229, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, सरसों की पीबीआर 357, कोरल पीएसी 437, पीडीजेड 1, एलईएस 54, जीएससी-7 (गोभी सरसों) किस्में को किसान बेहद पसंद कर रहे हैं। इसलिए सरसों के इन किस्मों के बीजों की बाजार में अच्छी खासी मांग है।

सरसों की फसल में सिंचाई किस प्रकार से करें

सरसों वैसे तो विपरीत परिस्तिथियों में उगने वाली फसल है। फिर भी यदि सिंचाई का साधन उपलब्ध है तो इस फसल के लिए 2-3 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। इस फसल में पहली बार सिंचाई बुवाई के 35 दिनों बाद की जाती है, इसके बाद यदि जरुरत महसूस हो तो दूसरी सिंचाई पेड़ में दाना लगने के दौरान की जा सकती है। किसानों को इस बात के विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस समय सरसों के पेड़ में फूल लगने लगें, उस समय सिंचाई न करें। यह बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है और इसके कारण बाद में किसानों को उम्दा क्वालिटी की सरसों प्राप्त नहीं होगी।

ध्यान देने वाली अन्य चीजें

सरसों की खेती में खरपतवार की समस्या एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए किसानों को खेत की निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए। साथ ही यदि खेत में खरपतवार जरुरत से ज्यादा बढ़ गया है, तो किसानों को परपैंडीमेथालीन (30 EC) की एक लीटर मात्रा 400 लीटर पानी में घोलकर खेत में स्प्रे के माध्यम से छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से किसानों को खरपतवार से निजात मिलेगी। अगर किसान चाहें तो खेत की जुताई करते समय मिट्टी में खरपतवारनाशी मिला सकते हैं ताकि बाद में परपैंडीमेथालीन के छिड़काव की जरुरत ही न पड़े।

सरसों की फसल में माहूं या चेंपा कीट के आक्रमण की संभावना बनी रहती है। ये कीट फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, इनकी रोकथाम के लिए किसान बाजार में उपलब्ध बढ़िया कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसान सरसों की खेती के साथ मधुमक्खी का पालन करते हैं तो उन्हें रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से बचना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों की जगह पर वो नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए 5 मिली लीटर नीम के तेल को 1 लीटर पानी के साथ मिश्रित करें और उसका खेत में छिड़काव करें।

सरसों की फसल में अच्छी पैदावार के लिए खेत की मेढ़ों पर मधुमक्खी पालन के डिब्बे जरूर रखें। मधुमक्खियां फसल की मित्र कीट होती है, जो पॉलीनेशन में मदद करती हैं, इससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी संभव है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आमदनी हो सकती है।

सरसों की खेती में कुछ और चीजें ध्यान देने की जरुरत होती है, जैसे- जब सरसों के पेड़ में फलियां लगने लगें तब पेड़ के तने के निचले भाग की पत्तियों को हटा दें, इससे फसल की देखभाल आसानी से हो सकेगी और पूरा का पूरा पोषण पेड़ के ऊपरी भाग को मिलेगा। इसके साथ ही यदि ठंड के कारण फसल में पाला लगने की आशंका हो, तो 250 ग्राम थायोयूरिया को 200 लीटर पानी में घोलकर फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। यह वैज्ञानिक उपाय करने के बाद फसल में पाला लगने की संभावना खत्म हो जाएगी।

जल्द ही शुरू होगी चना की बुवाई, जानिए बुवाई से लेकर कटाई तक की जानकारी

देश में खरीफ का सीजन समाप्त होने की ओर है। इसके बाद जल्द ही रबी का सीजन प्रारम्भ होने वाला है, जिसमें रबी की फसलों की बुवाई शुरू कर दी जायेगी। कई राज्यों में मध्य अक्टूबर से रबी की फसलों की बुवाई शुरू कर दी जाती है, तो कई राज्यों में दिसंबर तक जारी रहती है। आज हम आपको ऐसी ही खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको भारत में बड़ी मात्रा में किया जाता है और किसान इसकी खेती करना बेहद पसंद भी करते हैं। यह एक दलहनी फसल है जिसे हम चना (chana; bengal gram; chickpea) के नाम से जानते हैं।

भारत सरकार लगातार दलहनी फसलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसको लेकर सरकार समय-समय पर कई माध्यमों से किसानों को दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहित करती रहती है। चने की खेती एक फायदे की खेती होती है, जिसे करने से किसान ज्यादा रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि इसका भाव अन्य फसलों के मुकाबले बेहतर रहता है।

चने का उपयोग भारत में अंकुरित फूड से लेकर कई व्यंजनों में किया जाता है। इसकी फसल मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में की जाती है। वर्तमान में भारत चना उत्पादन के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है।

चने की कौन-कौन सी उन्नत किस्में किसानों को पहुंचा सकती हैं फायदा ?

चने की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्में के साथ उन्नत बीजों का चयन करना बेहद आवश्यक है। चना मुख्यतया तीन प्रकार का होता है, जिसे हम काला चना या देशी चना, काबुली चना और हराचना के नाम से जानते हैं।
इन तीन प्रकार के चनों की कई किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए –
काला चना या देशी चना में वैभव, जेजी-74, उज्जैन 21, राधे, जे. जी. 315, जे. जी. 11, जे. जी. 130, बीजी-391, जेएकेआई-9218, विशाल जैसी किस्में बाजार में उपलब्ध हैं।
काबुली चने में काक-2, श्वेता (आई.सी.सी.व्ही.- 2), जेजीके-2, मेक्सीकन बोल्ड जैसी किस्में बाजार में आसानी से मिल जाती हैं।
हरे चने में जे.जी.जी.1, हिमा जैसी किस्में बाजार में किसानों को बेहद आसानी से प्राप्त हो जाएंगी।

चने की खेती के लिए मिट्टी का चयन किस प्रकार से करें ?

वैसे तो भारत में चने की खेती हर तरह की मिट्टी में की जाती है। लेकिन इस फसल की खेती के लिए रेतीली और चिकनी मिट्टी, अन्य मिट्टियों की अपेक्षा बेहतर मानी गई है। इन मिट्टियों में चने की पैदावार होने की संभावना अन्य मिट्टियों की अपेक्षा ज्यादा है।

चने की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। साथ ही जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खेत में पानी भरने पर फसल को सड़ने से बचाया जा सके।
अगर किसान बुवाई के पहले मिट्टी का प्रायोगिक परीक्षण करवाते हैं तो बेहतर होगा। इससे खेती में लगने वाली लागत को कम करने में मदद मिल सकती है।

चने की बुवाई किस प्रकार से करें ?

चने की बुवाई के पहले खेत को जुताई करके अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद सीड ड्रिल की मदद से बीज के साथ उर्वरक मिलाकर चने की बुवाई की जाती है।

अगर हम देसी चने की बात करें तो 15 से 18 किलो प्रति एकड़ की दर से चने के बीजों की बुवाई करनी चाहिए। वहीं अगर काबुली चने की बात करें तो बुवाई के लिए बीज की मात्रा 37 किलो प्रति एकड़ तक ठीक रहेगी।
इसके अतिरिक्त यदि देसी चने की बुवाई लेट होती है, तो 15 नवंबर के बाद 27 किलो प्रति एकड़ और 15 दिसंबर के आस पास 36 किलो प्रति एकड़ की दर से चने की बुवाई करना चाहिए। बुवाई करते वक़्त 13 किलो यूरिया और 50 किलो सुपर फासफेट प्रति एकड़ की दर से चने के साथ मिक्स कर सकते हैं।

किस प्रकार से करें चने की फसल की देखभाल ?

चने की फसल में बेहद सावधानी बरतने की जरुरत होती है, क्योंकि इस फसल में जलवायु परिवर्तन का असर बहुत जल्दी होता है। इसके साथ ही इस फसल में कीटों का प्रकोप भी बहुत तेजी के साथ फैलता है, जिससे फसल बहुत जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों को समय-समय पर चने की फसल की निगरानी करते रहना चाहिए।

चने की फसलों में खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हरे चारे तथा खरपतवार को हाथों से उखाड़कर समाप्त किया जा सकता है।

चने की फसल में कीटों का प्रकोप बहुत जल्दी फैलता है। इसको देखते हुए 1 लीटर पैंडीमैथालीन को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के 3 दिन बाद छिड़काव करें, जिससे फसल में कीटों के प्रकोप की संभावना पहले से ही खत्म हो जाएगी।

अगर सिंचाई की बात करें तो चने की फसल में मौसम और जमीन के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर जमीन बहुत ज्यादा शुष्क है तो इस फसल के लिए 2 सिंचाई पर्याप्त हैं। पहली सिंचाई बुवाई के 45 दिन बाद और दूसरी सिंचाई 75 दिनों बाद की जा सकती है।

चने की फसल में पैदावार

चने की फसल 110-120 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है। चने की फसल तैयार होने के साथ ही पौधा सूख जाता है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती है। जिसके बाद चने को काटकर तेज धूप में 5 दिनों तक सुखाया जाता है। इसके बाद चने की फसल की थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग के बाद किसानों को इसकी खेती में 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही पशु चारा भी प्राप्त होता है, जिसे भूसा कहा जाता है। यह पशुओं के खिलाने के काम आता है।

किसान अफीम की खेती से कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा, कैसे ले सकते हैं लाइसेंस? जानें

अफ़ीम (Opium or opium poppy (ओपियम पॉपी); वैज्ञानिक नाम : lachryma papaveris) को मादक पदार्थ के तौर पर जाना जाता है। इसका उपयोग लोग प्रारम्भिक तौर पर नशा करने के लिए करते थे, इसलिए सरकार ने इसकी सार्वजनिक खेती पर बैन लगा रखा है। चूंकि अफीम का इस्तेमाल औषध उद्योग में दवाई बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए सरकार सीमित किसानों को इसकी खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। इस लाइसेंस के माध्यम से किसान एक लिमिट में अफीम का उत्पादन करके सरकार को बेच सकते हैं। इससे किसानों को अच्छा ख़ासा मुनाफा होता है, क्योंकि सरकार इसे बेहतर भाव के साथ खरीदती है। आइये समझते हैं कि इसकी खेती के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

अफीम की खेती (Opium Farming) सरकारी अधिकारियों की कड़ी निगरानी में होती है। ऐसे में बिना लाइसेंस के इस खेती को करना, खतरे को दावत देना है। भारत में अफीम की खेती के लिए नारकोटिक्स विभाग (Central Bureau of Narcotics / केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो) लाइसेंस जारी करता है। इसलिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसानों को सर्वप्रथम नारकोटिक्स विभाग से संपर्क करना होगा। लाइसेंस के लिए नारकोटिक्स विभाग के नियम कायदे उनकी वेबसाइट में उपलब्ध हैं, जहां पर जाकर किसान इसकी जानकारी ले सकते हैं। नारकोटिक्स विभाग से मंजूरी मिलने के बाद किसान अफीम की खेती की जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

देश में हर जगह वैध नहीं है ये खेती

अफीम की खेती के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए हर किसान आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के कुछ चुनिंदा स्थानों में ही अफीम की खेती की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले में और उसके आस पास सरकार द्वारा अफीम की खेती की स्वीकृति दी जाती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी अफीम की खेती के लिए सरकार की तरफ से किसानों को लाइसेंस दिया जाता है।

अफीम की खेती के लिए इन बीजों का करें प्रयोग

वैसे तो अफीम की खेती के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं, लेकिन किसान जवाहर अफीम-16, जवाहर अफीम-539 और जवाहर अफीम-540 जैसे बीजों को उगाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इन बीजों के प्रयोग से उत्पादन ज्यादा होने के साथ-साथ अफीम की क्वालिटी भी बेहतर प्राप्त होती है। इसके अलावा नारकोटिक्स विभाग के कई इंस्टीट्यूट अफीम पर रिसर्च करते रहते हैं और किसानों को समय-समय पर नए बीज उपलब्ध करवाते हैं। एक एकड़ खेत में अफीम की खेती करने के लिए कम से कम 6 किलो अफीम का बीज इस्तेमाल किया जाता है।

किस प्रकार से तैयार होती है अफीम

अफीम की फसल 4 महीने की फसल है। बुवाई के 100 दिन बाद अफीम का पौधा परिपक्व हो जाता है और उसमें डोडे निकल आते हैं। इस डोडे से ही अफीम निकलती है, जिसके लिए प्रतिदिन इसमें चीरा लगाया जाता है, जिससे अफीम तरल रूप में रिस कर बाहर आ जाती है, जिसे किसी धारदार हथियार या हसिया से एकत्र कर लिया जाता है।

सनद रहे कि अफीम एकत्र करने का काम धूप निकलने के पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक चलती रहती है। इसके बाद बचे हुए डोडे को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।

फसल के अंत में नार्कोटिक्स विभाग किसानों से अफीम खरीद लेता है, जिसके लिए किसानों को वाजिब दाम भुगतान किया जाता है।

सब्ज़ी

टमाटर की इन किस्मों की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल, जानें टमाटर की खेती की पूरी विधि

टमाटर (Tomato; tamatar) एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग लगभग भारत के हर घर में किया जाता है। इसलिए टमाटर की फसल किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है क्योंकि इसकी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए किसानों के पास हर मौसम में पर्याप्त मौके होते हैं। भारत में टमाटर की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में की जाती है। यदि किसान टमाटर की खेती में उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करें तो इसकी खेती से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है।

बाजार में उपलब्ध टमाटर की उन्नत किस्में

आजकल वैसे तो बाजार में टमाटर की बहुत प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ उन्नत किस्में भारतीय किसान बहुतायत से प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों को आमदनी होने की संभावना बढ़ जाती है।

बाजार में उपलब्ध टमाटर की उन्नत किस्मों में पंजाब छुहारा, पीकेएम 1, पूसा रूबी, पैयूर-1, शक्ति, पंत टी3, सोलन गोला, अर्का मेघाली, सएल 120, पूसा गौरव, एस 12, पंत बहार, पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी, सीओ-1, सीओ 2, सीओ 3, एस-12, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहूती, अर्का आशीष, अर्का आभा, अर्का आलोक, एचएस101, एचएस102, एचएस110, हिसार अरुण, हिसार ललिता, हिसार ललित, हिसार अनमोल, केएस.2, नरेंद्र टमाटर 1 और नरेंद्र टमाटर 2 प्रमुख हैं।

इन किस्मों के साथ ही यदि हम टमाटर की संकर किस्मों की बात करें तो उनमें COTH 1 हाइब्रिड टमाटर, रश्मि, वैशाली, रूपाली, नवीन, अविनाश 2, MTH 4, सदाबहार, गुलमोहर, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, अर्का विशाल, अर्का वरदान, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 और सोनाली प्रमुख हैं।

कितना हो सकता है उत्पादन

अगर किसान टमाटर की उन्नत किस्मों का उपयोग करता है, तो कुछ किस्मों में एक एकड़ में 500 क्विंटल तक टमाटर की पैदावार हो सकती है। जबकि सभी किस्मों में इतनी पैदावार नहीं होती। टमाटर की पैदावार मिट्टी की उर्वरता, मौसम, खाद, सिंचाई और देखभाल पर निर्भर करती है।

टमाटर की रोपाई का सही समय क्या है

यदि किसान सितंबर-अक्टूबर में टमाटर की रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई माह के अंत में तैयार कर लें। इसके बाद पौधे की रोपाई सितम्बर या अक्टूबर में करें। इसके साथ ही यदि किसान जनवरी माह में टमाटर की रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी नवम्बर माह में तैयार कर लें। इसके बाद जनवरी या फरवरी में टमाटर की रोपाई प्रारम्भ कर दें।

कैसे तैयार करें टमाटर की पौध

टमाटर की खेती के लिए टमाटर की पौध को तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए किसान को ऐसी नर्सरी बनाना चाहिए जहां पानी का ठहराव ना हो। नर्सरी बनाने के लिए किसान को जमीन से ऊपर 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी एकत्र करना चाहिए और उसमें नर्सरी बनाना चाहिए, ऐसे में नर्सरी में पानी के ठहराव की संभावना कम हो जाती है। टमाटर के बीजों को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। इसके बाद थोड़ी सिंचाई भी करना चाहिए ताकि नमी बरकरार रहे।

जब नर्सरी में पौधे अंकुरित हो जाएं तो उसके बाद लगभग 5 सप्ताह का इन्तजार करना चाहिए। 5 सप्ताह के बाद पौधे 10-15 सेंटीमीटर लम्बे हो जायेंगे। जिनको सावधानी से खेत में रोपाई करना चाहिए।

टमाटर की खेती में विशेष ध्यान रखने वाली चीजें

टमाटर की खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन का पीएच मान 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। इस खेती के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी बेहद अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों में टमाटर की फसल ज्यादा अच्छी होती है।

यदि टमाटर गर्मियों के मौसम में लगाया गया है, तो हर सप्ताह सिंचाई आवश्यक है। जबकि सर्दी के मौसम में लगाए गए टमाटर में 15 दिनों में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए समय-समय पर खेत में निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए।

टमाटर की खेती में किस प्रकार से इस्तेमाल करें खाद एवं उर्वरक

टमाटर की खेती में जैविक खाद का इस्तेमाल बहुतायत से किया जाता है। इसके अलावा किसान प्रति हेक्टेयर नेत्रजन-100 किलोग्राम, स्फूर-80 किलोग्राम तथा पोटाश-60 किलोग्राम के हिसाब से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

टमाटर की खेती में किस प्रकार से करें खरपतवार का नियंत्रण

टमाटर की खेती में पानी की सिंचाई होती रहती है, जिससे खरपतवार को फलने फूलने में सहायता मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई निराई-गुड़ाई के आलावा खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई 'लासो' खरपतवार नाशी का 2 किलोग्राम/हैक्टेयर कि दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की रोपाई के 4-5 दिन बाद स्टाम्प का भी 1 किलोग्राम प्रति हैक्टर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खरपतवार की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाता है और फसल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

ब्रोकली की नई वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक का सहारा लेकर पहाड़ी राज्यों के किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा, आप भी जानिए पूरी प्रक्रिया

यदि आप भारत के पहाड़ी राज्य वाले क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो सब्जी की दुकानों पर ब्रोकली (broccoli) की सब्जी जरूर देखने को मिलती होगी, वहीं दक्षिण भारत और मध्य भारत वाले राज्यों में ब्रोकली कुछ ही स्थानों पर उगायी जाती है। यह एक पोषक तत्व वाली सब्जी की फसल होती है जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों के अलावा कार्बोहाइड्रेट और आयरन के साथ ही सभी प्रकार के विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य के प्रति सतर्क युवा जनसंख्या ब्रोकली की बाजारू मांग को काफी तेजी से बढ़ा रही है।

ब्रोकली खाने के फायदे :

ब्रोकली सब्जी में कई प्रकार के फाइटोकेमिकल (Phytochemical) या पादपरसायन होते हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होते हैं और इसके सेवन से प्रोस्टेट कैंसर तथा ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोगों के प्रति सुरक्षा हासिल की जा सकती है।

गर्भवती महिलाएं भी शरीर के बेहतर विकास और पेट में पल रहे शिशु की बेहतर उन्नति के लिए ब्रोकली का सेवन करती हैं।

ब्रोकली उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु और तापमान :

यह एक व्यावसायिक सब्जी है। अक्टूबर और नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में बोई जाने वाली ब्रोकली, शीत क्षेत्र में उगने वाली सब्जी है। ब्रोकली के पौधों की वृद्धि और सही विकास के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और तापमान लगभग 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहना चाहिए।

उत्तरी भारत के राज्यों में सर्दियों के समय दिन की अवधि छोटी होती है जबकि रातें लंबी होती है, ऐसी जलवायुवीय परिस्थिति ब्रोकली के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

ब्रोकली उत्पादन के लिए कैसे करें नर्सरी की तैयारी :

ब्रोकली फसल की खेत में मुख्य बुवाई करने से पहले सितंबर महीने के मध्य में नर्सरी तैयार करने की शुरुआत कर देनी चाहिए।

प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 400 से 500 ग्राम उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल कर छोटी क्यारियां बनाते हुए नर्सरी की तैयारी शुरू करनी चाहिए।

क्यारियों की चौड़ाई 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए और बीजों के बीच में कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

बेहतर बीज उपचार के लिए नर्सरी क्षेत्र की मिट्टी में केप्टोन जैसी कवकनाशी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक बार नर्सरी तैयार हो जाने के बाद पौधों को निकालकर रोपण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दो पंक्तियों के बीच में कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी अनिवार्य है।

किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि रोपण करने के तुरंत पश्चात सीमित मात्रा में ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, अधिक पानी देने से पत्तियों के पीले होने का खतरा रहता है और सब्जी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कैसे करें पोषक तत्वों का बेहतर प्रबंधन :

जैविक खाद जैसे कि गोबर और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल खेत की जुताई के समय करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

इस सब्जी की फसल को बोने से पहले कम से कम दो से तीन बार खेत की जुताई करना आवश्यक है, और इसी दौरान जैविक खाद को खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिलने के लिए पर्याप्त समय सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए।

मिट्टी की जांच करवाकर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद सीमित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा सकता है।

ब्रोकली सब्जी की क्षेत्रवार उन्नत किस्में :

यदि किसान भाई अगेती फसलों के रूप में ब्रोकली की किस्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 'स्पार्टन अर्ली' और 'प्रीमियम क्लिप' के अलावा 'डी–सिक्को' नाम की किस्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पछेती किस्मों में पूषा के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई 'पूषा ब्रोकली' और 'पालम समृद्धि' के अलावा 'ग्रीन सर्फ' जैसी किस्मों का प्रयोग बेहतर उत्पादन प्रदान कर सकता है।

ब्रोकली की फसल में होने वाले रोग और उनका समाधान :

ब्रोकली की फसल में भी गोभी के जैसे ही आर्द्रगलन और काला विगलन जैसे रोग होने की संभावना रहती है, इस प्रकार के रोग पौधे की नर्सरी तैयार करते समय तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से होते हैं।

इन रोगों की वजह से पौधे की शाखाएं काले रंग की हो जाती है और पत्तियां मुड़ कर टूट जाती है, इनसे बचने के लिए बेहतर बीज उपचार और रासायनिक उर्वरक जैसे कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

ब्रोकली की सब्जी में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका समाधान :

कई दूसरे प्रकार की फल और सब्जियों की तरह ही ब्रोकली में भी कई प्रकार के कीट लगने की संभावनाएं होती है, जैसे कि :-

गोभी छेदक कीट :
यह कीट छोटी पौध के तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की पूरी कॉलोनी के तेज आक्रमण को छोटी पौध झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से तना टूट कर नीचे गिर जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है।

इस कीट के बेहतर प्रबंधन के लिए मेटासिसटॉक्स (Metasistocks) नामक रसायनिक उर्वरक का छिड़काव बेहतर साबित होता है।

माहूँ कीट :
हरे रंग का दिखाई देने वाला यह कीट पौधे की पत्तियों में छुप जाने के बाद बाहर से आसानी से पकड़ में नहीं आता है। यह पतियों की निचली सतह में छुपे रहते हैं और पत्तियों के कोमल हिस्से के रस को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

इस रोग के इलाज के लिए हाल ही में पूषा के वैज्ञानिकों ने 'रोगोर' नामक एक दवा बनाई है, जिसका सीमित मात्रा में छिड़काव कर इस के निदान पाया जा सकता है।

इसके अलावा डायमंडबैक मॉथ कीट और और कुछ फफूंद जनित रोग जैसे की 'पत्तीयों में होने वाला धब्बा रोग ' फसल की उत्पादकता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही वैज्ञानिक तकनीक और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर इन लोगों से आसानी से निजात पाया जा सकता है।

ठंडी और आर्द्र जलवायु में रंगीन फूल गोभी की उपज कर कमायें अच्छा मुनाफा, जानें उत्पादन की पूरी प्रक्रिया

छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में रंगो का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विभिन्न प्रकार के रंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।लेकिन क्या आपको पता है कि अब ऐसी ही रंगीन प्रकार की फूल गोभी (phool gobhee; cauliflower) का उत्पादन कर, सेहत को सुधारने के अलावा आमदनी को बढ़ाने में भी किया जा सकता है।

फूलगोभी के उत्पादन में उत्तरी भारत के राज्य शीर्ष पर हैं, लेकिन वर्तमान में बेहतर वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भी फूलगोभी का उत्पादन किया जा रहा है।

फूलगोभी में मिलने वाले पोषक तत्व :

स्वास्थ्य के लिए गुणकारी फूलगोभी में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट तथा विटामिन के अलावा कई जरूरी प्रकार के मिनरल भी पाए जाते हैं।

शरीर में बढ़े रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में भी फूल गोभी का महत्वपूर्ण योगदान है।

किसी भी प्रकार की रंगीन फूल गोभी के उत्पादन के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु अनिवार्य होती है। उत्तरी भारत के राज्यों में सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के शुरुआती दिनों से लेकर नवम्बर के पहले सप्ताह में 20 से 25 डिग्री का तापमान रहता है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में यह तापमान वर्ष भर रहता है, इसलिए वहां पर उत्पादन किसी भी समय किया जा सकता है।

रंगीन फूलगोभी की लोकप्रिय और प्रमुख किस्में :

वर्तमान में पीले रंग और बैंगनी रंग की फूलगोभी बाजार में काफी लोकप्रिय है और किसान भाई भी इन्हीं दो किस्मों के उत्पादन पर खासा ध्यान दे रहे हैं।

पीले रंग वाली फूलगोभी को केरोटिना (Karotina) और बैंगनी रंग की संकर किस्म को बेलिटीना (Belitina) नाम से जाना जाता है।

कैसे निर्धारित करें रंगीन फूलगोभी के बीज की मात्रा और रोपण का श्रेष्ठ तरीका ?

सितंबर और अक्टूबर महीने में उगाई जाने वाली रंगीन फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए पहले नर्सरी तैयार करनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के खेत में नर्सरी तैयार करने में लगभग 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है।

कैसे करें नर्सरी में तैयार हुई पौध का रोपण ?

तैयार हुई पौध को 5 से 6 सप्ताह तक बड़ी हो जाने के बाद उन्हें खेत में कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए।

रंगीन फूलगोभी की बुवाई के बाद में सीमित पानी से सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक पानी देने पर पौधे की वृद्धि कम होने की संभावना होती है।

कैसे करें खाद और उर्वरक का बेहतर प्रबंधन ?

जैविक खाद का इस्तेमाल किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीलिए गोबर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है।सीमित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है।

समय रहते मृदा की जांच करवाकर पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करने से उर्वरकों में होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है।

यदि मृदा की जांच नहीं करवाई है तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस के अलावा 30 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर की खाद को पौध की बुवाई से पहले ही जमीन में मिलाकर अच्छी तरह सुखा देना चाहिए।

निरन्तर समय पर मिट्टी में निराई-गुड़ाई कर अमोनियम और बोरोन जैसे रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

कैसे करें खरपतवार का सफलतापूर्वक नियंत्रण ?

एक बार पौध का सफलतापूर्वक रोपण हो जाने के बाद निरंतर समय पर निराई-गुड़ाई कर खरपतवार को खुरपी मदद से हटाया जाना चाहिए।

खरपतवार को हटाने के बाद उस स्थान पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे दुबारा खरपतवार के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके।

रंगीन फूलगोभी में होने वाले प्रमुख रोग एवं उनका इलाज :

कई दूसरे प्रकार के फलों और सब्जियों की तरह ही रंगीन फूलगोभी भी रोगों से ग्रसित हो सकती है, कुछ रोग और उनका इलाज निम्न प्रकार है :-

सरसों की मक्खी :
यह एक प्रकार कीट होते हैं, जो पौधे के बड़े होने के समय फूल गोभी के पत्तों में अंडे देते हैं और बाद में पत्तियों को खाकर सब्जी की उत्पादकता को कम करते हैं।

इस रोग के इलाज के लिए बेसिलस थुरिंगिएनसिस (Bacillus thuringiensis) के घोल का छिड़काव करना चाहिए।
इसके अलावा बाजार में उपलब्ध फेरोमोन ट्रैप (pheromone trap) का इस्तेमाल कर बड़े कीटों को पकड़ा जाना चाहिए।

एफिड रोग :
यह रोग छोटे हल्के रंग के कीटों के द्वारा फैलाया जाता है। यह छोटे कीट, पौधे की पत्तियों और कोमल भागों का रस को निकाल कर अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से गोभी के फूल का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है।
इस रोग के निदान के लिए डाईमेथोएट (Dimethoate) नामक रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए।

काला विगलन रोग :
फूल गोभी और पत्ता गोभी प्रकार की सब्जियों में यह एक प्रमुख रोग होता है, जो कि एक जीवाणु के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग की वजह से पौधे की पत्तियों में हल्के पीले रंग के धब्बे होने लगते हैं और जड़ का अंदरूनी हिस्सा काला दिखाई देता है। सही समय पर इस रोग का इलाज नहीं दिया जाए तो इससे तना कमजोर होकर टूट जाता है और पूरे पौधे का ही नुकसान हो जाता है।

इस रोग के इलाज के लिए कॉपर ऑक्सिक्लोराइड (copper oxychloride) और स्ट्रैप्टो-साइक्लीन (Streptocycline) का पानी के साथ मिलाकर एक घोल तैयार किया जाना चाहिए, जिसका समय-समय पर फसल पर छिड़काव करना चाहिए।

यदि इसके बावजूद भी इस रोग का प्रसार नहीं रुकता है तो, रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर इकट्ठा करके उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए।
इसके अलावा रंगीन फूलगोभी में आर्द्रगलन और डायमंड बैकमॉथ (Diamond-back Moth) जैसे रोग भी होते हैं, इन रोगों का इलाज भी बेहतर बीज उपचार और वैज्ञानिक विधि की मदद से आसानी से किया जा सकता है।

मार्च महीने की शुरुआती दौर में तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो जाने पर इस पौधे से अधिक बीज प्राप्त होते हैं और बेहतर परिपक्वता की वजह से इससे बनने वाली चाय का स्वाद भी बेहतरीन हो जाता है। इसीलिए पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में रहने वाले किसान गुरदीप सिंह बताते हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए मार्च महीने के शुरुआती दिनों में फूलों को तोड़कर बीज को बाजार में बेचते हैं, इससे वह तैयार उत्पाद को चाय बनाने वाली कंपनियों को अधिक दाम पर बेच सकते हैं।

पौधों की सिंचाई के दौरान नमी के स्तर को लगातार बनाए रहना चाहिए, इसके लिए समय-समय पर सीमित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। पूरी फसल को तैयार करने में 8 से 10 सीमित सिंचाइयों की आवश्यकता होती है।

कैसे करें खाद और उर्वरकों का बेहतर प्रबंधन तथा खरपतवार नियंत्रण ?

पौधे की बेहतर वृद्धि के लिए एक बार फूल निकलने पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों की राय में कैमोमाइल की फसल पर फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव बहुत ही कम होता है, इसलिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए।

कैमोमाइल के पौधे शुरुआत में बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं, इसीलिए खरपतवार तेजी से बड़ी हो जाती है और उसके नियंत्रण में समस्या होती है। शुरुआत में खरपतवार को हाथ से ही खुरपी की मदद से समय-समय पर निराई गुड़ाई कर नियंत्रित करना सुविधाजनक रहता है।

वर्तमान में कुछ रासायनिक उर्वरकों जैसे डी-सोडियम साल्ट और ऑक्सीफ्लोरफेन का इस्तेमाल कर भी खरपतवार को नष्ट किया जा रहा है।

कैमोमाइल के पौधे से प्राप्त होने वाली उपज :

भारतीय जलवायु और किसानों के द्वारा किये जाने वाले उर्वरकों के प्रयोग को आधार मानते हुए कृषि वैज्ञानिकों की राय में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 4000 किलोग्राम ताजे फूल इकट्ठे किए जा सकते हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में बदलते तापमान की वजह से अधिक उत्पादन भी प्राप्त हो सकता है।

अप्रैल के पहले सप्ताह में फूलों का वजन भी अधिक प्राप्त होता है और 1000 फूलों में 150 किलोग्राम तक वजन हो जाता है।

वर्तमान में कई बड़े किसान कोल्ड स्टोरेज सुविधा की मदद से कैमोमाइल चाय की अधिक मांग होने के समय ही अपने उत्पाद को बाजार में बेचते हैं, इससे उन्हें अधिक मुनाफा होता है।

वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क जनसंख्या कैमोमाइल चाय का इस्तेमाल एक एंटीऑक्सीडेंट और पाचन क्षमता में सुधार करने के लिए कर रही है। प्रतिदिन कैमोमाइल चाय के सेवन से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम किया जा सकता है।

फूल

कैमोमाइल फसल के फूल उगाकर एलोपैथी विज्ञान में योगदान दे रहे पंजाब और महाराष्ट्र के युवा किसान

प्राचीन सभ्यताओं के दौरान कैमोमाइल (Chamomile) के पौधे का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में जड़ी-बूटी के लिए किया जाता था। यह 'मैट्रीकेरिया कैमोमिला' नामक प्रजाति से संबंध रखने वाला एक पौधा है।

प्राचीन समय में दक्षिणी-पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता था और वर्तमान में यह पौधा जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे देशों में उगाया जाता है। पिछले 10 सालों से पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहने वाले भारतीय युवा किसान भी कैमोमाइल पौधे का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

क्या है कैमोमाइल का पौधा और इसके सेवन से होने वाले फायदे ?

वर्तमान में कैमोमाइल पौधे के गीले फूलों को तोड़कर उनमें से नीले रंग का एक तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल कई एंटीसेप्टिक दवाओं में किया जाता है।

कृषि वैज्ञानिकों की राय में इस पौधे के फूल को सुखाकर इससे एक पाउडर भी बनाया जा रहा है, जिससे एंटी-इन्फ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory) तत्व के रूप में घाव पर लगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा कैमोमाइल के फूलों से 'एल्फा बिसाबोलोल ऑक्साइड' (Alfa Bisabolol oxide) नामक एक रासायनिक पदार्थ भी प्राप्त किया जाता है, जिसे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही चोट वाले निशान पर लगाया जाता है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कैमोमाइल के पौधे से चाय बनाने का काम भी कर रही हैं, इसके लिए पहले फूलों को तोड़ कर कुछ समय तक धूप में सुखाया जाता है और फिर उन्हें गर्म करके पूरी तरीके से उपचारित किया जाता है। हल्के मीठे स्वाद वाली यह चाय, हृदय और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती है।

वर्तमान में एलोपैथी विज्ञान के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भी इस पौधे के फूलों का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है।

कैमोमाइल के उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु एवं मृदा :

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जर्मन कैमोमाइल को सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। इस पौधे के उत्पादन के लिए नमी वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है और तापमान 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए।

भारत में रबी के सीजन में इस पौधे की खेती की जाती है और अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह या नवंबर महीने के पहले पखवाड़े तक इसकी बुवाई की जानी चाहिए।

कैमोमाइल के बीज बोने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां :

इसको पौधे के बीजों को इसके फूलों से प्राप्त किया जाता है।

वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के तटीय इलाकों में इसकी सीधी बुवाई वाली तकनीक को अपनाया जाता है, जिसमे बीज का सीधे खेत में ही रोपण किया जाता है, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नर्सरी विधि के माध्यम से पौधरोपण किया जाता है।

एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आधा किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। किसान भाई ध्यान रखें कि बीजों के अंकुरण के समय अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। वर्तमान में उत्तर भारत में रहने वाले कुछ किसान भाई गर्मियों के मौसम में भी पॉलीहाउस तकनीक की मदद से इस फसल का उत्पादन कर रहे हैं।

भारतीय जलवायु के अनुसार जनवरी महीने की शुरुआत तक पौधे की तेजी से वृद्धि होती है, हालांकि अगले एक महीने तक इसकी वर्द्धि धीमी गति से होती है। बेहतर उर्वरकों के इस्तेमाल से फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में फूल तोड़ कर इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है।

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव

ICAR ने विकसित की नींबू की नई किस्म,तीसरे ही साल लग जाते हैं फल

बागवानी खेती करने वाले किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानि ICAR) एक अच्छी खबर लेकर आया है। पिछले कई सालों से ICAR नींबू (Lemon) की नई किस्में विकसित करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इस संस्थान को अंततः सफलता मिल गई है।

ICAR के कृषि वैज्ञानिकों ने नींबू के फल में एसिड और रस की मात्रा को ध्यान में रखते हुए नींबू की एक नई किस्म विकसित है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म को 'थार वैभव' (Thar Vaibhav) नाम दिया है। थार वैभव नींबू की किस्म को सेंट्रल हॉर्टिकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन (Central Horticultural Experiment Station (ICAR-CIAH)), वेजलपुर, गोधरा, गुजरात में विकसित किया गया है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, इस थार वैभव नींबू की किस्म की कई विशेषताएं हैं-

सिर्फ 3 साल बाद ही आने लगते हैं पेड़ में फल

नींबू की यह किस्म एक तरह की एसिड लाइम किस्म है, इसके पौधे को लगाने के बाद मात्र 3 साल में ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। नींबू के इस पेड़ में बेहद पास-पास फल लगते हैं, जिससे उत्पादन ज्यादा होता है। इसके फल गोलाकार होते हैं, साथ ही आकर्षक पीले और चिकने छिलके वाले होते हैं, एक फल में 6 से 8 बीज होते हैं।

एक पौधे में होगा इतना उत्पादन

यह पेड़ अन्य नींबू के पेड़ों के मुकाबले जल्द ही फल देने लगता है, इसके एक गुच्छे में 3 से 9 नींबू तक लगते हैं। 'थार वैभव' किस्म के नींबू के फल में रस की मात्रा 49 प्रतिशत तक हो सकती है, साथ ही अम्लता 6.84 प्रतिशत तक होती है। नींबू की इस किस्म का एक पेड़ एक मौसम में कम से कम 60 किलो नींबू का उत्पादन कर सकता है।

कृषि वैज्ञानिकों ने इस फल के बारे में बताया है कि ये फल गर्मियों में तैयार हो जाते हैं। इन दिनों भारत में एसिड लाइम के उत्पादक ऐसे फलों की मांग करते हैं, उनकी मांग को देखते हुए बाजार में ऐसे फलों की डिमांड बढ़ सकती है।

कोरोना काल में बढ़ी थी ऐसे नींबू की मांग

देश में जब कोरोना चरम पर था तब डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा Vitamin C के सेवन की सलाह दी थी, क्योंकि Vitamin C लोगों के भीतर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में कारगर होता है, और इसलिए लोगों ने इस दौरान Vitamin C का भरपूर सेवन किया, चाहे वह गोली के रूप में हो या नींबू और संतरे जैसे फलों के रूप में। कोरोना के बाद से लोगों के बीच Vitamin C को लेकर जागरूकता आई है और बाजार में नींबू की खपत बढ़ गई है। ऐसे में यदि किसान इस नई किस्म की खेती करते हैं तो वो 3 साल में ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और 'थार वैभव' नींबू को बेचकर अपनी आमदनी तेजी से बढ़ा सकते हैं।

'थार वैभव' के साथ ही ICAR के वैज्ञानिक नींबू की और भी नई किस्में विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिनमें नींबू का उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में हो और नींबू में रस की मात्रा भी ज्यादा हो, ताकि इस प्रकार की नई किस्म से मार्केट में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। फिलहाल कृषि वैज्ञानिक 'थार वैभव' को लेकर भी विश्लेषण करेंगे कि यह किस्म किसानों के बीच लोकप्रिय हो पाती है या नहीं।

बागवानी की तरफ बढ़ रहा है किसानों का रुझान, जानिये क्यों?

पारंपरिक खेती के बजाय अब किसान बागवानी (horticulture) खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि मौजूदा सरकार की बात करें, तो सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है। देश की केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें बागवानी फसलों को लेकर खाद-बीज, सिंचाई, रखरखाव, कटाई के बाद फसलों के भंडारण पर खास जोर दे रही हैं। सरकारों ने बागवानी फ़सलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने कृषि वैज्ञानिकों को लगा रखा है, जो इस पर बेहद बारीकी से रिसर्च कर रहे हैं तथा नए-नए बीज और संकरित किस्मों का निर्माण कर रहे हैं।

खाद्यान्न फ़सलों की अपेक्षा बागवानी फसलों में हो रही है वृद्धि

सरकार ने फसलों के उत्पादन के आंकड़े जारी किये हैं जिसमें बताया है कि मौसम की अनिश्चितता और बीमारियों के प्रकोप के कारण गेहूं, धान, दलहन, तिलहन जैसी पारंपरिक फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं बागवानी फसलों की बात करें तो फसलों के विविधिकरण, नई तकनीकों, मशीनरी और नए तरीकों का प्रयोग करने से उत्पादन में दिनों दिन वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही, बागवानी फसलों में प्राकृतिक आपदा और बीमारियों के प्रकोप का भी उतना असर नहीं पड़ता जितना खाद्यान्न उत्पादन करने वाली खेती में पड़ता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2021-22 के दौरान पारम्परिक खाद्यान्न फसलों के द्वारा 315,72 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। जबकि बागवानी फसलों के द्वारा साल 2021-22 के दौरान 341.63 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। साल 2021-22 के दौरान बागवानी फसलों के उत्पादन में 2.10% की वृद्धि हुई है, जबकि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में इस दौरान कमी देखी गई है।

बागवानी फसलों से प्रदूषण में लगती है लगाम

आजकल धान-गेहूं जैसी पारंपरिक खाद्यान्न फसलों की खेती करने पर कटाई के बाद भारी मात्रा में अवशेष खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं। ये अवशेष किसानों के किसी काम के नहीं होते, इसलिए खेत को फिर से तैयार करने के लिए उन अवशेषों में आग (stubble burning) लगाई जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में वातावरण में प्रदूषण फैलता है और आम लोगों को उस प्रदूषण से भारी परेशानी होती है। इसके अलावा किसान पारंपरिक खेती में ढेरों रसायनों का उपयोग करते हैं जो मिट्टी के साथ-साथ पानी को भी प्रदूषित करते हैं।

इसके विपरीत बागवानी फसलों की खेती किसान ज्यादातर जैविक विधि द्वारा करते हैं, जिसमें रसायनों की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही बागवानी फसलों की खेती से उत्पन्न कचरा जानवरों को परोस दिया जाता है या जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ने की संभावना नहीं रहती।

बागवानी फसलों में आधुनिक खेती से किसानों की बढ़ी आमदनी

आजकल बागवानी फसलों में किसानों के द्वारा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारतीय किसान फल, फूल, सब्जी और जड़ी-बूटियां उगाने के लिए प्लास्टिक मल्च, लो टनल, ग्रीन हाउस और हाइड्रोपॉनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके इस्तेमाल से उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी हुई है और लागत में भी कमी आई है।

इसके अलावा बागवानी फसलें नकदी फसलें होती है। जो प्रतिदिन आसानी से बिक जातीं है और इनकी वजह से किसानों के पास पैसे का फ्लो बना रहता है। बागवानी फसलों की मदद से किसानों को रोज आमदनी होती है। बागवानी फसलों के फायदों को देखते हुए कई पढ़े लिखे युवा भी अब इस ओर आकर्षित हो रहे हैं।

सही लागत-उत्पादन अनुपात को समझ सब्ज़ी उगाकर कैसे कमाएँ अच्छा मुनाफ़ा, जानें बचत करने की पूरी प्रक्रिया

सही लागत-उत्पादन अनुपात को समझ सब्ज़ी उगाकर कैसे कमाएँ अच्छा मुनाफ़ा, जानें बचत करने की पूरी प्रक्रिया

भारत शुरुआत से ही एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और यहां पर रहने वाली अधिकतर जनसंख्या का कृषि ही एक प्राथमिक आय का स्रोत है। पिछले कुछ सालों से बढ़ती जनसंख्या की वजह से बाजार में कृषि उत्पादों की बढ़ी हुई मांग, अब किसानों को जमीन पर अधिक दबाव डालने के लिए मजबूर कर रही है। इसी वजह से कृषि की उपज कम हो रही है, जिसे और बढ़ाने के लिए किसान लागत में बढ़ोतरी कर रहें है। यह पूरी पूरी चक्रीय प्रक्रिया आने वाले समय में किसानों के लिए और अधिक आर्थिक दबाव उपलब्ध करवा सकती है।
भारत सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर अब कृषि उत्पादों में नए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकों की मदद से लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

धान की तुलना में सब्जी की फसल में, प्रति इकाई क्षेत्र से किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है।

वर्तमान समय में प्रचलित सब्जियों की विभिन्न फसल की अवधि के अनुसार, अलग-अलग किस्मों को अपनाकर आय में वृद्धि की जा सकती है।
मटर की कुछ प्रचलित किस्म जैसा की काशी उदय और काशी नंदिनी भी किसानों की आय को बढ़ाने में सक्षम साबित हो रही है।

सब्जियों के उत्पादन का एक और फायदा यह है कि इनमें धान और दलहनी फसलों की तुलना में खरपतवार और कीट जैसी समस्याएं कम देखने को मिलती है।
सब्जियों की नर्सरी को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और जलवायुवीय परिवर्तनों के बावजूद अच्छा उत्पादन किया जा सकता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) के अनुसार भारत की जमीन में उगने वाली सब्जियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें धीमी वृद्धि वाली सब्जी की फसल और तेज वृद्धि वाली सब्जियों को शामिल किया जाता है।

धीमी वृद्धि वाली फसल जैसे कि बैंगन और मिर्च बेहतर खरपतवार नियंत्रण के बाद अच्छा उत्पादन दे सकती है, वहीं तेजी से बढ़ने वाली सब्जी जैसे भिंडी और गोभी वर्ग की सब्जियां बहुत ही कम समय में बेहतर उत्पादन के साथ ही अच्छा मुनाफा प्रदान कर सकती है।

कैसे करें खरपतवार का बेहतर नियंत्रण ?

सभी प्रकार की सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण एक मुख्य समस्या के रूप में देखने को मिलता है। अलग-अलग सब्जियों की बुवाई के 20 से 50 दिनों के मध्य खरपतवार का नियंत्रण करना अनिवार्य होता है।
इसके लिए पलवार लगाकर और कुछ खरपतवार-नासी रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कर समय-समय पर निराई गुड़ाई कर नियंत्रण किया जाना संभव है।
जैविक खाद का इस्तेमाल, उत्पादन में होने वाली लागत को कम करने के अलावा फसल की वृद्धि दर को भी तेज कर देता है।

कैसे करें बेहतर किस्मों का चुनाव ?

किसी भी सब्जी के लिए बेहतर किस्म के बीज का चुनाव करने के दौरान किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि बीज पूरी तरीके से उपचारित किया हुआ हो या फिर अपने खेत में बोने से पहले बेहतर बीज उपचार करके ही इस्तेमाल करें।

इसके अलावा किस्म का विपणन अच्छे मूल्य पर किया जाना चाहिए, वर्तमान में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बीज निर्माता कंपनियां अपने द्वारा तैयार किए गए बीज की संपूर्ण जानकारी पैकेट पर उपलब्ध करवाती है। उस पैकेट को पढ़कर भी किसान भाई पता लगा सकते हैं कि यह बीज कौन से रोगों के प्रति सहनशील है और इसके बीज उपचार के दौरान कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

इसके अलावा बाजार में बिकने वाले बीज के साथ ही प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में होने वाले अनुमानित उत्पादकता की जानकारी भी दी जाती है, इस जानकारी से किसान भाई अपने खेत से होने वाली उत्पादकता का पूर्व अंदाजा लगा सकते हैं।

ऐसे ही कुछ बेहतर बीजों की किस्मों में लोबिया सब्जी की किस्में काशी चंदन को शामिल किया जाता है, मटर की किस्म काशी नंदिनी और उदय के अलावा भिंडी की किस्म का काशी चमन कम समय में ही अधिक उत्पादकता उपलब्ध करवाती है।

कैसे निर्धारित करें बीज की बुवाई या नर्सरी में तैयार पौध रोपण का सही समय ?

किसान भाइयों को सब्जी उत्पादन में आने वाली लागत को कम करने के लिए बीज की बुवाई का सही समय चुनना अनिवार्य हो जाता है।

समय पर बीज की बुवाई करने से कई प्रकार के रोग और कीटों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और फसल की वर्द्धि भी सही तरीके से हो जाती है, जिससे जमीन में उपलब्ध पोषक तत्वों का इस्तेमाल फसल के द्वारा ही कर लिया जाता है और खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो जाता है।

कृषि वैज्ञानिकों की राय में मटर की बुवाई नवंबर के शुरुआती सप्ताह में की जानी चाहिए, मिर्च और बैंगन जुलाई के पहले सप्ताह में और टमाटर सितंबर के पहले सप्ताह में बोये जाने चाहिए।

कैसे करें बीज का बेहतर उपचार ?

खेत में अंतिम जुताई से पहले बीज का बेहतर उपचार करना अनिवार्य है, वर्तमान में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि थायो-मेथोक्जम ड्रेसिंग पाउडर से बीज का उपचार करने पर उसमें कीटों का प्रभाव कम होता है और अगले 1 से 2 महीने तक बीज को सुरक्षित रखा जा सकता है।

कैसे करें सब्जी उत्पादन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल ?

वर्तमान में कई वैज्ञानिक अध्ययनों से नई प्रकार की तकनीक सामने आई है, जो कि निम्न प्रकार है :-

ट्रैप फसलों (Trap crop) का इस्तेमाल करना :
इन फसलों को 'प्रपंच फसलों' के नाम से भी जाना जाता है।

मुख्यतः इनका इस्तेमाल सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाने के लिए किया जाता है।

पिछले 10 वर्षों से कृषि क्षेत्र में सक्रिय कृषि वैज्ञानिक 'नीरज सिंह' के अनुसार यदि कोई किसान गोभी की सब्जी उगाना चाहता है, तो गोभी की 25 से 30 पंक्तियों के बाद, अगली दो से तीन पंक्तियों में सरसों का रोपण कर देना चाहिए, जिससे उस समय गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले डायमंडबैक मॉथ और माहूँ जैसे कीट सरसों पर आकर्षित हो जाते हैं, इससे गोभी की फसल को इन कीटों के आक्रमण से बचाया जा सकता है।

इसके अलावा टमाटर की फसल के दौरान गेंदे की फसल का इस्तेमाल भी ट्रैप फसल के रूप में किया जा सकता है।

फेरोमोन ट्रैप (pheromone trap) का इस्तेमाल :
इसका इस्तेमाल मुख्यतः सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को पकड़ने में किया जाता है।

गोभी और कद्दू की फसलों में लगने वाला कीट 'फल मक्खी' को फेरोमोन ट्रैप की मदद से आसानी से पकड़ा जा सकता है।

इसके अलावा फल छेदक और कई प्रकार के कैटरपिलर के लार्वा को पकड़ने में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाल ही में बेंगुलुरू की कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक स्टार्टअप कम्पनी के द्वारा तैयार की गई चिपकने वाली स्टिकी ट्रैप (या insect glue trap) को भी बाजार में बेचा जा रहा है, जो आने वाले समय में किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

सोयाबीन की तीन नई किस्मों को मध्य प्रदेश शासन ने दी मंजूरी

भारत में सोयाबीन (soyabean) का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है इसलिए इस राज्य को सोया राज्य कहा जाता है, चूंकि मध्य प्रदेश के किसान हर साल बड़ी माला में सोयाबीन की खेती करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन मिलकर इसके रिसर्च और अनुसंधान पर भी पूरा ध्यान देते हैं, ताकि समय-समय पर किसानों को नए बीज उपलब्ध करवाए जा सकें, जिससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तथा किसानों को भी फायदा हो।

भारत में खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, ICAR – भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (IISR), इंदौर पिछले कई सालों से सोयाबीन की नई किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। इस संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों के सतत प्रयासों के बाद भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (IISR), इंदौर ने सोयाबीन की 3 नई किस्मों को विकसित करने में सफलता पाई है। इन किस्मों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एनआरसी 157, एनआरसी 131 और एनआरसी 136 नाम दिया गया है।

कृषि वैज्ञानिकों के काम से खुश होकर मध्य प्रदेश शासन ने इन तीनों किस्मों को तुरंत ही मंजूरी दे दी है, ताकि ये किस्में जल्द से जल्द बाजार में किसानों के लिए उपलब्ध हो सकें, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा नई किस्मों के द्वारा लाभान्वित हो सकें।

संस्थान के हेड साइंटिस्ट और ब्रीडर डॉ संजय गुप्ता ने सोयाबीन की नई किस्मों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एनआरसी 157 एक मध्यम अवधि की फसल है, जो बुवाई करने के बाद माल 94 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म की उपज भी शानदार है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 16.5 क्विंटल फसल का उत्पादन दे सकती है। एनआरसी 157 नाम की यह किस्म अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल पस्ट्यूल और टारगेट लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों से मध्यम प्रतिरोधी क्षमता रखती है। इसकी खेती करने वाले किसानों को ज्यादा हानि होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही यदि इस किस्म की बुवाई 20 जुलाई तक भी की जाती है, तो भी यह इस किस्म के लिए उपयुक्त मानी जाएगी।

दूसरी किस्म एनआरसी 131 भी एक मध्यम अवधि की फसल है, जो बुवाई करने के बाद 93 दिनों में तैयार हो जाती है। यह औसत रूप से एक हेक्टेयर में 15 क्विंटल फसल का उत्पादन दे सकती है। यह किस्म भी चारकोल रॉट और टार्गेट लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों के लिए मध्यम रूप से प्रतिरोधी है।

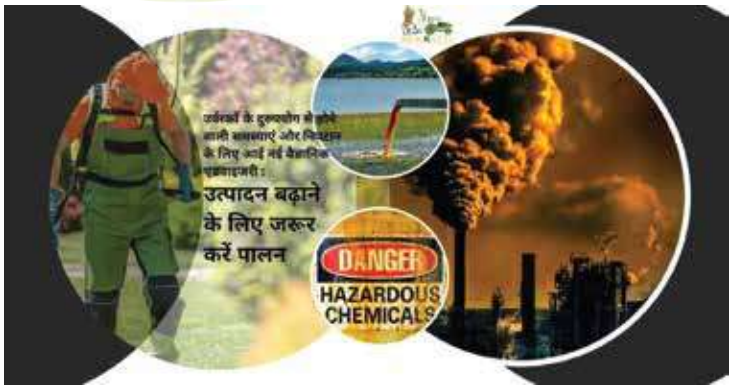

उर्वरकों के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं और निपटान के लिए आई नई वैज्ञानिक एडवाइजरी : उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूर करें पालन

हरित क्रांति के बाद से भारत के खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, हालांकि उर्वरकों के बढ़े हुए इस्तेमाल की वजह से प्रति व्यक्ति उत्पादकता में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन इससे हमारी मृदा पर नकारात्मक असर देखने को मिला है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 (Economic survey 2021-22) के अनुसार वर्तमान में पूरे विश्व भर में प्रतिवर्ष 16 हज़ार टन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं यदि बात करें प्रति हेक्टेयर उर्वरक इस्तेमाल की, तो यह लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

अनाज और दलहनी फसलों के उत्पादन में उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल अथार्त दुरुपयोग होने की वजह से धीरे-धीरे प्रति किलोग्राम उर्वरक की मदद से होने वाली उत्पादकता में भी कमी दिखाई दे रही है।

रसायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं :

बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य मांग की पूर्ति के लिए रसायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल तो अब अनिवार्य हो गया है, हालांकि बेहतर समुचित विकास के लिए पर्यावरण का सहयोग प्राप्त किए बिना, भविष्य में इस मांग की आपूर्ति करना नामुमकिन हो सकता है।

वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से निम्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है :

पानी का प्रदूषण (Water Eutrophication) :

वर्तमान में भारतीय किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रासायनिक उर्वरक, पानी की गुणवत्ता को खराब करने में सर्वाधिक भूमिका निभा रहे हैं।

बारिश के मौसम के दौरान उर्वरक का इस्तेमाल किए हुए खेत के ऊपर से गुजरा हुआ पानी, जब किसी जगह पर इकट्ठा होता है तो वह अपने साथ उर्वरकों के दूषित पदार्थों को भी बहाकर ले जाता है, जो कि उस पानी को पूरी तरीके से अनुपयोगी बना देते हैं। इस प्रकार का पानी पूरे जलीय चक्र को प्रभावित कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यदि किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपने खेत में पड़े हुए पानी को, उर्वरकों के तुरंत इस्तेमाल के बाद बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपके आसपास में स्थित पानी के स्रोत दूषित हो सकते हैं, जो भविष्य में सम्पूर्ण परिस्थिति की तंत्र को बिगाड़ सकते हैं।

हरितगृह गैस का बढ़ता प्रभाव (Greenhouse Gas Emission) :

वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ रासायनिक उर्वरक जैसे कि डीएपी (DAP) और यूरिया तथा पोटाश के लिए विदेश से आयात किए जा रहे कुछ उर्वरकों में ऐसे पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जो खेत से निकलने वाली हरित गृह गैस 'मीथेन' की मात्रा को बढ़ा देते हैं।

यह मीथेन पृथ्वी से भूतापीय ऊर्जा को वापस लेकर जाने वाली किरणों को पर्यावरण में रोक देती है, जिससे धीरे-धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसी बढ़ते तापमान की वजह से कम बारिश और सूखे के अलावा कई स्थानों पर बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि अंततः किसान भाइयों के लिए ही खतरनाक साबित होती है।

इस हरित ग्रह प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को ऐसी फसलों का उत्पादन नहीं करना चाहिए जो ज्यादा मिथेन गैस निकालती हो।

संयुक्त राष्ट्र संस्थान से जुड़ी खाद्य एवं कृषि संस्थान (Food and Agriculture Organisation) की एक रिपोर्ट के अनुसार पोटाश और मैग्नेशियम की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उर्वरकों का बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए, इससे हरित गृह प्रभाव को कम करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही सीमित प्रयोग से उत्पादकता की अच्छी प्राप्त होगी।

मृदा में बढ़ती हुई अम्लता (Soil acidification) :

अम्लीय उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भारतीय मृदा की अम्लता में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि किसी भी पौधे की वृद्धि दर को धीरे कर सकती हैं। अम्लता बढ़ने से मृदा में पाए जाने वाले छोटे-छोटे जीव पाचन की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। पोषक तत्वों की कमी की वजह से उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल के बावजूद भी पौधे की लंबाई और अनुमानित उत्पादकता वास्तविकता में कम प्राप्त होती है।

कृषि वैज्ञानिकों की राय में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जोकि मृदा के स्तर को पहले जैसा बनाने में सहायक साबित होते है। इसके लिए किसान भाई पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केंचुआ से प्राप्त खाद को भी उर्वरक के रूप में खेत में डाल सकते हैं।

मृदा अपरदन (Soil degradation / Soil erosion) :

मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से कमी आने को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। वास्तविकता में मृदा अपरदन में, मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थों में आई कमी के साथ ही, उर्वरता में आई कमी के अलावा लवणता बढ़ने जैसी समस्याओं को शामिल किया जाता है।

अधिक उत्पादन और ज्यादा मुनाफे के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी के अधिक इस्तेमाल और रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग की वजह से मृदा पर बढ़ता दबाव किसानों के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है।

उत्पादकता को पुनः स्थापित करने के लिए कृषि वैज्ञानिक प्रयासरत हैं, इसी राह पर चलते हुए अब पूसा के वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों से अलग अधिक उत्पादकता देने वाले जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी कर दिए है। खेतों की घटती उत्पादकता आने वाले समय में भारी खाद्य संकट भी पैदा कर सकती है।

किसानों पर बढ़ता आर्थिक दबाव (Monetary Pressure) :

उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल के लिए किसानों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा आर्थिक दबाव पैदा कर रही है। यदि किसी एक किसान ने अपने खेत में ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल किया और उस वर्ष उसके खेत से अधिक उत्पादकता प्राप्त हुई, तो उसी को देख कर दूसरे किसान भी अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। इससे मृदा पर बढ़ता दबाव और किसानों की जेब पर आया अतिरिक्त आर्थिक बोझ, उन्हें आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं की तरफ ले जा रहा है।

ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार किसानों के बीच उर्वरकों के समोचित इस्तेमाल के लिए जागरूकता फैलाने के अलावा, कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के द्वारा समय-समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले उर्वरकों की जानकारी भी उपलब्ध करवा रही है।

उर्वरकों के बढ़ते प्रभाव से होने वाली समस्याओं का समाधान :

यदि आप भी अपने आर्थिक बोझ को कम करने के लिए प्रयासरत हैं तो नीचे बताए गए कुछ समाधान को अपनाकर फायदा उठा सकते हैं :-

पता लगाएं मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की सही मात्रा :

भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की मृदा में पाई जाती है और प्रत्येक मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।

यदि किसी मृदा में पहले से ही नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है तो, उस मृदा में डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरक का इस्तेमाल कोई सकारात्मक उत्पादकता नहीं देगा बल्कि आपके लिए नुकसान ही करेगा।

अपने खेत में पाई जाने वाली मृदा को पास में ही स्थित किसी कृषि सेवा केंद्र में जाकर 'सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम' (Soil Health card scheme) के जरिए उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड में खेत की मृदा में पाए जाने वाले 12 मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारियां उपलब्ध करवाई। सोयल हेल्थ कार्ड से प्राप्त रिपोर्ट की मदद से अपने खेत में केवल उसी पोषक तत्व से जुड़े उर्वरक का इस्तेमाल करें, जिसकी कमी पाई गई है।

कैसे करें उर्वरकों का सही इस्तेमाल और प्रबंधन ?

उर्वरकों के सही प्रबंधन में हम कुछ आधार निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए उर्वरक का इस्तेमाल अलग-अलग हो सकता है , इसलिए किसी भी फसल को उगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और केवल सही समय पर ही उर्वरक का छिड़काव करें, जिससे बेहतर उत्पादकता के साथ ही पौधे की वृद्धि दर अधिक प्राप्त होगी।

इसके अलावा उर्वरक की सही मात्रा का इस्तेमाल भी फर्टिलाइजर के बेहतर प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है, यदि किसी फसल को कम उर्वरक की आवश्यकता है तो उसमें केवल सीमित मात्रा में ही छिड़काव करें, पौधे की वृद्धि दर सुचारू रूप से होने पर उर्वरक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करने से पहले किसान भाइयों को यह जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए कि वह उर्वरक किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है और इस कंपनी के उत्पादों के साथ किसानों का पूर्व अनुभव कैसा रहा है, इससे आपको सही ब्रांड से उत्पाद खरीदने का अंदाजा लग जाएगा।

यदि आप अपने खेत से एक से अधिक जगह से मृदा के सैंपल ले जाकर जांच करवाते हैं तो अलग-अलग सैंपल में प्राप्त हुई पोषक तत्वों की अलग-अलग मात्रा को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की छिड़काव की मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है।

भारत में पहली बार जैविक कपास की किस्में हुई विकसित, किसानों को कपास के बीजों की कमी से मिलेगा छुटकारा

भारत कपास (cotton) के उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 53,34,000 मीट्रिक टन कपास का उत्पादन होता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार कपास का निर्यात भी करती है। भारत कपास के निर्यात के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान रखता है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बहुत हद तक भारतीय कपास के ऊपर निर्भर है। भारत में कपास का उत्पादन ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किया जाता है।

भारत सरकार कपास के उत्पादन में लगातार वृद्धि करने को लेकर प्रयासरत रहती है, ताकि सरकार ज्यादा से ज्यादा कपास का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके, जिससे भारत का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संतुलन बना रहे। लेकिन बहुत सालों से देखा जा रहा है कि भारत में कपास के अच्छे बीजों को लेकर किसानों के बीच संकट बना रहता है, इसलिए भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए साल 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था। इस मिशन के अंतर्गत एक लक्ष्य यह भी है कि किसानों की सहायता के लिए कपास अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा तथा कपास के नए बीजों का निर्माण किया जाएगा, ताकि किसान कपास की उन्नत खेती कर सकें। इस योजना को कृषि एवं कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है।

साल दर साल इस मिशन के अंतर्गत भारत ने कपास के अनुसंधान में काफी प्रगति की है और ब्रीडिंग प्रोग्राम के परिणामस्वरूप कई नई किस्में विकसित की हैं, जो किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हुईं हैं। अब कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने दस साल से अधिक के ब्रीडिंग प्रोग्राम के परिणामस्वरूप पहली बार कपास की दो जैविक किस्में विकसित की हैं।

वैज्ञानिकों द्वारा इन किस्मों का नाम आरवीजेके-एसजीएफ-1 (RVJK-SGF-1), आरवीजेके-एसजीएफ-2 (RVJK-SGF-2) बताया जा रहा है, जिन्हें हाल ही में किसानों को उपलब्ध करवाया गया है। यह कपास की पहली किस्में हैं जिन्हें पहली बार पूरी तरह से जैविक माध्यम से विकसित किया गया है और इनके पोषण के लिए भी पूरी तरह से जैविक परिस्थितियां उपलब्ध करवाई गई हैं। इन किस्मों को वैज्ञानिकों ने विशेष प्रजनन कार्यक्रम के तहत विकसित किया है, जिसमें FIBL स्विट्जरलैंड और अन्य लोगों का विशेष योगदान शामिल है।

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय बाजारों में इन दिनों निजी कंपनियों के आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीज उपलब्ध हैं, और किसान इन बीजों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। ये आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्में अन्य किस्मों की शुद्धता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। अभी तक देश में पारंपरिक, गैर-जीएम बीज पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुए हैं। साथ ही ये पारम्परिक बीज किसानों की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करते हैं। यह एक बड़ी चुनौती है।

इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने कपास के बीजों की इन दो नई किस्मों को विकसित किया है। फिलहाल इन बीजों को आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश की राज्य बीज उप समिति द्वारा बाजार में किसानों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। मध्य प्रदेश फ़िलहाल देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास उगाने वाला राज्य है। कपास की जारी की गई ये दोनों जैविक किस्में उच्च गुणवत्ता युक्त हैं और औद्योगिक फाइबर गुणवत्ता की जरूरतों को पूरा करती हैं। इन बीजों के उत्पादन क्षमता भी सामान्य बीजों से ज्यादा है। यह सब देखते हुए राज्य बीज उप समिति ने इसी महीने इन दोनों किस्मों को स्वीकृति दी है।

कपास की नई जैविक किस्मों की विशेषताएं

जैविक कपास किस्म RVJK-SGF-1 में सामान्य कपास के मुकाबले 21.05 प्रतिशत ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता है। इस किस्म के बीजों की फसल बुवाई के मात्र 144-160 दिनों बाद तैयार हो जाती है। अगर इस किस्म के फाइबर के लम्बाई की बात करें तो वो 28.77 मिमी के आस पास होती है, जबकि उच्च फाइबर शक्ति लगभग 27.12 ग्राम/टेक्स होती है।

जैविक कपास किस्म RVJK-SGF-2 अन्य कपास की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता युक्त कपड़ा बनाने के लिए शानदार होती है। इसे कताई के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। सामान्य फसल के मुकाबले 21.18% ज्यादा उत्पादन होता है। बुवाई के बाद इसके पौधे की लम्बाई लगभग 96-110 सेमी के आसपास होती है। इसके साथ ही यह फसल 145-155 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म के फाइबर की लम्बाई 29.87 मिमी और एक उच्च फाइबर शक्ति 29.92 ग्राम/टेक्स होती है।

अब एक ही पौधे पर लगेंगी दो तरह की सब्जियां, पढ़िए पूरी खबर

जी हां, अब एक ही पौधे पर दो तरह की सब्जियां लगेंगी, वैज्ञानिकों ने इस तकनीकी को खोज निकाला है। यूपी के वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान (आईआईवीआर) के वैज्ञानिकों ने सब्जियों के लिए एक नई तकनीकी से ऐसी पौध का अविष्कार किया है, जो एक ही पौधे पर दो तरह की सब्जी उगाएगा।
घर की रसोई का शौक बढ़ाने वाला वैज्ञानिकों का यह प्रयोग लोगों को काफी उत्साहित करने वाला है। दावा है कि इस पौधे को घर की बालकनी, घर की छतों पर , बगीचों आदि स्थानों पर लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस नई तकनीकी से ऐसे पौधे विकसित किए हैं, जिसमें टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्च, खीरा, लोकी, तोरई व करेला उगाए जा सकेंगे। एक पौधे पर दो तरह की अलग-अलग सब्जियां उगाई जा सकती हैं।

पांच साल से चल रहा थी खोज

एक ही पौधे पर कई प्रकार की सब्जियां उगाने के लिए वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान केन्द्र में पिछले पांच वर्षों से शौध चल रहा था। फिलहाल वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे पर ग्राफ्टिंग के जरिए दो तरह की सब्जियां उगाने वाली पौध का अविष्कार कर लिया है। अभी भी खोज जारी है।

भारतीय सब्जी अनुसंधान केन्द्र वाराणसी में ग्राफ्टिंग तकनीकी से तैयार किए गए पौधों को अलग नाम से जाना जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नई पौध को ब्रिमेटो (Brimato) और पोमैटो (Pomato) नाम से जाना जाएगा, जो काफी चर्चा बटोर रहे हैं।

किचन गार्डन या गमले में तैयार करें पौध
भारतीय सब्जी अनुसंधान केन्द्र वाराणसी के वैज्ञानिक डॉ. अंनत कुमार के अनुसार ग्राफ्टिंग तकनीकी से तैयार हुई इस पौध को किचन गार्डन या गमले में सही तरह तैयार करें। हर एक पोमैटो से 2 किग्रा टमाटर और 600 ग्राम आलू तैयार किया जा सकता है। एक ही पौधे पर मिट्टी के ऊपर टमाटर तो वहीं मिट्टी के निचले हिस्से में आलू तैयार होगा।

आलू के पौधे के मिट्टी के ऊपर कम से कम 6-7 इंच लंबा होने पर उसके ऊपर टमाटर के पौधे की ग्राफ्टिंग की जाएगी। ध्यान रहे दोनों ही पौधों के तने की मोटाई बराबर होनी चाहिए। करीब 20 दिन बाद दोनों के तने जुड़ जाएं तो उसे खेत में छोड़ दें। रोपाई के दो महीने बाद ही टमाटर की तोड़ाई शुरू हो जाएगी और बाद में आलू की खुदाई करें।

MERIKHETI

Mahindra 275DI TU XP PLUS

28.7 kW (39 HP)

FIRST TIME IN INDUSTRY

6 YEARS WARRANTY

*CONDITIONS APPLY

आकर्षक ऑफर्स के लिए क्लिक करें

MERI KHETI

MASSEY FERGUSON

7235DI

35 HP

आकर्षक ऑफर्स के लिए क्लिक करें

सरकारी नीतियां

66 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी यह राज्य सरकार, मिलेगी हर प्रकार की सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हितो में कार्य कर रही है, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार 66 लाख नए किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' (Kisan Credit Card) मुहैया करवाने जा रही है, ताकि किसान भाई आसानी से सरकार द्वारा दिए जा रहे कृषि सम्बंधित लाभों का उपयोग कर पाएं। फिलहाल अभी तक प्रदेश में 94 लाख से ज्यादा कृषकों के पास 'किसान क्रेडिट कार्ड' है। अब निश्चित तौर पर 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारक कृषकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने वाली है।

'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से सरकार कृषकों को बेहद सस्ती दरों पर अल्पकालिक लोन की सुविधा मुहैया करवाती है। जबकि इसके विपरीत बाजार में निजी संस्थाएं भी कृषि के लिए लोन मुहैया करवाती हैं जिनमें ब्याज की दर ऊंची रहती है, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस सकते हैं।

'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से खेती की तैयार के लिए मिलेगी सुविधा

'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से सरकार किसानों को खेती की तैयारी के लिए लोन उपलब्ध करवाती है। इनमें कृषि उपकरणों की खरीदारी से लेकर अन्य तरह की सुविधाओं के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। कृषि उपकरणों की खरीदारी के लिए किसान भाई 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कई बार सरकार कृषि उपकरणों की खरीदारी पर सिर्फ उन्हीं किसानों को सब्सिडी देती है जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड होता है।

'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से किसानों को खाद, बीज और उर्वरक की भी मिलेगी सुविधा

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खाद बीज के साथ ही उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए भी सरकार लोन उपलब्ध करवाती है। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि बुंदेलखंड के कई जिलों में दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार 'किसान क्रेडिट कार्ड' बनाने के लिए बुन्देलखंड के किसानों पर विशेष फोकस करने वाली है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और किसान भाई आसानी से अपनी जरुरत के मुताबिक़ खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें व जिससे किसानों की फसलों को किसी भी प्रकार के पोषण की कमी महसूस न हो। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि रबी के सीजन में किसानों को डीएम-सीडीओ की ओर से भी बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि संयंत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इस साल प्रदेश में गेहूं का रकबा कम हो गया है, जिसके कारण बाजार में गेहूं की कमी महसूस की गई है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार किसानों को गेहूं के रकबे में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से लोन लेकर किसान भाई गेहूं की अच्छी अच्छी किस्मों के बीज खरीद सकते हैं ताकि उनके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके। इसके अलावा हाथ में पैसे होने के कारण गेहूं की खेती और सिंचाई में लगने वाले अन्य सामानों को भी किसान भाई आसानी से खरीद सकते हैं।

अगर बरसात के कारण फसल हो गई है चौपट, तो ऐसे करें अपना बीमा क्लेम

बदलते हुए मौसम के कारण आजकल मानसूनी गतिविधियों में तेजी से बदलाव आ रहा है, अब कहीं जरुरत से ज्यादा बरसात हो रही है तो कहीं सूखे का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस दौरान बहुत सारे किसानों की कई एकड़ फसलें पानी में डूब गईं, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

किसानों को होने वाले नुकसानों को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसल का मामूली प्रीमियम भरकर बीमा करवा सकते हैं। अगर उनकी फसल किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाये या पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो किसान संबंधित बीमा कम्पनी से अपनी फसल के बीमा का क्लेम भी मांग सकते हैं, जिसके बाद संबंधित बीमा कंपनी किसान को हुए नुकसान की भरपाई करेगी।

क्या है कृषि बीमा करवाने की प्रक्रिया

कृषि बीमा करवाना बेहद आसान है। इसके लिए किसानों को किसी भी बैंक या बीमा कंपनी के बार-बार चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। यदि किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है या किसी किसान ने बैंक से पहले से ही लोन ले रखा है, तो उनके लिए यह प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो जाती है। बीमा करवाने के लिए किसान को बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद फॉर्म के साथ आधार कार्ड, जमीन से संबंधित कागजात और वोटर आईडी की फोटो कॉपी लगानी होगी, इसके साथ ही पटवारी द्वारा जारी खेत में बोई गई फसल का ब्यौरा भी जमा करना होगा। यह सब बैंक में या बीमा कम्पनी में जमा करने के बाद किसान का बीमा बेहद आसानी से हो जाएगा।

कैसे क्लेम करें कृषि बीमा की राशि ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषि बीमा दो प्रकार से क्लेम किया जा सकता है, पहले में यदि फसल पूरी तरह से खराब हो जाये या नष्ट हो जाये तो किसान फसल बीमा का क्लेम कर सकता है। और दूसरे में यदि किसान की फसल आंशिक रूप से खराब हो जाये या कम माला में खराब हो तो भी किसान फसल बीमा का क्लेम कर सकता है।

यदि फसल किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है, जैसे – बाढ़, भीषण बरसात, ओले गिरना इत्यादि तो किसान को यह क्लेम लेने के लिए संबंधित बैंक या बीमा कंपनी में आवेदन करना पड़ता है। इसके साथ ही किसान को 72 घंटों के भीतर प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हुई फसल की जानकारी कृषि विभाग को देना अनिवार्य होता है। इस जानकारी में बीमा की फोटो कॉपी के साथ ही फसल का पूरा ब्योरा फॉर्म में भरना पड़ता है।

वहीं यदि किसान की फसल आंशिक रूप से खराब हुई तो किसान को इसकी जानकारी कहीं देने की जरुरत नहीं है। बीमा कम्पनी या बैंक से सिर्फ क्लेम करने पर, सम्बंधित बैंक या बीमा कम्पनी नुकसान की राशि किसान के बैंक खाते में जमा कर देती हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सभी फसलों के नष्ट होने पर अलग-अलग बीमा राशि सम्बंधित बैंक या बीमा कम्पनी के द्वारा किसानों को दी जाती है। उदाहरण के लिए – यदि किसान की कपास की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तो किसान को 36,282 रुपये प्रति एकड़ की दर से बीमा राशि मिलेगी। वहीं अगर किसान ने अपने खेत में धान बोया है और धान की खेती प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गई है, तो किसान को 37,484 रुपये प्रति एकड़ की दर से बीमा राशि मिलेगी। इसी तरह से बाजरा, मक्का और मूंग की फसल के लिए क्रमशः 17,639 रुपये, 18,742 रुपये और 16,497 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

कृषि लोन लेने के लिए किसानों को नहीं होगी ज्यादा दिक्कत, रबी की फसल होगी जबरदस्त

कृषि योजनाओं के तहत किसानों को सस्ती दर पर कृषि सम्बंधित कर्ज मिलेगा, किसान लोन योजनाओं के माध्यम से सहजता से कर्ज ले सकते हैं। मूसलाधार बारिश के चलते किसानों के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता की बेहद आवश्यकता है। आकस्मिक आपदा की वजह से किसानों की फसल चौपट हो गयी है, उनको अब कोई भी आय का स्त्रोत नजर नहीं आ रहा है।

किसानों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है, पूर्णतया किसान सरकार के भरोसे ही बैठे हैं। इसमें कृषि लोन योजनायें किसानों की भरपूर मदद करेगी, जिससे किसानों को रबी की फसल उगाने के लिए आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ निजी संस्थाए भी किसानों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड क्या है

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) किसानों के लिए आर्थिक सहायता काफी कम दर पर देने का माध्यम है, जिसको भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बेहद हितेषी साबित होता है, जिसके अंतर्गत किसानों को १ लाख ६० हजार रुपये तक की राशि, न्यूनतम दर पर बिना किसी गारंटी के किसानों को प्रदान की जाती थी। भारत सरकार द्वारा किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की मर्यादा ३ लाख रूपए तक कर दी गयी है, ३ लाख तक के अल्पकालिक कर्ज पर १.५ प्रतिशत प्रति वर्ष छूट देने का ऐलान किया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड के अन्य भी कई लाभ हैं, जैसे कि फसलों का बीमा ,पशुपालन एवं मछली पालन आदि के लिए भी न्यूनतम दर पर कर्ज लेने में सहायक होता है।

कृषि स्वर्ण लोन एवं एस बी आई कृषक उत्थान योजना में अंतर

कृषि स्वर्ण लोन योजना तथा एस बी आई कृषक उत्थान योजना (SBI Krishak Uthan Yojna) दोनों ही किसानों के लिए लोन देकर उनकी समस्याओं को दूर करने में काफी सहायक होती हैं। कृषि स्वर्ण योजना किसानों को ५० लाख तक की सहायता प्रदान करती है, जबकि एस बी आई २० हजार व्यय पर १ लाख तक की सहायता किसानों को उपलब्ध कराती है। दोनों योजनाओं का मकसद किसान की खुशहाली है। किसानों को उनकी फसल को तैयार करने के लिए किसी भी आर्थिक तंगी से न गुजरना पड़े, इसलिए ये योजनायें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्ज प्रदान करती हैं।

भूमि खरीदी योजना क्या है ?

भूमि खरीदी योजना के तहत आर्थिक रूप से असमर्थ किसानों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया व अन्य सरकारी बैंकों से लोन प्रदान किया जाता है। भूमि की वास्तविक कीमत और उसकी सटीक जानकारी बैंक प्रबंधक को देने के उपरांत, भूमि की कीमत की ८५ प्रतिशत धनराशि बैंक द्वारा कर्ज के रूप में प्रदान करदी जायेगी। किसान भूमि खरीदकर, उसमें फसल उगा अपनी आय का स्त्रोत उत्पन्न कर सकते हैं और लोन की धन राशि को समयानुसार अदा भी कर सकते हैं।

कृषि सम्बधित उद्योगों के लिए कितना लोन मिल सकता है

किसानों की आर्थिक स्तिथि को सुधारने के लिए एवं पूर्णतया कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिए, नाबार्ड किसानों को २० लाख रूपये तक का व्यक्तिगत कर्ज उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए किसानों को १ करोड़ तक का लोन प्रदान किया जाता है। कृषि उपचार केंद्र एवं कृषि सम्बंधित औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से किसानों की आजीविका के लिए नवीन अवसर उपलब्ध होंगे, जिनकी सहायता से किसानों की अर्थव्यवस्था एवं जीवन शैली बेहतर पथ की और अग्रसर होगी।

स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है सरकार

खरीफ फसलों के समय के गुजरने के बाद रबी फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है, खरीफ की फसलों की अपेक्षा में रबी फसलों को जल की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए सरकार किसानो को स्प्रिंकल सिंचाई (Irrigation sprinkler यानि सिंचाई छिड़काव या बौछारी सिंचाई या फव्वारा सिंचाई) के लिए प्रोत्साहन दे रही है। स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से किसान अपनी फसल में कम जल खर्च करके अधिक पैदावार कर सकते हैं।

जल के अतिदोहन को रोकने एवं फसलों में बेहतर रूप से सिंचाई करने के लिए सरकार किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए ९० प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है। भारत में आज भी ज्यादातर किसानों के पास स्प्रिंकलर सिंचाई के उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। पी एम कृषि सिंचाई योजना के तहत यह अनुदान देने की घोषणा की गयी है।

पी एम कृषि सिंचाई योजना से मिलेंगे यह लाभ

पी एम कृषि सिंचाई योजना से किसानों को सिंचाई सम्बंधित पूरी मदद और सलाह सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत ही किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से ही अपनी रबी की फसलों की सिंचाई करें।

सरकार की यह योजना अत्यधिक जल खपत को कम करने के साथ साथ किसानों की पैदावार भी बेहतर करना चाहती है। पी एम कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए काफी सहायता मिलती है, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे सिंचाई के माध्यम से रबी की फसलों में बेहतर तरीके से सिंचाई की जा सकेगी।

स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए कितना अनुदान मिलेगा

पी एम कृषि सिंचाई योजना के तहत बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय (बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट) किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए ९० प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान कर रही है।

किसान जनपद के समीप किसी भी उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर योजना सम्बंधित सहायता ले सकते हैं।

स्प्रिंकलर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए https://www.pmksy.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

स्प्रिंकलर सिंचाई कौन सी फसलों के लिए बेहतर है, इसके क्या लाभ हैं

स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से चाय, आलू, प्याज, धान, गेंहू और सब्जी की फसलों में सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर सिंचाई बेहद ही अच्छी और फायेमंद तकनीक है, इसकी सहायता से जल की बर्बादी रोकने के साथ साथ कीटनाशक दवाओं का भी फसल में छिड़काव किया जा सकता है। अत्यधिक जल की वजह से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई बेहद सहायक होती है।

सरकार से मिल रहा ड्रोन लेने पर 100 % तक अनुदान, तो क्यों न लेगा किसान

आजकल खेती के लिए नयी नयी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे फसल के उत्पादन के लिए कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से खेती की देखभाल और रख रखाव बेहद आसान हो गया है, कृषि क्षेत्र में ड्रोन (Agriculture Drone) की उपस्थिति ने एक नयी कृषि प्रणाली को प्रचलन में ला दिया है। किसान ड्रोन की सहायता से फसल को कीटनाशकों से बचाने के लिए छिड़काव आदि कर सकते हैं।

ज्यादातर किसान आर्थिक रूप से ड्रोन जैसे महंगे उपकरण खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है, जिससे किसान आवश्यक यंत्रों को आसानी से खरीद सकें। साथ ही, सरकार के द्वारा ड्रोन के उपयोग को खेती किसानी में बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, इसी के अनुरूप सरकार द्वारा बम्पर सब्सिडी देने की बात कही जा रही है।

ड्रोन पर कितना अनुदान मिल रहा है ?

फसल की कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता बेहद आवश्यक है, सरकार ड्रोन जैसे कृषि उपकरणों पर अनुदान दे रही है, जिसमें कृषि प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद पर १०० % तक या १० लाख रुपये तक अनुदान दिया जायेगा।

कृषि से स्नातक युवा, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं महिला किसान ५० % या ५ लाख रुपये तक अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

कृषक उत्पादक संगठनों को ड्रोन की खरीद पर ७५ % तक अनुदान दिया जायेगा।

इसके साथ ही अन्य किसानों को ४० % या ४ लाख रुपये तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सरकार द्वारा भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अनुदान का प्रतिशत भी भिन्न भिन्न है, हालाँकि सरकार अधिकतर किसानों को लाभान्वित करने के लिए पूरी योजना में है।

ड्रोन किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है

किसान जिस भूमि में १ घंटे में जितना कीटनाशक छिड़काव कर पाते हैं, ड्रोन की सहायता से उतनी ही फसल में २० मिनट में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसानों को फसलीय कीड़े मकोड़ों से होने वाली क्षति से भी दूर रखा जा सकता है।

आकस्मिक रूप से फसलों में कीट और रोगों के आने के बाद पूरी फसल में समयानुसार छिड़काव, किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है, जिसमे ड्रोन उनकी इस समस्या के निराकरण के लिए बेहद सहायक होगा। ड्रोन की क्षमता कम समय में अधिक भूमि में बेहतर रूप से छिड़काव करने की है।

क्या किसान ड्रोन को अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे

बदलते दौर में किसानों ने समयानुसार कृषि यंत्रों को सुचारु रूप से उपयोग में लाने का कार्य किया है एवं आधुनिक यंत्रों से उत्पादन में भी वृद्धि की है। धीरे धीरे किसान ड्रोन के उपयोग को बड़े स्तर पर कृषि उत्पादन में लाने का कार्य करेंगे। सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से किसानों को ड्रोन खरीदने और उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। परिणामस्वरूप इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उत्पादन में निश्चित रूप से सहजता भी होगी।

हरियाणा राज्य में कृषि सम्बंधित उपकरणों पर मिल रहा 80 % सब्सिडी, समय से करलें आवेदन

आजकल कृषि जगत में कृषि उपकरणों की अहम भूमिका है, आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान की मेहनत के साथ साथ उनकी लागत में भी बेहद कमी आयी है। पहले किसान काफी परिश्रम करके फसल को उगाते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान की सहायता से नवीन कृषि उपकरणों की खोज हो रही है, जिससे किसानों के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों की उपलब्धता तीव्रता से बढ़ी है।

सरकार उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि सम्बंधित उपकरणों पर अनुदान देने की योजना लाती रहती है। इसी सन्दर्भ में फ़िलहाल हरियाणा सरकार किसानों के लिए ८० प्रतिशत तक का अनुदान देने का आह्वान कर चुकी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे कि बुवाई, छिड़काव और कटाई से सम्बंधित उपकरण भी शामिल हैं।

हरियाणा सरकार ८० प्रतिशत तक क्यों दे रही है कृषि यंत्रों पर अनुदान ?

किसानों की आर्थिक हालत को देखते हुए सरकार ये भली भांति जानती है कि बहुतायत किसान आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन पैदावार में वृद्धि और किसान की लागत में कमी के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है।

सरकार किसानों की समस्या को समझते हुए उनके लिए ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की इस मुहिम से, किसानों को आर्थिक तंगी से निजात दिलाना चाहती है। साथ ही हरियाणा राज्य को काफी उन्नत राज्य बनाने की राह पर चलना शुरू कर रही है, क्योंकि हरियाणा राज्य में अधिकतर लोग कृषि आश्रित होते हैं, इसलिए कृषि जगत को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। किसान की उन्नति से ही राज्य और देश की उन्नती का मार्ग जाता है।

कौन कौन से कृषि उपकरणों पर मिल रहा है अनुदान ?

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इन कृषि उपकरणों पर मिल रहा है अनुदान जिसमें, रोटावेटर, हे रेक मशीन, मोबाइल श्रेडर, रिप्पर बाइंडर, स्ट्रॉ बेलर, फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, लेसर लैंड लेवलर समेत ११ कृषि उपकरण सम्मिलित हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कृषि विभाग के माध्यम से वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जानकारी उपलब्ध कराई है, जहाँ किसान भाई आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए कृषि केंद्र की सहायता भी ले सकते हैं।

पूर्व में भी पराली के अवशेष से निजात के लिए उपकरण अनुदान देने के लिए मांगे थे आवेदन

हरियाणा राज्य सरकार ने पराली से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी कृषि उपकरणों पर अनुदान देने की घोषणा की और आवेदन करने के लिए बोला था, जिससे पराली के अवशेष को नष्ट किया जा सके और दिल्ली समेत अन्य शहरों को भी प्रदुषण की मार से बचाया जा सके।

भंडारण की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, प्री कूलिंग यूनिट के लिए 18 लाख रुपये देगी सरकार

उत्पादन करने के बाद फसलों का भंडारण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या उन फसलों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी है जो बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान देखा गया कि फसलों का बंपर उत्पादन होने के बावजूद ज्यादतर फसलें उचित भंडारण न होने के कारण खेतों में ही पड़े पड़े खराब हो गईं, जिसके कारण किसानों को भारी घाटा झेलना पड़ा। क्योंकि उन दिनों सभी प्रकार के मार्केट बंद होने के साथ ही मंडियां भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही थीं, जिसके कारण किसान अपनी फसलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए और फसलें सड़ गईं।

इसके अलावा किसानों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि कई फसलें ऐसी होती हैं, जो कटाई के बाद थोड़ी भी बरसात नहीं झेल पातीं और पानी पड़ते ही उनमें सड़न उत्पन्न होने लगती है। ये किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार की समस्या को देखते हुए अब सरकार किसानों की सहायता के लिए आगे आई है। सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे किसान अपनी फसलों का भंडारण उचित मात्रा में कर पाएं और जब उन्हें अच्छा भाव मिले तब वो अपनी फसलों को मंडियों में बेच पाएं।

इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए प्री कूलिंग यूनिट (Pre Cooling Unit) यानी कोल्ड स्टोरेज (cold storage) लगाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत बिहार सरकार किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को 18 लाख 75 हजार रूपये तक का अनुदान उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसान तथा किसान उत्पादक संगठन एक अच्छे प्री कूलिंग यूनिट का निर्माण कर पाएं, जिसमें वो अपनी फसलों का भंडारण सुरक्षित तरीके से कर सकें।

कितनी मिलेगी प्री कूलिंग यूनिट लगाने पर सब्सिडी ?

बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय (Bihar Agriculture Department , Horticulture Directorate) ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत राज्य के किसानों, व्यक्तिगत निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों को जो प्री-कूलिंग यूनिट लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है, उसमें प्रति इकाई अधिकतम लागत 25 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

• यदि किसान और व्यक्तिगत निवेशक इस इकाई को लगाते हैं, तो सरकार अधिकतम लागत 25 लाख रूपये का 50 प्रतिशत, यानी 12 लाख 50,000 रुपये का अनुदान देगी।

• वहीं यदि किसान उत्पादन संगठन (FPO/FPC) प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज इकाई लगाना चाहता है, तो सरकार उस संगठन को अधिकतम लागत 25 लाख रूपये का 75 प्रतिशत, यानी 18 लाख 75,000 रुपये का अनुदान प्रदान करेगी।

बिहार राज्य के जो भी किसान तथा किसान उत्पादक संगठन एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)) के तहत यह प्री कूलिंग स्टोरेज इकाई लगाना चाहते हैं, वो बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर नियम और कायदे देख सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान या किसान उत्पादक संगठन ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं वो अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन और दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो और किसान होने का कोई प्रमाण अपने साथ रखें। ये दस्तावेज आवेदन करते वक़्त साथ में संलग्न करने होंगे।

गाय-भैंस की देशी नस्लों का संरक्षण करने वालों को मिलेगा 5 लाख का ईनाम, ऐसे करें आवेदन

देश भर में देसी गाय-भैंस की लगातार कमी होती जा रही है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह देसी गाय-भैसों के कारण लगातार घटता हुआ मुनाफा है। विदेशी नस्लों की गाय-भैंसों की अपेक्षा देसी गाय-भैंसों को पालने में किसानों को उतना फायदा नहीं होता, जितना किसान वास्तव में मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन देसी गाय-भैंसों को लेकर किसानों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम यह है कि गाय-भैंसों की कई प्रकार की देसी नस्लें अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं।

गाय-भैंसों की देसी नस्लों का संरक्षण

इसको देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं चलाईं हैं, ताकि गाय-भैंसों की देसी नस्लों का संरक्षण किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying) ने गोपाल रत्न पुरस्कार (National Gopal Ratna Award-2022) देना प्रारम्भ किया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना (Rashtriya Gokul Mission (RGM)) के तहत, जो हर साल की तरह इस साल भी पशुपालकों को दिया जाएगा। सरकार यह पुरस्कार पशुपालन में गाय भैंसों को संरक्षण देने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए दिया जाता है। इस योजना का मकसद स्वदेशी दुधारू गाय-भैसों में कृतिम गर्भाधान करके दुग्ध उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार यह योजना लेकर आई है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का एक अन्य उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को 100 प्रतिशत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या एआई (AI – Artifical Intelligence) कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही सरकार इस योजना के माध्यम से सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को विकसित करने पर जोर दे रही है। साथ ही सरकार चाहती है कि दुग्ध उत्पादक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे, ताकि उत्पादन के साथ दुग्ध क्वालटी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाया जा सके।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक 30 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विजेताओं को 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (NMD – National Milk Day) के अवसर पर केंद्र सरकार पुरस्कृत करेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रूपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

चूंकि अंतिम तारीख नजदीक ही है, इसलिए राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने अपने राज्य के किसानों को जल्द से जल्द इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कहा है। पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहे दुग्ध उत्पादन को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। इसलिए मंत्रालय अब हर साल पशुपालकों के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेगा।

कौन लोग हैं इस पुरस्कार के लिए पात्र ?

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सिर्फ ऐसे पशुपालक ही पात्र हैं, जो गाय की प्रमाणित स्वदेशी 50 नस्लों अथवा भैंस की 17 देसी प्रमाणित नस्लों में से किसी एक का पालन करते हों। इसके साथ ही ऐसे तकनीशियन, जो पशुधन विकास बोर्ड, दुग्ध फेडरेशन, गैर सरकारी संगठन में काम करते हो तथा ऐसा कोई भी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जिसने इसके लिए 90 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ऐसे सभी लोग इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र हैं।

इनके अलावा ग्राम स्तर की ऐसी सहकारी समिति जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित हुई हो, ऐसा दुग्ध उत्पादक यूनियन जो प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन करता है, साथ ही उसके साथ कम से कम 50 किसान जुड़े हैं और एमपीसी या एफपीओ भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन के पात्र होंगे।

कैसे कर सकते हैं आवेदन ?

इच्छुक किसान, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कम्पनियां 30 सितंबर के पहले तक गोपाल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट https://awards.gov.in में जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक़्त किसान आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, मोबाइल नंबर, पशु की जानकारी वाले कागजात ज़रूर साथ रखें। आवेदन करते वक़्त इनकी जरुरत पड़ सकती है।

बिहार में मशरूम की खेती करने पर सरकार दे रही 90 फीसदी अनुदान

मशरूम यानी कुकुरमुत्ता (कवक – Mushroom) की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा एलान किया है। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को मशरूम की खेती करने पर 90 फीसदी तक अनुदान देने की घोषणा की है।

अभी तक बिहार में किसान परम्परागत खेती ही करते रहे हैं। लेकिन इस बार मशरूम की खेती की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक अच्छी मुहिम शुरू की है। इस साल मशरूम की खेती पर 90 फीसदी तक अनुदान देकर सरकार मशरूम की खेती पर जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना से मिलेगा अनुदान

बिहार सरकार मशरूम की खेती करने वाले किसानों को 'मुख्यमंत्री बागवानी मिशन' के तहत 90 फीसदी तक अनुदान दे रही है। योजना में शामिल होने के लिए किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, किसानों में भी इस योजना को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।

खगरिया जिले में 500 किसान कर रहे हैं मशरूम की खेती

बिहार में अभी तक खगरिया जिले में तकरीबन 500 किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं। सरकार द्वारा मशरूम की खेती पर प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मशरूम की खेती करने वाले किसानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

झोंपड़ी में मशरूम की खेती से किसान की आमदनी होगी दोगुनी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत झोंपडी में मशरूम की खेती करने वाले किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। इस योजना के तहत किसानों को अलग से 50 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है। झोंपड़ी बनाने से लेकर मशरूम की खेती करने तक आने वाली लागत पर 50 फीसदी अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है, इस कुल लागत का 50 प्रतिशत खर्च यानि 20 लाख रुपए की लागत में 10 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार वहन करेगी और शेष धनराशि किसान को लगानी होगी।

मशरूम पर अनुदान के लिए ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम की खेती पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर किसान चाहें तो इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी जिले के उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर सहायक निदेशक से भी संपर्क किया जा सकता है।

देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करेगी सरकार, देश भर में बांटेगी मिनी किट

इस साल देश के कई राज्यों में खरीफ की फसल मानसून की बेरुखी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई है। उत्पादन में यह गिरावट किसानों की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यदि किसान खरीफ की फसल में लाभ नहीं कमा पाए तो उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर किसानों के पास पैसा नहीं रहा तो किसानों के लिए रबी की फसल में बुआई करना मुश्किल हो जाएगा। बिना पैसों के खेती से जुड़ी चीजें जैसे कि खाद, बीज, कृषि उपकरण, डीजल इत्यादि सामान खरीदना किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा।

किसानों की इन चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों की मदद करने जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के लिए रबी सीजन में दलहन और तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुफ्त मिनी किट वितरित करेगी। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे देश भर में दलहन के उत्पादन में लगभग 20-25 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है। इसको देखते हुए मिनी किट वितरण की रूप रेखा तैयार कर ली गई है।

देश भर में मिनी किट का वितरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अंतर्गत आने वाली संस्था राष्ट्रीय बीज निगम – एनएससी (NSC) करेगी। इन मिनी किटों का भुगतान भारत सरकार अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किया जाएगा। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की योजना के अनुसार इन मिनी किटों का वितरण उन्हीं राज्यों में किया जाएगा, जहां दलहन एवं तिलहन का उत्पादन किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य क्या है

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों के बीच फसलों की नई किस्मों को लेकर जागरूक करना है, ताकि किसान इन मिनी किटों के माध्यम से नई किस्मों के प्रति आकर्षित हों और ज्यादा से ज्यादा रबी की बुआई में नई किस्मों का इस्तेमाल करें।

इस योजना के अंतर्गत किसानों के बीच मिनी किटों में उच्च उत्पादन वाले बीजों का वितरण किया जाएगा। मिनी किटों का वितरण महाराष्ट्र के विदर्भ में रेपसीड और सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में वहां की प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अलसी और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कुसुम (सूरजमुखी) का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत किसानों के बीच मिनी किटों में उच्च उत्पादन वाले बीजों का वितरण किया जाएगा। मिनी किटों का वितरण महाराष्ट्र के विदर्भ में रेपसीड और सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में वहां की प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अलसी और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कुसुम (सूरजमुखी) का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने इस साल देश भर के 11 राज्यों में दलहन की बुवाई बढ़ाने के लिए, उड़द के 4.54 लाख बीज मिनी किट और मसूर के 4.04 लाख बीज मिनी किट राज्यों को भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा 1,11,563 मिनी किट भेजे गए हैं, इसके बाद झारखण्ड के लिए 12,500 मिनी किट और बिहार के लिए 12,500 मिनी किट भेजे गए हैं।

इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय एक और योजना लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत देश भर के 120 जिलों में मसूर और 150 जिलों में उड़द का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना को विशेष कार्यक्रम '(TMU 370; टीएमयू 370) 'तूर मसूर उड़द – 370" के नाम से प्रचारित किया जाएगा।

अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 सालों के दौरान देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। अगर साल 2018-19 तक अब की तुलना करें तो दलहन के उत्पादन में 34.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां साल 2018-19 में दलहन का उत्पादन 727 किग्रा/हेक्टेयर था। जबकि मौजूदा वर्ष मे दलहन का उत्पादन बढ़कर 1292 किग्रा/हेक्टेयर पहुंच गया है।

भारत सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये तीन नए उत्कृष्टता केंद्र

भारत दुनिया में मोटे अनाजों (Coarse Grains) का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए भारत इस चीज के लिए तेजी से प्रयासरत है कि दुनिया भर में मोटे अनाजों की स्वीकार्यता बढ़े। इसको लेकर भारत ने साल 2018 को मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया था और साथ ही अब साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स (आईवायओएम/IYoM-2023) के तौर पर मनाएगा। इसका सुझाव भी संयुक्त राष्ट्र (United Nations) संघ को भारत सरकार ने ही दिया है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहमति जताई है।

देश के भीतर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने देश में तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये हैं, जो देश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होंगे, साथ ही ये उत्कृष्टता केंद्र देश में मोटे अनाजों के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे।

इन तीन उत्कृष्टता केंद्रों में से पहला केंद्र बाजरा (Pearl Millet) के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar) में स्थापित किया गया है। यह केंद्र पूरी तरह से बाजरे की खेती के लिए, उसके उत्पादन के लिए तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, इसके साथ ही यह केंद्र लोगों के बीच बाजरे के फायदों को लेकर जागरूक करने का प्रयास भी करेगा।

इसी कड़ी में सरकार ने दूसरा उत्कृष्टता केंद्र भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (Indian Institute of Millets Research (IIMR)) में स्थापित किया है। यह केंद्र ज्वार (Jowar) की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह केंद्र देश भर में ज्वार की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करेगा, साथ ही लोगों के बीच ज्वार से होने वाले फायदों को लेकर जागरूकता फैलाएगा।

इनके साथ ही तीसरा उत्कृष्टता केंद्र कृषि विज्ञान विश्विद्यालय, बेंगलुरु (University of Agricultural Sciences, GKVK, Bangalore) में स्थापित किया गया है। यह उत्कृष्टता केंद्र छोटे मिलेट्स जैसे कोदो, फॉक्सटेल, प्रोसो और बार्नयार्ड इत्यादि के उत्पादन और प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है।

मोटे अनाजों में मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर बाजरा और अन्य कुटकी जैसे कोदो, फॉक्सटेल, प्रोसो और बार्नयार्ड इत्यादि आते हैं, इन सभी को मिलाकर भारत में मोटा अनाज या मिलेट्स (Millets) कहते हैं। इन अनाजों को ज्यादातर पोषक अनाज भी कहा जाता है क्योंकि इन अनाजों में चावल और गेहूं की तुलना में 3.5 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं।

मोटे अनाजों में पोषक तत्वों का भंडार होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद फायदेमंद होते हैं। मिलेटस में मुख्य तौर पर बीटा-कैरोटीन, नाइयासिन, विटामिन-बी6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि खनिजों के साथ विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन अनाजों का सेवन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, इनका सेवन करने वाले लोगों को कब्ज और अपच की परेशानी होने की संभावना न के बराबर होती है।

ये अनाज बेहद चमत्कारिक हैं क्योंकि ये अनाज विपरीत परिस्तिथियों में भी आसानी से उग सकते हैं, इनके उत्पादन के लिए पानी की बेहद कम आवश्यकता होती है। साथ ही प्रकाश-असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन का भी इन अनाजों पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका उत्पादन भी ज्यादा होता है और इन अनाजों का उत्पादन करने से प्रकृति को भी ज्यादा नुकसान नहीं होता।

आज के युग में जब पानी लगातार काम होता जा रहा है और भूमिगत जल नीचे की ओर जा रहा है ऐसे में मोटे अनाजों का उत्पादन एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि इनके उत्पादन में चावल और गेहूं जितना पानी इस्तेमाल नहीं होता। यह अनाज कम पानी में भी उगाये जा सकते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल हैं।

मोटे अनाजों का उपयोग मानव अपने खाने के साथ-साथ जानवरों के खाने के लिए भी कर सकता है, इन अनाजों का उपयोग भोजन के साथ-साथ, पशुओं के लिए और पक्षियों के चारे के रूप में भी किया जाता है। ये अनाज हाई पौष्टिक मूल्यों वाले होते हैं जो कुपोषण से लड़ने में सहायक होते हैं।

मोटे अनाजों का उत्पादन देश में कर्नाटक, राजस्थान, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यहां की जलवायु मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए अनुकूल है और इन राज्यों में मिलेट्स को आसानी से उगाया जा सकता है, इसके साथ ही इन राज्यों के लोग अब भी मोटे अनाजों के प्रति लगाव रखते हैं और अपनी दिनचर्या में इन अनाजों को स्थान देते हैं।

इसके अलावा इन अनाजों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति करना है। मोटे अनाजों के पेड़ों का उपयोग कई राज्यों में पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, इनके पेड़ों को मशीन से काटकर पशुओं को खिलाया जाता है, इस मामले में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश टॉप पर हैं, जहां मोटे अनाजों का इस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए बहुतायत में उत्पादन किया जाता है।

मोटे अनाजों के कई गुणों को देखते हुए सरकार लगतार इसके उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। जहां साल 2021 में 16.93 मिलियन हेक्टेयर में मोटे अनाजों की बुवाई की गई थी, वहीं इस साल देश में 17.63 मिलियन हेक्टेयर में मोटे अनाजों की बुवाई की गई है। अगर वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो देश में हर साल 50 मिलियन टन से ज्यादा मिलेट्स का उत्पादन किया जाता है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को सम्बोधित करते हुए मोटे अनाजों को 'सुपरफूड' बताया था। उन्होंने अपने सम्बोधन में इन अनाजों से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया था। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के विभिन्न नेताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स फूड फेस्टिवल के आयोजन की वकालत की थी। उन्होंने बताया था की इन अनाजों के उत्पादन के लिए कितनी कम मेहनत और पानी की जरुरत होती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और प्रचारित करने के लिए प्रयासरत है।

किसान समाचार

दीवाली से पहले पीएम मोदी ने करदी किसानों की बल्ले बल्ले, खातों में भेजी पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली से पहले ही किसानों को तोहफा दे दिया है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की १२ वीं किस्त उनके खातों में भेज दी गयी है। बतादें कि पिछले कई दिनों से १२ वीं किस्त के लिए किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार १७ अक्टूबर को पी एम मोदी द्वारा करोड़ों किसानों के खाते में पी एम किसान सम्मान निधि की १२ वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गयी है। किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। दीवाली के समय किसानों को धन की काफी आवश्यकता होती है, ऐसे में पी एम किसान सम्मान निधि की १२ वीं क़िस्त आने से किसानों को आर्थिक सहायता मिली है।

जिन किसान भाइयों की १२ वीं किस्त अभी तक नहीं आयी है उनको तत्काल लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहिए। यदि पात्र होने के बावजूद सूची में नाम अंकित नहीं है, तो सहायक प्रशासन अधिकारी को सूचित करें।

कितने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की १२ वीं किस्त प्राप्त हुई है ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गयी पीएम किसान सम्मान निधि की १२ वीं किस्त से देशभर में लगभग ८ करोड़ से भी अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में २००० रूपये की धनराशि पहुँच चुकी है। किसानों को निर्देश भी दिया गया है कि यदि किसी किसान की १२ वीं किस्त अभी तक उसके खाते में नहीं पहुंच पायी है, तो वह बैंक के शाखा प्रबंधक से बात करे। बैंक से उपयुक्त जानकारी न मिलने पर यदि आवश्यकता पड़े, तो योजना से सम्बंधित अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीवाली से पहले ही किस्त को किसानों के खातों में भेजने के निर्णय से किसान बेहद खुश हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि की १२ वीं किस्त खाते में न पहुँचने की स्तिथि में क्या करें किसान ?

पीएम किसान सम्मान निधि की १२ वीं किस्त यदि अभी तक नहीं पहुंची है तो इस स्तिथि में किसान मेल या फोन के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अधिकारीयों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मेल करने के लिए (pmkisan-ict@gov.in) मेल आईडी पर अपनी समस्या भेज सकते हैं या फिर योजना सम्बंधित हेल्पलाइन नम्बर १५५२६१ या फिर १८००११५५२६ टोल फ्री, अथवा ०११२३३८१०९२ पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करायें। साथ ही बैंक को दी गयी अपनी सभी आवश्यक जानकारियों के पूर्णतया सटीक होने की भी जाँच करलें, जैसे कि आपकी आधार कार्ड संख्या, खाता संख्या एवं नाम इत्यादि।

पीएम मोदी ने किसानों को १२ वीं सम्मान निधि भेजने के साथ ही किया किसान सम्मेलन का भी उद्घाटन

प्रधानमंत्री द्वारा १७ अक्टूबर को जारी की गयी पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ एग्री स्टार्ट अप कॉनक्लेव और किसान सम्मेलन (Agri Startup Conclave & Kisan Sammelan) का भी उद्घाटन कर दिया गया, जिसमें हजारों किसानों एवं सैकड़ों कृषि स्टार्टअप शामिल रहे। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना की भी शुरुआत करदी है एवं ६०० प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को भी स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए किसान हित में निर्णय किसानों को काफी हद तक फायदा पहुंचाने में मदद करेंगे।

दीवाली पर अधिक मांग की वजह से मिलावटी हो रहे तेल, दाल और मसाले

दिवाली के समय तेल, दाल और मसालों के साथ साथ मिठाईयों में भी मिलावट होने की खबर आती रहती है, इसका मुख्य कारण त्योहारों पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग है। क्यूँकि त्योहारों पर पकवान मिठाईयां एवं अन्य भोज्य सामग्री हर घर में बनती हैं, जिसकी पूर्ति करने और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर दाल, तेल और मसालों में मिलावट करते हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों को जहरीला बना देते हैं, जिससे खाने वालों की सेहत खराब हो जाती है।

दिवाली से पहले ही तेल, दाल, मसाले सब्जी व घी में मिलावट करने की बात सामने आयी है। मिलावटयुक्त खाद्य पदार्थों से बचने का प्रयास करें, अच्छी तरह जाँच परख कर ही खरीदें खाद्य सामग्री। इन दिनों खाद्य पदार्थों को लेकर बेहद सजग रहने की आवश्यकता है।

कैसे पहचाने मिलावटी खाद्य पदार्थों को

दिवाली के आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की शिकायत आना शुरू हो जाती है इसलिए राजस्थान सरकार ने 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' (Shuddh Ke Liye Yuddh Abhiyan) शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत जितने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत आती है, जैसे की दाल, तेल, मसाले, घी एवं अनाज आदि, सभी की अच्छी तरह जाँच की जाएगी। हालाँकि जिला जाँच विभाग ने खाद्य उघोगों से कई हजार टन मिलावटी खाद्यान्न पदार्थों को पकड़ा है। ऐसे में किसी भी पदार्थ पर आँख बंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। त्योहारों पर मिलावट की ये खबरें अब बेहद आम बात हो गयी है, आये दिन किसी न किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट होने की खबर से उपभोक्ताओं के अंदर भय व्याप्त हो चुका है। राजस्थान सरकार का 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' लोगों को मिलावटी जहर खाने से बचाने में बेहद सहायक साबित होगा।

क्या दालों में मिलाया जा रहा है धतूरा

राजस्थान जिला प्रशासन विभाग के अधिकारीयों द्वारा इस बात की शंका जताई गयी है कि दाल का वजन बढ़ाने के लिए धन के लालची लोग दाल में धतूरे के बीजों का मिश्रण कर देते हैं, जिससे दाल का वजन बढ़ जाता है। दाल में धतूरे को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि यदि दाल में काले काले दाने दिखें, तो उनको तुरंत निकालकर जाँच करें। क्योंकि अगर धतूरा दाल के साथ उबलने के बाद खा लिया, तो खाने वालों की तबियत बेहद खराब कर सकता है।

क्या हरी सब्जियों और सरसों में भी मिलावट की आशंका है

सब्जियाँ और सरसों का तेल मानव जीवन का बेहद महत्वपूर्ण भाग है। प्रतिदिन जीने के लिए सब्जियों और तेलों की बेहद आवश्यकता होती है। हालांकि इनमे भी आजकल मिलावटखोर मिलावट करने लग गए हैं। जबकि सरसों के तेल का उपयोग खाने से लेकर त्वचा और बालों के लिए भी किया जाता है, ऐसे में अगर इन पदार्थों में मिलावट की जायेगी तो मानव जीवन बेहद प्रभावित होगा। सब्जियों को हरी भरी और ताजातरीन रखने के लिए न जाने कैसे कैसे केमिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है, जिनसे सब्जियां तरोताजा तो रहती ही हैं, लेकिन लोगों को इन्हें खाने के उपरांत बेहद खराब अनुभव होता है।

मध्य प्रदेश: लहसुन की फसल को खेत में जलाने पर मजबूर हुए किसान, वहीं चीन से आयात हो रहा लहसुन

इस साल देश में लहसुन (Garlic) का बंपर उत्पादन हुआ है, जिसके कारण बाजार में लहसुन की भरपूर उपलब्धता है। जरुरत से ज्यादा सप्लाई होने के कारण इन दिनों किसानों को लहसुन के मन मुताबिक़ दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में तो यह हालात हो चुके हैं कि आढ़तिये लहसुन की फसल को कौड़ियों के दाम खरीदने के लिए तैयार हैं। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए प्रदेश के लहसुन किसान निराश होते जा रहे हैं। अब किसानों ने अपनी लहसुन की फसल को खुले में फेंकना शुरू कर दिया है, तो कई किसान अपनी फसल को नदी में फेंक आए हैं। बीते दिनों इस प्रकार के घटनाक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुए हैं।

अगर कृषि उपज मंडी में लहसुन के वर्तमान भाव की बात करें यह मात्र 2 से 5 रूपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। जबकि इसी समय पिछले साल लहसुन का भाव 25-30 रूपये प्रति किलो था। लहसुन का गिरता हुआ भाव किसानों के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसके कारण किसान पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। अभी खबर आई है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में कई किसानों ने लहसुन की फसल के पर्याप्त दाम न मिलने के कारण उसमें आग लगा दी। इस मामले में किसानों का कहना है कि मौजूदा लहसुन के भाव इनपुट लागत और बाजारों तक परिवहन लागत को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो इस फसल को बेवजह घर में नहीं रखना चाहते।

चीन से आयात हो रहा है भारत में लहसुन

एक तरफ भारतीय किसानों को लहसुन के पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं चीन से बड़ी मात्रा में भारत में लहसुन आयात किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण चीनी लहसुन में बड़े बल्ब का होना है। भारतीय बाजार में इन दिनों बड़े बल्ब वाली लहसुन दिनोंदिन फेमस होती जा रही है। जिसके कारण ग्राहक देशी लहसुन की अपेक्षा बड़े बल्ब वाली लहसुन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि चीनी लहसुन के बल्ब बड़े होने के कारण इनको छीलना बेहद आसान होता है।

भारत में लहसुन की पर्याप्त कीमत न मिलने का एक बहुत बड़ा कारण लहसुन के रकबे में लगतार वृद्धि भी है। जिसके कारण उत्पादन बढ़ा है और बाजार में डिमांड उस रूप से नहीं बढ़ी, जिससे लहसुन के दाम धरातल पर आ गए। अगर पिछले 3 सालों में गौर करें तो पूरे देश में लहसुन के रकबे में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है।

जिन किसानों ने भी लहसुन की खेती में अच्छी मेहनत की है तथा इनपुट लागत के रूप में बड़ी रकम लगाई है, वो अब निराश हो चले हैं। राजस्थान के कोटा और झालावाड़ के लहसुन किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले तो लहसुन की खेती में अच्छी खासी रकम खर्च कर दी है, उसके बाद लहसुन को 6 माह तक स्टोर करने में भी पैसा लगाया है। अब इसके विक्रय से लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। जिसके कारण किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

मुख्यमंत्री योगी ने दी प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन को हरी झंडी – यूपी कैबिनेट बैठक में अहम फैसला

प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जायेगा। सूबे में इस योजना पर अब तेजी से काम होगा। बोर्ड के अध्यक्ष स्वंय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे।

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार प्राकृतिक खेती यानी नैचुरल फार्मिंग (Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक कर रही है। तरह-तरह की योजनाएं लागू कर किसानों को प्राकृतिक खेती करने को प्रोत्साहित कर रही है। अब प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर सूबे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड में शामिल होंगे दो किसान

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जा रहा है। यूपी कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले में बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इनके अलावा प्राकृतिक खेती बोर्ड के उपाध्यक्ष कृषि मंत्री व प्रदेश के वित्त, कृषि विपणन, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता विभाग के मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होंगे। इन सभी विभागों के मुख्य सचिव भी बोर्ड के सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य के दो किसानों को भी बोर्ड की सदस्यता सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ है।

जिला स्तर पर भी होगा बोर्ड का गठन

यूपी कैबिनेट में हुए अहम फैसले में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्राकृतिक खेती बोर्ड का जिला स्तर पर भी गठन किया जाएगा। प्राकृतिक खेती बोर्ड के कार्यों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर बोर्ड का गठन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। जिला स्तर पर बोर्ड के अध्यक्ष जिलाधिकारी और बोर्ड के सचिव कृषि उपनिदेशक होंगे। सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

मक्के की फसल से बिहार में बढ़ेगा एथेनॉल का उत्पादन

मक्के की फसल से बिहार में एथेनॉल (इथेनॉल; Ethanol) का उत्पादन किया जायेगा, जिसके लिए बिहार में बहुत बड़ा और नया प्लांट खुलने जा रहा है। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बेहतर होगी, वहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही एथेनॉल उत्पादन से पेट्रोलियम के दामों में भी कमी आएगी। भारत में ग्रीनफ़ील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट (Green Field Grain Based Ethanol Plant) की शुरुआत बिहार के पूर्णियां जिले में हुई है। यह प्लांट लगभग ६५ हजार लीटर उत्पादन करने में सक्षम है। देश में एथेनॉल से चलने वाली कार भी लॉन्च होने लगी है। आने वाले समय में एथेनॉल की मांग में बढ़ोतरी होने वाली है। मक्के की फसल से बिहार के लोग आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने का कार्य कर रहे हैं।

एथेनॉल की कितनी मांग है बाजार में

बिहार से एथेनॉल खरीदने के लिए पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर तेल कंपनियों को बिहार से एथेनॉल खरीदने के लिए मांग की गयी है। बिहार में लगभग १३९ उद्योगों को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रथम चरण में स्वीकृति दी गयी है, जिससे कि उत्पादन ४ करोड़ लीटर से बढ़कर ५८ करोड़ हो सके। हालाँकि अब बिहार की बेहतरीन पोलिसी से प्रभावित होकर अन्य कम्पनियाँ भी प्लांट खोलने के लिए आग्रह कर रही हैं। भविष्य में एथेनॉल की मांग में अच्छी खासी वृद्धि होने जा रही है, इसलिए एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां पूर्ण प्रयास कर रही हैं।

बिहार में एथेनॉल प्लांट की शुरुआत पुर्णिया जनपद से हुई है

बिहार के पुर्णिया जिले में सर्वप्रथम ग्रीनफ़ील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की शुरुआत हुई है, साथ ही यह बिहार का पहला वाटर बॉटलिंग प्लांट भी है। बिहार में एथेनॉल प्लांट के खुलने से करीबी क्षेत्रों में उन्नति होगी, जिसमें कतिहार, अररिया, किशनगंज और पुर्णिया जनपद सम्मिलित हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था को देखते हुए वहां औद्योगिक क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है। बिहार में रोजगार के कम अवसर होने की वजह से वहां के ज्यादातर लोगों को अपनी आजीविका के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और वास्तविक मजदूरी से कम कीमत पर काम करना पड़ता है। एथेनॉल प्लांट खुलने से उनको गृह राज्य में ही रोजगार का अवसर प्राप्त हो पायेगा।

किसानों को एथेनॉल प्लांट खुलने से क्या लाभ होगा

एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का और धान जैसी फसलों की बेहद आवश्यता होती है और बिहार में मक्का की फसल से एथेनॉल उत्पादन किया जायेगा, जिसका प्रथम प्लांट पूर्णियां जिले में खुल चुका है। किसानों को मक्का और धान की फसल में काफी मुनाफा मिलेगा, साथ ही अच्छी कीमत पर उनकी फसल विक्रय हो पायेगी। किसानों को खाली समय में रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा।

एथेनॉल उत्पादन से देश को क्या लाभ होगा

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी; EBP – Ethanol Blended Petrol) कार्यक्रम जनवरी 2003 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम ने वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने की मांग की। चूंकि इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, यह इंजन में ईंधन को पूरी तरह से दहन करने देता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन कम होता है और इस तरह पर्यावरण कम प्रदूषित होता है।

विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2021 के अवसर पर, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अब संभव है। वर्ष 2025 तक, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के उत्पादन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वाहन निर्माताओं की विशिष्ट जिम्मेदारियों का सुझाव दिया गया है।

वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण से देश को अपार लाभ मिल सकता है, जैसे प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन, बेहतर वायु गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग, किसानों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन और अधिक निवेश के अवसर मिलेंगे।

एथेनॉल उत्पादन से देश की अर्व्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ पेट्रोलियम का आयात भी कम होगा, जिससे देश का पैसा बचेगा। फ़िलहाल एथेनॉल सम्मिश्रण की मात्रा देश में ५% है, जिसको वर्ष २०२५ तक २०% तक करने की तैयारी है। इससे पेट्रोल के खर्च में कमी आएगी और भारत आत्मनिर्भरता की और बढ़ेगा। पेट्रोलियम के लिए पूर्णतया विदेशों पर निर्भर रहने से देश का अधिक खर्च होता है, देश में ही एथेनॉल उत्पादित करके जीडीपी में बढ़ोत्तरी भी होगी और देश की स्थिति भी बेहतर होगी।

बारिश ने मचाई तबाही, किसानों ने अपनी जान गंवाई

बीते कुछ दिनों से भारी बरसात के चलते किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, कई दिनों से किसानों के घर चूल्हे नहीं जल पा रहे। किसान बेहद दुखी और निराश हैं, इसका एकमात्र मूसलाधार बारिश ही कारण नहीं है, इसका दूसरा कारण किसानों की आर्थिक स्तिथि भी है। किसान पूर्णतया कृषि के उपर ही आश्रित रहते हैं, अगर फसल में कोई नुकसान होता है तो प्रत्यक्ष रूप से किसान की आजीविका को खतरा हो जाता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में अब तक कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि किसानों को भारी नुकसान होने से उनको उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या जुलाई की तुलना में ३ गुना बढ़ गयी है। इसमें इकलौते नांदेड़ जिले में अगस्त तक ९३ आत्महत्या के मामले सामने आये हैं, जिनमें से ६३ किसानों को १ लाख रूपए प्रति किसान के हिसाब से पात्र घोषित किया गया था। पिछले वर्ष ११९ किसानों की आत्महत्या की पुष्टि हुई थी, जिसमें मात्र ६५ लोगों को ही आर्थिक सहायता मिल पायी थी। महाराष्ट्र में मराठवाडा क्षेत्र में ही ६६१ आत्महत्या करने वाले किसानों में से मात्र ४८५ परिवार को ही आर्थिक सहायता मिल पायी थी।

महाराष्ट्र की कितनी भूमि में फसल बर्बाद हो चुकी है ?

महाराष्ट्र में बारिश के कोहराम से बहुत बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुयी है, लगभग ३,६५२,८७२ हेक्टेयर भूमि बुरी तरह प्रभावित हो गयी है। किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। किसान अपनी फसल को पैदा करने के लिए पहले कर्ज लेकर लागत लगाते हैं, इस वजह से फसल में नुकसान होने की स्तिथि में आय होने की जगह किसानों के उपर कर्ज की मार पड़ जाती है, जो किसानों के लिए बेहद चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में किसान कैसे अपनी कर्ज की धनराशि को चुका पायेगा, जब साथ ही उसकी आजीविका के लिए भी पर्याप्त धन अर्जित करने का एकमात्र स्त्रोत भी नष्ट हो गया है।

क्या किसानों के नुकसान की भरपाई हो पायेगी

किसानों को सरकार द्वारा तभी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जब उनकी फसल ३३ प्रतिशत से अधिक खराब हो गयी है। अब इस स्तिथि में बहुत सारे किसान आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं। यह कहना पूर्णतया उचित नहीं होगा कि समस्त पीड़ित किसानों को पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता मिल पायेगी। किसानों को सहायता मिलने को लेकर संशय बना हुआ है, परिणामस्वरूप प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

NEW HOLLAND AGRICULTURE

अब नहीं होगी किसानों को उर्वरकों की कमी, फसलों के लिए प्रयाप्त मात्रा में मिलेगा यूरिया और डी ए पी

किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया (urea) और डी ए पी (DAP) की आवश्यकता होती है। पिछले साल किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक न उपलब्ध होने की वजह से बहुत समस्या आयी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पूर्ण मात्रा में करने की तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही किसानों को सूचित किया गया है कि उर्वरकों की तरफ से किसानों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यता नहीं है, भरपूर मात्रा में यूरिया और डी ए पी का प्रबंध है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं उर्वरकों की प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की है। शिवराज चौहान केंद्र सरकार के सहयोग से भरपूर मात्रा में उर्वरकों की पूर्ति करने में सफल रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक १९.०९ लाख मीट्रिक टन यूरिया, ८.५८ लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट और ३.४२ लाख मीट्रिक टन एनपीके (NPK) की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी की पहचान किसान मित्र के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वह किसानों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनायें लागू करते रहते हैं। दशहरा से पहले उन्होंने किसानों के खातों में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान से राहत देने के लिये सहायक धनराशि ट्रांसफर की है। अब रबी की फसल के लिए किसानों को यूरिया और डी ए पी आदि की कमी न रहे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार पूर्व से ही यूरिया और डी ए पी का उचित प्रबंध करने में जुट गयी है।

उर्वरकों के वितरण का क्या प्रबंध होगा ?

उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी सही प्रकार से वितरण करना एक मुख्य समस्या रही है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार वितरण प्रणाली को बेहतर और प्रभावी बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे किसी भी किसान को उर्वरकों के लिए इंतज़ार न करना पड़े और उसके पास समय से ही पूर्ण मात्रा में यूरिया इत्यादि उपलब्ध हो सके।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का सख्त निर्देश है कि उर्वरकों की उपलब्धता से सम्बंधित किसी भी किसान की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और जिन किसानों की शिकायत आयी हों, उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाये।

आखिर किस कारण सहकारिता विभाग से कम हुआ उठान?

सहकारिता विभाग से उर्वरकों के कम उठान के सन्दर्भ में कृषि विभाग के मुख्य सचिव अजित केसरी जी का कहना है कि राज्य में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मध्य प्रदेश सरकार उर्वरकों के लिए केंद्र सरकार का सहयोग ले रही है। केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भरपूर उर्वरक प्रदान किये जा रहे हैं, यही कारण है कि सहकारिता विभाग से उर्वरकों के उठान में बेहद कमी देखने को मिल रही है। साथ ही जनपद विपणन अधिकारियों को किसानों की उर्वरक सम्बंधित मांग को अतिशीघ्र पूर्ण करने का आदेश है।

गन्ना किसानों को दिवाली के तोहफे के रूप में मिलेंगे सरकार से 900 रुपए प्रति हेक्टेयर

सरकार द्वारा दिवाली के त्यौहार को खुशनुमा बनाने के लिए गन्ना (ganna; sugarcane) किसानों के लिए उपहार के रूप में ९०० रूपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, साथ ही किसान अपनी फसल के लिए उर्वरक आदि आसानी से खरीद सकते हैं।

भारत चीनी उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ देश बन कर उभरा है, इसके साथ ही चीनी के उत्पादन में बेहद वृद्धि आयी है। सरकार द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान समय से कर दिया गया है, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को किसी संकट से न जूझना पड़े। गन्ना किसानों को ९०० रूपए प्रति हेक्टेयर की मदद से जरूरी दवाएं एवं अन्य उर्वरक खरीदने के लिए आर्थिक बल मिलेगा, त्यौहार के समय सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए यह बेहद बड़ी खुशखबरी दी गयी है।

गन्ना किसानों को अनुदान किस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जायेगा ?

गन्ना किसानों को सरकार अनुदान की रकम "पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम" एवं "बीज भूमि उपचार कार्यक्रम" के माध्यम से प्रदान की जाएगी, अनुदान की राशि प्रति हेक्टेयर ९०० रूपए है। पूर्व में गन्ना रसायनों के कुल खर्च का लगभग ५० प्रतिशत अनुदान ही मिलता था, जिसकी धन राशि ५०० रूपये होती थी। जबकि पेड़ी गन्ना की फसल सुरक्षा के लिए १५० रुपए, मतलब ५० फ़ीसदी अनुदान दिया जाता था। सरकार की तरफ से अब किसानों को अधिक अनुदान मिलेगा, जिससे गन्ना किसानों को अच्छी पैदावार करने के लिए काफी मदद मिलेगी।

रसायन के उपयोग से गन्ने की खेती

गन्ने की खेती एक उम्दा किस्म की फसल है, जिसको उत्पादित करने के लिए किसान को असामान्य मेहनत और देखरेख करने की आवश्यकता होती है। साथ ही कीट व रोगों से बचाने के लिए गन्ना किसानों को बेहतर किस्म के कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिनके प्रयोग से किसान गन्ने की फसल को अच्छी तरह पैदा कर सकें और अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर सकें। किसान मिट्टी की उत्तम जाँच कराते है जिससे गन्ने की फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

पराली से प्रदुषण नहीं अब बढ़ेगी उर्वरकता

पंजाब में मोहाली के किसानों ने प्रदुषण का कारण बनने वाली पराली (यानी फसल अवशेष or Crop residue or stubble) को ही उर्वरकता एवं उपज बढ़ाने का साधन बना लिया है। किसानों ने पराली के अवशेष को मिट्टी के साथ मिश्रित करके भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहयोगी होने की बात कही है। हालाँकि, यह सच है कि पराली के अवशेष को मृदा में मिलाने से भूमि की उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती है, इसी के अनुरूप किसान भी पराली के अवशेष से मृदा को अधिक उपजाऊ और उर्वरकों के व्यय को कम करना चाहते हैं। किसानों की यह पहल प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए काफी हद तक सहायक होगी।

सभी राज्यों की राज्य सरकार खरीफ की फसल के समय पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता में रहती हैं, क्योंकि किसान धान की फसल की कटाई पिटाई के उपरांत शेष बचे फसल अवशेषों को आग लगा देते हैं, जो वातावरण प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी करती है, जैसे पराली से सम्बंधित कृषि उपकरणों पर अनुदान देना, बायो डिकम्पोज़र का छिड़काव एवं पराली जलाने वालों को रोकने के लिए कानूनी सहायता से उनके विरुद्ध कार्यवाही का भी प्रावधान किया है। लेकिन इन सब इंतेज़ाम के बावजूद भी किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है। पंजाब के किसानों ने प्रदुषण को कम करने के लिए पराली के अवशेष को ही उर्वरक के रूप में चुना है जो बेहद सराहनीय है।

उर्वरकों के खर्च में कितनी कमी आयेगी

जब मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि आएगी तो निश्चित रूप से अन्य उर्वरकों की आवश्यकता में कमी होगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से लागत में कमी एवं पराली के अवशेष का सही उपयोग होगा, परिणामस्वरूप प्रदुषण से काफी हद तक राहत मिलेगी। पंजाब के किसानों ने उर्वरकों की खपत कम करने के लिए इस प्रकार की अद्भुत पहल की है। पराली के अवशेष को मिट्टी में मिलाकर किसान मृदा की शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आगामी फसल में उनको बिना किसी अतिरिक्त व्यय के बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके।

पंजाब में मोहाली जनपद के बदरपुर गाँव निवासी भूपेंद्र नामक किसान, ३० एकड़ जमीन पर आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग करके पराली के अवशेष को मिट्टी में मिला देता है, जो समयानुसार सड़ने के बाद उर्वरकों का कार्य करती है।

आखिर किसान इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी क्यों जलाते हैं पराली

पराली को समय से मृदा में न मिला पाने या अन्य उपयोग में न ले पाने की स्तिथि में, किसानों पर इसको ठिकाने लगाने का दवाब बन जाता है। क्योंकि दूसरी फसल के बीजारोपण के लिए किसानों के पास पर्याप्त समय नहीं बचता, मजबूरन किसानों को पराली के अवशेष में आग लगानी पड़ती है, जिससे वह शीघ्रता से दूसरी फसल का कार्य प्रारम्भ कर सकें। पंजाब में पराली जलाने से सम्बंधित काफी मुक़दमे दर्ज होते आये हैं, जिसकी मुख्य वजह यही है।

मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिली सहायता, 202 करोड़ रुपए हुए जारी

मध्य प्रदेश में इस साल सामन्य से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। कई जिलों में बरसात के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वर्षा के कारण शहरों से लेकर ग्रामीण लोगों का जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। किसानों को इस बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने किसानों की सहायता करने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी वर्षा की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित 19 जिलों के किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 202 करोड़ 64 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की है। इन 19 जिलों में विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगर-मालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़, बैतूल और सिवनी जिले का नाम शामिल है।

अगर इस साल भारी वर्षा से प्रभावित रकबे की बात करें, तो यह लगभग 2 लाख 2 हजार 488 हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस मीटिंग में सम्बंधित जिलों के कलेक्टर और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में अति वृष्टि का बेहद बीरीकी से अध्ययन किया गया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद हर गांव का सर्वे करवाया गया है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने और घरेलू सामग्री के नुकसान और पशु हानि के लिए मध्य प्रदेश शासन पहले ही 43 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि वितरित कर चुका है। अब तक पूरे प्रदेश में 1 लाख 91 हजार 755 किसानों के खातों में सहायता राशि भेजी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत राशि अंतरित करते वक़्त कुछ हितग्राहियों से भी चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा में विदिशा जिले के मनमोहन सिंह दांगी, सागर के संजीव विश्वकर्मा और गुना जिले के रंगलाल ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया को बताया कि इस साल प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है, वहीं 26 जिलों में अधिक वर्षा हुई है तथा 3 जिलों में अत्याधिक बरसात हुई है। मुख्यमंत्री ने बिना देर किये हुए सभी प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश ने फेरा किसानों की उम्मीद पर पानी

दो दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता को बेहद बढ़ा दिया है, क्योंकि अत्यधिक बारिश की वजह से किसानों की बाजरे और धान की फसल के साथ साथ अन्य फसल भी बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ आदि क्षेत्र बेहद संकट से जूझ रहे हैं जहां हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल लगभग ६० से ८० प्रतिशत तक ख़राब हो चुकी है, साथ ही उनके आय का साधन भी जलमग्न हो चुका है।

मथुरा जिले के हसनपुर ग्राम पंचायत में हरेंद्र चौधरी नामक किसान ने बताया है कि उन्होंने खुद की भूमि के अतिरिक्त १०० बीघे भूमि में धान की फसल उगाई हुई थी, जिसको उन्नत रूप से अर्जित करने के लिए उन्होंने सबसे महंगे व अच्छे उर्वरकों का उपयोग किया। फसल भी अच्छी हुई, लेकिन आकस्मिक भारी बरसात ने उनकी सारी मेहनत और लागत को चौपट कर दिया। हरेंद्र ने आँखों में आंसू लाते हुए मेरीखेती के संवाददाता से कहा कि उन्होंने इस फसल के उत्पादन के लिए कर्ज लेकर बीज, उर्वरक इत्यादि की पूर्ति की थी, अब लागत को भी फसल से निकालना असंभव हो गया है, यह कहकर किसान फूटफूट कर रोने लगा।

पीड़ित किसानों ने की आर्थिक सहायता की मांग

बारिश के कहर से किसान आर्थिक संकट के शिकंजे में आ गए हैं, ऐसे में किसानों को उनकी फसल से होने वाले मुनाफे की उम्मीद टूट चुकी है। किसानों में दुःख की लहर है। अब किसानों की उम्मीद सरकार से आर्थिक सहायता के भरोसे ही है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल में ६० से ८० प्रतिशत नुकसान है जिसकी भरपाई के लिए किसान लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

यह क्षेत्र हुए बारिश के चलते अत्यधिक प्रभावित

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले मूसलाधार बारिश से बेहद प्रभावित हुए हैं जिसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर आदि जनपद अच्छे खासे नुकसान की चपेट में आ गए हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में फसल १०० प्रतिशत बर्बाद हो गयी है, जिसमे लेश मात्र भी आय की कोई उम्मीद नहीं बची है।

देश में 5G हुआ लॉन्च, किसानों की बदल जाएगी इस तकनीक से किस्मत

इंतजार खत्म हुआ, आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसचांर के क्षेत्र में 5जी या 5G तकनीक को देश को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने 5G को उपयोग करके भी देखा। पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे-बैठे स्वीडन में कार चलाकर देखी।

मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी ने कहा, "हम भले इस इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी देर से आये हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहले हम ही अपने देश में इसके पूर्ण विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।" इसके साथ ही अम्बानी ने बताया कि रिलायंस जिओ दिसंबर 2023 तक भारत के कोने-कोने में 5G तकनीक को पहुंचा देगा। जिओ के साथ ही भारती एयरटेल ने 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया है।

मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही कंपनियों ने बताया कि 5G तकनीक में इंटरनेट की स्पीड 10GBPS तक बढ़ने वाली है, जो लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। चूंकि इस तकनीक से आम लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बदलने वाली है, इसलिए इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से किसान भी हाई टेक हो सकते हैं, जिससे वो उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं तथा अपनी फसल का विक्रय भी बहुत आसानी से कर सकते हैं।

विशेषज्ञों ने बताया है कि किसान अब 5G नेटवर्क की मदद से घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे की वो घर बैठे ही अब अपने ट्रैक्टर को संचालित कर सकते हैं, तथा 5G तकनीक से द्वारा वह ट्रैक्टर को आदेश भी दे सकते हैं कि कहां पर कैसे काम करना है। किसान अपने ट्रैक्टर को जुताई बुवाई का आदेश भी दे सकते हैं। इसके साथ ही किसान खेतों में ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव भी बेहद आसानी से कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट इसको आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

5G तकनीक के द्वारा किसानों के लिए खेतों की मैपिंग से लेकर निगरानी तक के कामों को करना बेहद आसान हो जाएगा। इससे खेती में होने वाले जोखिमों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही किसानों का बेहद बेशकीमती समय और धन की बचत होगी।

5G तकनीक की सहायता से मंडियों में होगा किसानों को फायदा

सरकार लगातार डिजिटल रूप से किसानों को साक्षर करने का प्रयास कर रही है, और सरकार का उद्देश्य है कि किसान ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रूप से सरकार के साथ जुड़ें। इसको देखते हुए सरकार ने ई-नाम (e-NAM) पोर्टल शुरू किया है, जहां खेती बाड़ी, फसल विक्रय और फसल भंडारण से सम्बंधित किसानों को सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही सरकार ने समय-समय पर बहुत सारे एप्प (mobile app) लॉन्च किये हैं ताकि किसान भाई अपनी नजदीकी मंडी से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पाएं। अब मंडियों में फसल बेचने से लेकर बीजों की होम डिलीवरी तक हर कुछ सरकार ऑनलाइन माध्यम से कर रही है। इसलिए ऐसे कामों को बेहद आसान बनाने में हाई स्पीड इंटरनेट अब बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है।

अभी कई क्षेत्रों और गावों में नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड की समस्या बनी रहती है। गावों में 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद यह समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जिससे किसान आसानी से ऑनलाइन माध्यम से मंडी डीलरों और बिचौलियों से संपर्क साध पाएंगे। मंडी में फसलों की बिक्री में पारदर्शिता आएगी। साथ ही बिना किसी रुकावट के किसान अपनी फसलों को मनचाही जगह पर बेहतर दामों में बेंच पाएंगे।

5G की मदद से खेती करने वाले किसानों की हो सकेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग

इन दिनों भारत में सरकार के साथ ही कई निजी संस्थाएं और NGO किसानों को खेती की ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की धीमी स्पीड होने के कारण इसमें व्यवधान आता है। अब 5G तकनीक के आ जाने से ये बेहद आसान होने वाला है। अब किसान घर बैठे खेती से जुड़े प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी संस्थाओं और NGO का उद्देश्य भी यही है कि किसान जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनें और अपनी आय को बढ़ाएं। 5G तकनीक किसानों के आत्मनिर्भर बनने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

मौसम आधारित खेती में भी मिलेगा 5G का साथ

खेती किसानी एक अलग तरह का व्यवसाय है, यहां कभी भी मौसम की मार किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद कर सकती है। जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन 5G की मदद अब इन चीजों में भी मिलने वाली है। अब किसान 5G की मदद से विशेषज्ञों से मौसम आधारित कृषि परामर्श ले सकते हैं, कि कैसे मौसम में या कितनी बरसात या सूखे में कौन सी खेती लाभदायक होगी।

इसके साथ ही सेंसर आधारित तकनीकों से फसल का सही अपडेट लेकर किसानों का काम बेहद आसान हो जाएगा। प्लांट सेंसर तकनीकों के इस्तेमाल से किसान भाई पौधों का विकास, मिट्टी की संरचना और खेत की जरूरतों का पता बेहद आसानी से लगा पाएंगे। सेंसर तकनीक की मदद से किसान भाई जलवायु या कीट-रोगों की मुसीबतों से पहले से ही सचेत हो जाएंगे। यह सभी चीजें 5 नेटवर्क के माधयम से बेहद आसान होने वाली हैं।

पशुपालन में भी होगा 5G का इस्तेमाल

खेती किसानी के साथ-साथ पशुपालन भी किसानों का एक अहम व्यवसाय है, गावों में ज्यादातर किसान इससे जुड़े हुए हैं। आजकल पशुपालन में किसान भाई पारंपरिक तरीकों के अलावा स्मार्ट डेयरी फार्मिंग की तरफ देख रहे हैं, ताकि किसान भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। अगर हम स्मार्ट डेयरी फार्मिंग की बात करें तो इसकी मदद से किसानों का काम बेहद आसान हो गया है। पशुपालन में भी किसान सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करके पशुओं की हर एक हरकतों पर नजर रख सकते हैं।

सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करके किसान गाय, भैंस, बकरी से लेकर मुर्गी और मछलियों के खाने पीने के साथ दूध देने और अंडे देने के क्रियाकलापों को बेहद आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। मछली पालन में 5G टेक्नोलॉजी वरदान साबित हो सकती है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी का तापमान, मछलियों की हलचल की निगरानी करना और उनका प्रबंधन करना पहले की तुलना में बेहद आसान होने वाला है।

पंजाब सरकार सिचाई पर करेगी खर्च कम, लेगी सौर ऊर्जा की मदद

पंजाब सरकार ने कृषि सिचाई के खर्च को कम करने के लिए १५ हॉर्स पावर सौर ऊर्जा यानि सोलर एनर्जी (solar energy) की सहायता लेने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। पी एम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के लिए सौर ऊर्जा चलित पंप सेट प्रदान करती है। इसी के अनुरूप पंजाब सरकार भी राज्य के किसानों के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है, जिससे राज्य के किसानों की बिजली का खर्च कम हो सके।

पंजाब एक महत्वपूर्ण फसल उत्पादक राज्य है जो कि कृषि जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से खरीफ की फसल के उत्तम उत्पादन के लिए राज्य के किसानों को बीज के साथ साथ अधिक बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि पंजाब सरकार बिजली के खर्च को कम करने के लिए पी एम कुसुम योजना से वित्तीय सहायता की मांग की है।

पंजाब राज्य को भी पी एम कुसुम योजना में सम्मिलित करने की मांग

पंजाब सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्री अमन अरोड़ा जी ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को लिखित में पत्र भेजा है, जिसमें पंजाब राज्य को पी एम कुसुम योजना में सम्मिलित करने की मांग की है। साथ ही, पंजाब सरकार इस मांग को औपचारिक रूप से केंद्र के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है।

हालाँकि, अमन अरोरा जी ने ये भी कहा कि पंजाब राज्य को इस पी एम कुसुम योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। साथ ही पंजाब में ज्यादातर पंप सेट की क्षमता १० से १५ एच पी है, किसान उनको वहन करने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए किसानों को सी एफ ए यानि केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है।

पंजाब राज्य सरकार ने कितने हॉर्स पावर के पंप सेट के लिए माँगा फंड

केंद्र सरकार १ अगस्त २०२२ को पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के किसानों को १५ एच पी क्षमता वाले कृषि पम्पों के लिए सी एफ ए प्रदान करने का प्रावधान किया है, सिर्फ पंजाब राज्य में ही यह ७.५ एच पी तक है। लेकिन पंजाब राज्य सरकार ने १५ एच पी हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा पंप सेट की मांग रखी थी।

बरसात की मार से त्रस्त हुए मौसम्बी के बाग़, किसानों में हाहाकार

महाराष्ट्र में भारी बरसात की वजह से सभी फसलों की भाँति मौसम्बी (मौसंबी; mosambi fruit; Citrus limetta) भी चपेट में आयी है। मोसंबी के बागों से काफी हद तक फल गिर चुके हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के किसान बहुत प्रभावित हुए हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है, साथ ही किसान बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, हालाँकि किसानों ने सरकार से भी उचित मुआवजा प्राप्त करने की गुहार लगायी है।

पेड़ों से मौसंबी के गिरने की वजह से फलों में सड़न व कीटाणु भी हो गये हैं। भारी बरसात के कारण बागों में भी जलभराव हो गया है, जो फलों की बर्बादी की वजह बन गया है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तो इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें जलना, नाशिक समेत कई जिले शामिल हैं।

किसानों द्वारा जल्द मुआवजा प्रदान करने की मांग ?

किसान अपनी फसल को लेकर बेहद उत्साहित एवं अच्छे मुनाफा मिलने की आस लगाए बैठे थे, क्योंकि दशहरा और दिवाली पर अन्य फलों की भाँति मौसम्बी की भी मांग में वृद्धि आती है, जिससे उनको काफी अच्छे दाम मिलने की संभावना थी। अत्यधिक बारिश के कारण बागों में जलभराव से फलों का गिरना और संक्रमित होना चालू हो गया है।

अब ऐसे में उनको फलों का वाजिब दाम मिलना असम्भव है, साथ ही किसानों की लागत और मेहनत भी निकलना मुश्किल हो गयी है। किसान को बाजार और प्राकृतिक आपदा की दोहरी मार पड़ रही है, अब कैसे अपना जीवन यापन करें, ये किसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

भारी बारिश के कारण फलों की उपलब्धता में कितनी गिरावट आयी है ?

उपरोक्त में जैसा कि बताया गया है कि फल फ्रूट की फसल में जलभराव की वजह से हुई तबाही के चलते निश्चित रूप से फलों के उत्पादन में गिरावट आयी है, जो कि काफी हद तक बाजार में मौसम्बी सहित अन्य कई फलों की उपलब्धता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। हालाँकि किसानों द्वारा ८० % नुकसान की मुआवजा राशि लेने की माँग की गयी है।

मौसम्बी फल में फफूँद रोग, कीट का प्रकोप बढ़ना आदि कई रोगों की चपेट में है। इससे यह पता चलता है कि इस बार मोसंबी के पेड़ पर उसके पर्याप्त उत्पादन से भी कम फलन हुआ है। साथ ही, किसानों ने सरकार से १ लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा की मांग की है।

अब इस राज्य में भी MSP पर होगी धान की खरीदी, सरकार खोलेगी 23 नई मंडियां

खरीफ का सीजन अपने पीक पर है। इस दौरान देश में सबसे ज्यादा धान उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धान की फसल तैयार हो चुकी है। ज्यादातर राज्यों में तो धान की कटाई भी खत्म हो चुकी है और फसल मंडियों में पहुंचने लगी है। इसको देखते हुए कुछ राज्य सरकारें MSP पर धान की खरीदी प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं, जबकि कुछ सरकारें धान को MSP पर 1 अक्टूबर से खरीदना प्रारम्भ करेंगी।

अन्य राज्यों को देखते हुए अब जम्मू और कश्मीर का प्रशासन भी अपने राज्य के किसानों की मदद के लिए आगे आया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने घोषणा की है कि राज्य में धान किसानों की मदद करने के लिए 23 नई मंडियां खोली जाएंगी, जिसमें किसानों को तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, ताकि जम्मू और कश्मीर के किसान बिना किसी परेशानी के अन्य राज्यों के किसानों की तरह अपनी धान की फसल को आसानी से बेच पाएं। राज्य में नई मंडियों की स्थापना करने के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर अपने काम पर लग गए हैं। नई मंडियों की स्थापना और जमीन अधिग्रहण में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किये हैं।

किस जिले में कितनी धान मंडियां होंगी स्थापित

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने बताया कि जो 23 मंडिया स्थापित की जानी है वो जम्मू डिवीजन के अंतर्गत ही स्थापित की जाएंगी, क्योंकि धान की पैदावार इसी डिवीजन में होती है। प्रशासन ने बताया कि 11 मंडियां जम्मू जिले में, 11 मंडियां कठुआ जिले में और एक मंडी सांबा जिले में स्थापित की जाएगी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन के अंतर्गत आने वाला कृषि उत्पादन व किसान कल्याण डिपार्टमेंट ने इसको लेकर कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी सूचना भी सार्वजनिक कर दी जाएगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हुआ तय

राज्य में नई धान मंडियों की घोषणा के साथ ही जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने राज्य के किसानों को तोहफा देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा कर दी है। प्रशासन के अनुसार, राज्य में ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रूपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीदा जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किये हैं, मंडियों में उसी के अनुसार खरीदी की जाएगी।

तीनों जिलों में बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश

जिन जिलों में धान की खरीदी होनी है, उन जिलों में प्रशासन की तरफ से बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी फसल की खरीदी बिना बारदाने के नहीं हो सकती। इसलिए प्रशासन ने उचित मात्रा में बारदाना रखने के निदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने बताया है कि मंडियों में किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए हेल्पडेस्क बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जहां पर एक मंडी कर्मचारी हमेशा तैनात रहेगा। यदि किसानों को फसल बेचने से संबधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो किसान की उस समस्या को हेल्पडेस्क में उपस्थित कर्मचारी नोट करेगा और किसान को त्वरित समाधान प्रदान करने की कोशिश करेगा।

कई राज्यों में जल्द ही शुरू होगी धान की खरीदी

पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने इस साल 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार ने 400 से अधिक मंडियों में धान खरीदी की व्यवस्था की है। मंडियों में खरीदी को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में 1 नवम्बर से धान की खरीदी प्रारम्भ होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए सरकारी अफसर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं।

हाइवे में हजारों ट्रकों के फंसने से लाखों मीट्रिक टन सेब हुआ खराब

जम्मू कश्मीर के सेब (Apple) के किसान पहले ही संकट में हैं और अब हाइवे में जाम लगने के बाद उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इन दिनों जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने वाले मेन हाइवे NH-44 में कुछ दिक्कत आ गई है, जिसके कारण आवागमन सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। इसलिए सेब से लदे सैकड़ों ट्रक बीच में ही फंस गए हैं, जिसके कारण अब तक हजारों क्विंटल सेब खराब हो चुका है। इसका सीधा असर किसानों के ऊपर पड़ रहा है।

चूंकि अब सेब की सप्लाई आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर की मंडियों में सेबों की डिमांड भी कम हो गई है, जिसके कारण सेबों को बेंचने पर किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सेब व्यपारियों का कहना है कि यदि कुछ दिनों में हालात सामान्य नहीं हुए तो और भी ज्यादा सेब खराब हो सकते हैं, जिससे उनका घाटा बढ़ जाएगा। व्यापरियों की मांग है कि सरकार को जल्दी से जल्दी हाइवे की मरम्मत करवाकर आवागमन को बहाल करना चाहिए, ताकि सेब को खराब होने से पहले ही बाजार में पहुंचाया जा सके।

कैसे खराब हुआ इतनी बड़ी मात्रा में सेब ?

इस साल अच्छी बरसात होने के साथ ही अनुकूल मौसम होने की वजह से जम्मू कश्मीर में बम्पर सेब का उत्पादन हुआ है, जिसके कारण मंडियों में सेब की आवक बढ़ गई है। यहीं से सेब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों को भेजा जाता है। लेकिन देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले मुख्य हाइवे पर इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके कारण हजारों की संख्या में सेब ट्रक फंस गए हैं और सेबों की स्थिति खराब होना प्रारम्भ हो चुकी है।

कितनी कीमत का माल लगा है दांव पर ?

जम्मू कश्मीर सेब संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, अभी तक लगभग 8,000 सेब से लदे हुए ट्रक हाइवे में फंसे हुए हैं, जिनमें कम से कम 100 करोड़ रूपये का माल लोड है। ये ट्रक पिछले दो हफ़्तों से एक भी कदम आगे नहीं बढ़े हैं, जिसके कारण इनमें रखा हुआ माल सड़ने लगा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि इन हालातों में और कितने दिनों तक ये ट्रक हाइवे में फंसे रहेंगे। इस साल बम्पर उत्पादन की वजह से जम्मू कश्मीर में सेब का उत्पादन 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुआ है।

जम्मू कश्मीर का सेब उद्योग पहले ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, यहां के सेब किसानों और व्यापारियों को ईरान से आने वाले सेब से घाटा हो रहा है। ईरान से आने वाले सेब के कारण बाजार में कम्पटीशन बढ़ गया है। इसलिए राज्य के सेब व्यापारियों और किसानों ने ईरान से सेब के आयत में प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है। इसके अलावा बाजार ये भी खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाकर रूस के व्यापारी अपना सेब भारत में खपा रहे हैं। बड़ी मात्रा में रूसी सेब अफगानिस्तान होते हुए भारत आ रहा है, हालांकि भारतीय अधकारियों ने इन बातों का खंडन किया है।

भारत दुनिया में सेब का सातवाँ सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपना विशेष स्थान रखता है। भारत में सेब की खेती सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में ही होती है। सेब की खेती से राज्य को हर साल लगभग 1500 करोड़ रूपये की आमदनी होती है। अगर देश में उत्पादित होने वाले सभी फलों की बात की जाए, तो सभी फलों के बीच सेब का शेयर 3 प्रतिशत के आस पास है। इसलिए सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी हाइवे की मरम्मत करवाई जाए और आवागमन को बहाल किया जाए, ताकि किसानों तथा सेब व्यापारियों को लग रहे घाटे को कम किया जा सके।

राजस्थान में लंपी के वेरिएंट बदलने की आशंका से पशुपालको में चिंता

आजकल पशुओं में लंपी स्किन रोग यानी 'लम्पी स्किन डिजीज' या एलएसडी (LSD – Lumpy Skin Disease) किसान व पशुपालकों के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते लोग दूध का सेवन तक कम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश के कई राज्य लंपी स्किन रोग की चपेट में आ गए हैं।

हाल ही में राजस्थान सूबे के पशुपालन मंत्री लालचंद्र कटारिया ने लंपी रोग के वेरिएंट बदलने की सम्भावना व्यक्त की है, जिससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार ५०० पशु एम्बुलेंस खरीदने व पशु चिकित्सा केंद्र को सुचारु एवं मजबूत बनाने की पुरजोर तैयारी में है। क्योंकि पहले लंपी स्किन रोग सिर्फ गोवंश में ही था, लेकिन अब भैंस भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं, इसलिए राज्य सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है।

पशुपालन मंत्री लालचंद्र कटारिया जी ने ये भी बताया कि राजस्थान सरकार गोवंश का मुफ्त में टीकाकरण तेज़ी से करा रही है एवं पशुओं में लम्पी रोग की तबाही को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु चिकित्सा केंद्रों पर औषधी का पर्याप्त बंदोबस्त भी किया है। पशुपालकों को इससे काफी सहायता प्राप्त होगी और इस रोग से निपटने में भी सहजता होगी। हालाँकि भैसों में इस रोग के पाए जाने से पशुपालक व किसान दोनों की ही समस्या बढ़ गयी है। पशुपालन विभाग भी इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है।

राजस्थान सरकार ने ३० करोड़ की राशि पशु चिकित्सा सुविधा के लिए जारी की

लंपी स्किन रोग से निवारण के लिए सरकार ने पशु चिकित्सा केंद्रों के लिए ३० करोड़ की धन राशि जारी की है, जो कि सहजता से इस रोग से निपटने में काफी हद तक मदद करेगी और पशुपालकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उनके रोगग्रस्त पशुओं को पशु चिकित्सा केंद्र ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। पशुपालक सरकार के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा कर रहे हैं।

चिकित्सा केंद्र में कितनी भर्तियां होने की सम्भावना है

तेज़ी से फैलने वाले इस संक्रामक लंपी रोग से निपटने के लिए अधिक मात्रा में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अनुरूप सरकार ने अर्जेंट टेम्परारी बेसिस पर काफी नियुक्तियां की है एवं अभी और नियुक्ति करने के विचार में है, क्योंकि पशुओं को लंपी स्किन रोग तीव्रता से चपेट में लेता जा रहा है। उपरोक्त में जैसा बताया गया है कि इसने भैंसों में भी अपनी दस्तक दे दी है, इसके चलते पशु चिकित्सा केंद्रों में पशुधन सहायक व पशु चिकित्सक दोनों की आवश्यक पड़ेगी, इसलिए सरकार द्वारा ३०० पशुधन सहायकों की भर्ती की जा रही है।

गोवंश टीकाकरण को लेकर राजस्थान की रणनीति क्या है

राजस्थान राज्य सरकार ने लंपी स्किन रोग की दस्तक की खबर से ही गंभीरता पूर्वक गोवंश टीकाकरण करना सुचारु रूप से शुरू करा दी थी, साथ ही पशुओं के लिए प्रयाप्त मात्रा में औषधि और पशु चिकित्सकों का प्रबंध भी कर चुकी है। इसके साथ ही गोट पॉक्स टीकाकरण का पूरा खर्चा राज्य सरकार खुद ही वहन कर रही है। हालाँकि केंद्र सरकार से भी इस चिंताजनक पशु रोग से सम्बंधित मदद के लिए राजस्थान सरकार परस्पर वार्ता में है।

भारत सरकार के सामने नई चुनौती, प्रमुख फसलों के उत्पादन में विगत वर्ष की अपेक्षा हो सकती है कमी

फिलहाल भारत सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, इस साल खरीफ और रबी की फसलों में भारी कमी होने की संभावना है, इसका कारण है कई जगहों पर वर्षा की असमानता। इस साल कई राज्यों के कई क्षेत्रों में या तो औसत से ज्यादा बरसात हुई है या औसत से बहुत कम वर्षा हुई है, जिसका असर सीधा फसलों के उत्पादन में पड़ रहा है। औसत से ज्यादा बरसात वाले क्षेत्रों में फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, कई जगह फसलें सड़ के पूरी तरह से चौपट हो गई हैं, तो कई जगह सूखे की वजह से फ़सलों की वैसी ग्रोथ नहीं हुई है जैसी उम्मीद की जा रही थी। हरियाणा और पंजाब में कम बरसात की वजह से एक बहुत बड़े रकबे की धान की खेती अविकसित रह गई है। इसलिए नीति निर्माताओं का अनुमान है कि 2022-23 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है, जिसका असर भारत के सामान्य लोगों पर पड़ेगा। अगर तय लक्ष्य के मुताबिक़ फसलों का उत्पादन नहीं हुआ तो बाजार में अनाज की कमी हो जाएगी, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम में बढ़ोत्तरी हो सकती है, जो सरकार के लिए एक नया सिरदर्द है। सरकार को इससे निपटने के लिए जल्द से जल्द योजना बनाने की जरुरत है।

यूपी, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में इस साल बेहद कम बरसात हुई है, जिसका असर खरीफ की खेती पर पड़ना तय है। यह क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस साल कम वर्षा के कारण यहां पर चावल के उत्पादन में भारी कमी हो सकती है, इस सीजन में इन राज्यों में कम से कम 11 मिलियन टन चावल के उत्पादन में कमी हो सकती है। पिछले साल इन राज्यों में चावल का कुल उत्पादन 111.8 मिलियन टन था, इस साल घटकर 100-102 मिलियन टन होने की संभावना है, इसको देखते ही सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है, इसलिए सरकार ने पहले गैर-बासमती चावल निर्यात (chawal niryat) पर प्रतिबन्ध लगाया उसके बाद टुकड़ा चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

चावल के अतिरिक्त कपास के उत्पादन में भी भारी कमी की संभावना है, क्योंकि इस खेती में भी असमान वर्षा और मौसम की मार पड़ी है, जिससे कपास की खेती भी प्रभावित हुई है। कपास के उत्पादन में कमी घरेलू कपड़ा उद्योग को प्रभावित करेगी। उत्पादन की कमी के कारण बाजार में कपास महंगा हो सकता है जिसका सीधा असर कपड़ा बनाने में आने वाली लागत पर पडेगा। आगामी वर्ष में कपड़ा उत्पादन की लागत बढ़ भी सकती है।

बिहार में खाद की भयंकर कमी, मांग के मुकाबले यूरिया की आपूर्ति में 22 फीसदी की कमी

1 अप्रैल से 12 सितंबर के बीच, बिहार सरकार को बिहार कृषि विभाग से जानकारी मिली कि बिहार को खरीफ सीजन के लिए 10,100 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अब तक केंद्र सरकार ने सिर्फ 7.89576 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की है।

खरीफ फसल का मौसम चल रहा है। खरीफ मौसम की मुख्य फसल धान देशभर में उगाई जाती है। वहीं, इस सीजन में खाद की मांग सबसे ज्यादा होती है। बिहार में इस खरीफ सीजन में खाद की आपूर्ति नही होना किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इससे किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार को खरीफ सीजन के दौरान पिछले सालों की तुलना में यूरिया का आबंटन बहुत ही कम किया है। बिहार सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार ने पीक सीजन (जून से अगस्त) के दौरान उपयोग के लिए आबंटित यूरिया की मात्रा को 22 फ़ीसदी कम कर दिया है।

इतने खाद की है आवश्यकता

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार को खरीफ सीजन 1 अप्रैल से 12 सितंबर तक 10.100 मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष अब तक 7.89576 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की है, जो आवश्यकता अनुपात का 78% है।

बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में 1.20 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 1.03 लाख मीट्रिक टन खाद दी गई. इसी प्रकार जुलाई में 2.50 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, लेकिन जुलाई में 1.72 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई, और अगस्त में 2.80 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 2.51 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई।

पिछले खरीफ सीजन के दौरान भी कम आपूर्ति देखी गई थी। पिछले खरीफ सीजन में बिहार सहित कई क्षेत्रों में उर्वरक की भारी किल्लत थी। इसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी बिहार के लिए जरूरी यूरिया का महज 77 फीसदी ही मुहैया कराया गया था।

बिहार के दौरे के दौरान, केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने नीतीश कुमार पर केंद्र से लगातार और पर्याप्त शिपमेंट के बावजूद उर्वरक की कमी का नाटक करने का आरोप लगाया है। उर्वरक राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा की नीतीश कुमार को किसानों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा कार्य किया है। किसानों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा की वे यूरिया खरीदारी पर दर से अधिक पैसा न दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की खातिर यूरिया, डीएपी, एनपीके और अन्य कृषि आदानों पर भारी सब्सिडी दे रही है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि सरकार को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसानों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। प्रशासकों को किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के उपयोग के उनके अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए निर्देश भी दिए जाते हैं।

फसल खराब होने पर किसानों को मिली क्षतिपूर्ति, सरकार ने जारी की 3 हजार 500 करोड़ की मुआवजा राशि

इस साल भारी बरसात के कारण महाराष्ट्र की फसलों को कई प्रकार का नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बरसात के साथ-साथ कीटों के भीषण प्रकोप से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गईं हैं। इसको देखते हुए पिछले कई दिनों से राज्य के किसान, सरकार से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे। अंततः किसानों की यह मांग सरकार तक पहुंच गई है।

राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने मुआवजा के तौर पर 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जो प्रभावी किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस राशि का वितरण 15 सितम्बर से प्रारम्भ हो चुका है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में इस प्रकार की मुआवजा राशि के वितरण में काफी धांधली हुई थी। लेकिन इस बार राज्य की शिंदे सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए किसानों को हुई क्षति की भरपाई की जा रही है। राज्य सरकार किसानों के लिए मुआवजा राशि जारी करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस राशि को सहायता राशि के तौर पर किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, सभी जिला अधिकारियों ने किसानों का पैसा उनके बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, जो जल्द ही किसानों को मिल जाएगा। उनकी सरकार किसानों के खातिर केंद्र सरकार से ऑनलाइन ई-पीक निरीक्षण में बदलाव करने की मांग भी करेगी। सत्तार ने एकनाथ शिंदे सरकार को किसानों का हितैषी बताया, साथ ही कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किसानों की सभी प्रकार की समस्याएं सुलझाने में सक्षम हैं।

इस बार की खरीफ फसल के दौरान हुई बरसात ने किसानों की फसलों में भारी नुकसान पहुंचाया है, रही सही कसर घोंघों ने पूरी कर दी है। घोंघों ने भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण राज्य में फसलें चौपट हो गईं हैं।

अगर हम हम फसलों के नुकसान का जिलेवार आंकलन करें तो सबसे ज्यादा नुकसान लातूर, उस्मानाबाद और बीड जिलों में उगाई गई फसलों को हुआ है। इन जिलों में फसलों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तो पहले ज्यादा बरसात की वजह से यहां की फसलें चौपट हो गईं हैं, बाकी रही सही कसर घोंघों ने पूरी कर दी है। इन जिलों में किसानों की स्थित को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन 3 जिलों के लिए 98 करोड़ 58 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की है, जिसे यहां के प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया जा रहा है ताकि नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके।

इसके साथ ही कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार राज्य में प्रगति लाने के लिए आधुनिक कृषि पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्रों से अवगत करवाया जा सके। इससे फायदा यह होगा कि किसान कम समय में, कम लागत के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, जिससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जो भी किसान आधुनिक कृषि को अपनाएं वो अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती के महत्व को समझाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्रकार खेती करके लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा, सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी गांव के अंतिम किसान तक पहुंचे, ताकि हर किसान इस तरह के कृषि यंत्रों और तकनीक से लाभान्वित हो सके, जिससे किसानों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हो और राज्य का किसान खुश रहे।

पराली मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने उठाये आवश्यक कदम, तीन राज्यों को दिए 600 करोड़ रुपये

खरीफ का सीजन चरम पर है, देश के ज्यादातर हिस्सों में खरीफ की फसल तैयार हो चुकी है। कुछ हिस्सों में खरीफ की कटाई भी शुरू हो चुकी है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगी और किसान अपनी फसल घर ले जा पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या किसान अपने खेत में ही छोड़कर चले जाते हैं, जो आगे जाकर दूसरों का सिरदर्द बनती है, वो है पराली (यानी फसल अवशेष or Crop residue)।

पराली एक ऐसा अवशेष है जो ज्यादातर धान की फसल के बाद निर्मित होता है। चूंकि किसानों को इस पराली की कोई ख़ास जरुरत नहीं होती, इसलिए किसान इस पराली को व्यर्थ समझकर खेत में ही छोड़ देते हैं। कुछ दिनों तक सूखने के बाद इसमें आग लगा देते हैं ताकि अगली फसल के लिए खेत को फिर से तैयार कर सकें। पराली में आग लगाने से किसानों की समस्या का समाधान तो हो जाता है, लेकिन अन्य लोगों को इससे दूसरे प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसके कारण लोग पराली जलाने (stubble burning) के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की मांग लम्बे समय से कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर भारत में ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा में जो भी पराली जलाई जाती है, उसका धुआं कुछ दिनों बाद दिल्ली तक आ जाता है, जिसके कारण दिल्ली में वायु प्रदुषण के स्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी होती है। इससे लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पराली के प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

पराली की वजह से लोगों को लगातार हो रही समस्याओं को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग-अलग स्तर कई प्रयास किये हैं, जिनमें पराली का उचित प्रबंधन करने की भरपूर कोशिश की गई है ताकि किसान पराली जलाना बंद कर दें।

इस साल भी खरीफ का सीजन आते ही केंद्र सरकार ने पराली के मैनेजमेंट (फसल अवशेष प्रबन्धन) को लेकर कमर कस ली है, जिसके लिए अब सरकार एक्टिव मोड में काम कर रही है। अभी तक सरकार दिल्ली के आस पास तीन राज्यों के लिए पराली प्रबंधन के मद्देनजर 600 करोड़ रुपये का फंड आवंटित कर चुकी है। यह फंड हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली मैनेजमेंट के लिए जारी किया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली मैनेजमेंट के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में बताया कि, पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार ने पराली से छुटकारा पाने के लिए किसानों को 2.07 लाख मशीनों का वितरण किया है। जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को वितरित की गईं हैं। बैठक में तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के द्वारा पराली जलाने को लेकर बेहद चिंतित है।

पराली मैनेजमेंट के मामले में राज्यों की सफलता तभी मानी जाएगी जब हर राज्य में पराली जलाने के मामले शून्य हो जाएं, यह एक आदर्श स्थिति होगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य सरकारों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने यहां के किसानों को पराली मैनेजमेंट के प्रति जागरूक करना होगा, ताकि किसान पराली जलाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को गंभीरता से समझ पाएं।

बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि पराली जलाने के बेहद नकारात्मक परिणाम हमारे पर्यावरण के ऊपर भी होते हैं। ये परिणाम अंततः लोगों के ऊपर भारी पड़ते हैं। ऐसे में राज्यों के जिलाधिकारियों को उच्चस्तरीय कार्ययोजना बनाने की जरुरत है, ताकि एक निश्चित अवधि में ही इस समस्या को देश से ख़त्म किया जा सके। मंत्री ने कहा कि राज्यों को और उनके अधिकारियों को गंभीरता से इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए कि इसका समस्या का त्वरित समाधान कैसे किया जा सकता है।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हमें वेस्ट को वेल्थ में बदलने की जरुरत है, यदि किसानों को यह समझ में आ जाएगा कि पराली के माध्यम से कुछ रुपये भी कमाए जा सकते हैं, तो किसान जल्द ही पराली जलाना छोड़ देंगे। इसलिए कृषि अधिकारियों को चाहिए कि पूसा संस्थान द्वारा तैयार बायो-डीकंपोजर के बारे में किसानों को बताएं। जहां भी पूसा संस्थान द्वारा तैयार बायो-डीकंपोजर लगा हुआ है वहां किसानों को ले जाकर उसका अवलोकन करवाना चाहिए, साथ ही इसके अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दें, जिससे किसानों को यह पता चल सके कि पराली के द्वारा उन्हें किस प्रकार से लाभ हो सकता है।

औषधीय खेती

ईसबगोल को जैविक खाद से तैयार करने पर दोगुनी हो गई गुजरात के किसानों की आय

विश्व में इसबगोल (Isabgol or Psyllium husk (सिलियम)) के उत्पादन तथा निर्यात में शीर्ष पर विराजमान भारत के किसान, अब जैविक खेती की मदद लेकर अपनी आय को दोगुना करने में सफल हो रहे हैं।

वर्तमान में भारत में प्रति वर्ष लगभग एक लाख टन इसबगोल उत्पादन किया जाता है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में इसबगोल की उत्पादकता 700 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भी अधिक हो रही है।

गुजरात और राजस्थान के किसान भाईयों ने अब धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक पदार्थों का इस्तेमाल कर उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही अपनी आय को सुधारने में भी सफलता हासिल की है।

वर्तमान में भारत में उत्पादित किया जा रहा ईसबगोल, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को 1800 से 2000 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, लेकिन किसानों को केवल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ही भुगतान किया जाता है, सामान को कम्पनियों तक पहुंचाने वाले एजेंट ही सारा मुनाफा कमा लेते हैं।

क्या है इसबगोल और इसका इस्तेमाल ?

इसबगोल के बीजों में एक छिलके के जैसा पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल औषधीय तत्व के रूप में किया जाता है। इस बीज को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग करने से पेट में कब्ज और गर्मी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
इसके अलावा डायरिया और पेचिश जैसे रोगों को दूर करने में भी इसबगोल का आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

इसबगोल उत्पादन के लिए आवश्यक मृदा और जलवायु :

रबी के मौसम में उगाई जाने वाली इस फसल के लिए ठंडी जलवायुवीय स्थितियों की आवश्यकता होती है। फसल के उत्पादन से पहले किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि कम नमी की मात्रा वाले क्षेत्रों में इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक होता है।

अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह या नवंबर की शुरुआती सप्ताह में इसबगोल की बुवाई की जाती है।

7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा इसबगोल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, वर्तमान में भारतीय किसान 'दोमट बलुई मृदा' से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर पा रहे हैं।

इसबगोल उत्पादन के लिए कैसे तैयार करें

राजस्थान के बाड़मेर जिले में रहने वाले किसान विश्वप्रसाद बताते हैं कि वर्तमान में वह ट्राइकोडर्मा (Trichoderma) नाम के फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर बीजों का बेहतर उपचार कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी और प्रदूषण रहित सुरक्षित फफूंदनाशी होता है, वर्तमान में कृषि वैज्ञानिक इसे जैविक श्रेणी में शामिल करते हैं।

बेहतर बीज उपचार के लिए शुरुआत में इसबगोल के बीजों को पानी में डुबोकर गीला किया जाता है और उन्हें ट्राइकोडरमा के साथ तैयार किए गए एक घोल में मिलाकर कुछ समय के लिए रख देना चाहिए। एक किलोग्राम ट्राइकोडरमा के घोल में 25 किलोग्राम जैविक खाद को मिला करें एक एकड़ में इस्तेमाल होने वाले बीजों का उपचार किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया की मदद से इसबगोल के पौधों में होने वाले तनागलन और कई अन्य रोगों से सफलतापूर्वक निदान पाया जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के से जुड़ी एक गैर सरकारी संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार इसबगोल के प्रति हैक्टेयर के क्षेत्र में उत्पादन करने में लगभग पन्द्रह हज़ार रुपए का खर्चा आता है और वर्तमान बाजार दर से को आधार मानकर किसान एक लाख रुपये तक कि उपज प्राप्त कर सकते हैं।

किसान विश्वप्रसाद बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने अस्सी हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुनाफा कमाया है।

वर्तमान में लोकप्रिय इसबगोल की उन्नत किस्में :

वर्तमान में भारतीय किसान परिपक्वता की अवधि के आधार पर इसबगोल की अलग-अलग किस्म का उत्पादन करना पसंद करते हैं।

पूसा के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाई गयी कुछ इसबगोल की कुछ उन्नत किस्में जैसे कि आर.आई.-89 (R. I.- 89) नामक किस्म 110 से 120 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इस किस्म से प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से 15 क्विंटल तक इसबगोल का उत्पादन किया जा सकता है।

इसके अलावा एम आई जी -2 (MIG-2) नाम की किस्म तीन से चार सिंचाईयों में ही पक कर तैयार हो जाती है।

यह किस्म सर्वाधिक उत्पादन देती है और इसकी मदद से प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में सामान्यतः 18 क्विंटल से भी अधिक औसत उपज प्राप्त की जा सकती है।

इसबगोल उत्पादन के दौरान कैसे करें खाद एवं उर्वरकों का बेहतर प्रबंधन तथा सिंचाई योजना :

वर्तमान में इसबगोल उत्पादन में एक सफल किसान के रूप में उभरे गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में रहने वाले किसान जैविक खाद अर्थात गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना सर्वोत्तम मानते हैं। अधिक पैदावार के लिए किसान मृदा परीक्षण की मदद से पोषक तत्वों की भी समय पर जांच करवा रहे हैं।

इस फसल के उत्पादन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वर्तमान में डिजिटल तकनीकों की मदद से किसानी क्षेत्र में मुनाफा कमाने वाले किसान एजेटॉबेक्टर कल्चर (Azotobacter culture) की मदद से भी बीजों का उपचार कर रहे हैं, जिससे नाइट्रोजन जैसे उर्वरक को खरीदने में आने वाली लागत को कम किया जा सकता है।

इसबगोल की फसल की सिंचाई योजना के दौरान बुवाई के तुरंत बाद ही पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल का अंकुरण शुरू होने से पहले पानी का सीमित प्रयोग ही बेहतर उत्पादकता देता है।

इसबगोल के एक सीजन को तैयार होने में लगभग तीन से चार सिंचाईयों की आवश्यकता होती है।

किसान भाई अपनी सहूलियत के अनुसार बुवाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करने के पश्चात अगली सिंचाई 35 दिनों के अंतराल के बाद कर सकते हैं।

इसबगोल की फसल में होने वाले रोग और उनका उपचार :

भारतीय क्षेत्र की जलवायु के अनुसार वर्तमान में इसबगोल में मृदुरोमिल नामक एक फफूंद मुख्य रोग के रूप में देखा जाता है।

इस रोग की निशानी के रूप में पत्तियों में सबसे पहले धब्बे के जैसे आकार दिखाई देना शुरू होता है, इसके बाद यह पूरी पत्ती पर फैल कर उसे नष्ट कर देते हैं। अधिक नमी वाले स्थानों पर इस रोग के प्रभाव अधिक भी हो सकते हैं।

इस फफूंद का प्रभाव कम करने के लिए खड़ी फसल पर लकड़ी के बुरादे से तैयार हुई राख का छिड़काव करना चाहिए।

इसके अलावा जैविक कृषि से तैयार नीम के पत्तियों को पीस कर एक जैविक कीट घोल बनाकर समय-समय पर इसबगोल की फसल पर छिड़काव करना चाहिए।

भारतीय बाजार में बढ़ी पिपरमिंट ऑयल की मांग, ऐसे करें पिपरमिंट की खेती

भारतीय बाजार में पिपरमिंट की मांग लगातार बढ़ रही है, किसान बदलते समय के साथ पारंपरिक फसलों के साथ-साथ आधुनिक खेती करने का तरीका भी खूब सीख रहे हैं, और नए नए प्रयोग करके फसलों, फलों व सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी पिपरमिंट (Peppermint; वैज्ञानिक नाम – मेंथा-पिपरिता; Mentha piperita Linn; मेंथा; Mentha) की खेती करके भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो पढ़िए कैसे करते हैं पिपरमेंट की खेती। पिपरमेंट या पिपरमिंट बेहतरीन पौधों में से एक है, जिसकी पैदावार करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।

ऐसे करें पिपरमिंट की खेती (Peppermint Farming)

पिपरमिंट को देसी भाषा मे मेंथा या पिपरमेंट भी कहा जाता है, यह क्रैश क्रॉप फसलों की श्रेणी में आती है। पिपरमिंट का पौधा दिखने में पुदीना जैसा दिखाई देता है। जनवरी से फरवरी महीने के बीच पिपरमेंट की खेती करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन दिनों की जलवायु पिपरमिंट के लिए काफी बेहतर होती है।

पिपरमिंट की खेती के लिए बलुई दोमट अथवा मटियारी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, खेत को समतल करके अच्छे से जुताई करें। इसके बाद मिट्टी में 20 से 25 टन देसी गोबर से बनी खाद डाल दें, इससे मिट्टी अच्छी तरह नम और उपजाऊ बन जाये। ततपश्चात तैयार खेत मे पिपरमिंट के पौधों की रोपाई की जाएगी, पौध लगाने के तुरंत बाद खेत मे हल्के पानी के साथ सिंचाई करनी चाहिए।

जलजमाव नहीं होना चाहिए

पिपरमिंट की खेती के लिए खेत को इस तरह तैयार करें कि उस खेत में जलभराव नहीं होना चाहिए। खेत में जलनिकासी की व्यवस्था पहले ही कर लें।

पहाड़ी अथवा जंगली जमीन पर नहीं होगा पिपरमिंट
पिपरमिंट की खेती के लिए समतल जगह होनी चाहिए, पहाड़ी अथवा जंगली जमीन पर पिपरमिंट की खेती नहीं हो सकती है। अधिक ठंड वाले स्थानों पर भी पिपरमिंट की खेती करना संभव नहीं है। जहां बर्फ या पाला पड़ता है, ऐसे स्थानों पर पिपरमिंट का पौधा विकास नहीं कर पाता है। हालांकि कुछ ठंड के इलाकों में मार्च महीने में पिपरमिंट की पौध लगाई जा सकती है।

100 दिन के अंदर मिल जाता है पूरा उत्पादन

पिपरमिंट की फसल की केवल 40 से 50 दिन में ही कटाई शुरू हो जाती है, दूसरी कटाई 60 से 70 दिन के बीच हो जानी चाहिए। इस तरह कुल 100 दिन के अंदर पिपरमिंट की फसल का पूरा उत्पादन मिल जाता है।

पिपरमिंट के तेल की मांग

पिपरमिंट की खेती करना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाज़ार में इस पौधे से निकलने वाले तेल की मांग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यह पौधा और भी कीमती हो जाता है। अगर आप 1 बीघा जमीन में पिपरमिंट की खेती करते हैं, तो उसके पौधों से लगभग 20 से 25 लीटर या उससे ज्यादा तेल निकल सकता है।

पिपरमिंट के तेल की कीमत

भारतीय बाज़ार में एक लीटर पिपरमिंट तेल की कीमत लगभग 2 हजार से 3 हजार रुपए के बीच है, ऐसे में किसान 20 से 25 लीटर तेल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पिपरमिंट की खेती से लेकर उसकी पेराई तक, प्रति लीटर पिपरमिंट आयल के उत्पादन पर लगभग 500 रुपए लागत आती है, जबकि मार्केट में पिपरमिंट तेल की कीमत लागत से दोगुना है।

पिपरमिंट तेल का इस्तेमाल

पिपरमिंट तेल (peppermint oil) का इस्तेमाल एक दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस तेल में मेन्थोन, मेंथाल और मिथाइल जैसे एसीटेट पाए जाते हैं, जो सिर दर्द, कमर दर्द समेत घुटनों के दर्द और सांस सम्बंधी समस्याओं को दूर करने मददगार साबित होते हैं।

इसके अतिरिक्त पिपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए भी किया जाता है, जिससे कई प्रकार की क्रीम और साबुन इत्यादि तैयार किए जाते हैं। पिपरमिंट ऑयल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेय पदार्थ, पर्फ्यूम और पान मसाला बनाने के लिए भी किया जाता है।

यही कारण हैं कि भारतीय बाज़ार में पिपरमिंट ऑयल की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से किसान इस पौधे की खेती करने में रूचि ले रहे हैं। पिपरमिंट की फसल को दो बार काटकर उससे तेल निकाला जा सकता है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है।

पशुपालन-पशुचारा

ये राज्य सरकार दे रही है पशुओं की खरीद पर भारी सब्सिडी, महिलाओं को 90% तक मिल सकता है अनुदान

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पशुपालन का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में काफी फल फूल रहा है क्योंकि भारत के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन के व्यवसाय के लिए ज्यादातर सुविधाएं प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। इसलिए यह व्यवसाय ग्रामीणों की दशा और दिशा दोनों को बदल रहा है। गावों में अब लोग दूध के साथ विभिन्न चीजों की प्राप्ति के लिए पशुपालन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि सरकार भी अब पशुपालकों और किसानों को पशुपालन में मदद करने लगी है ताकि लोग इस व्यवसाय की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, यह व्यवसाय छोटे और मध्यम किसानों के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

केंद्र सरकारों के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अब इस दिशा में प्रयास कर रही हैं ताकि ग्रामीण किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके। इसको देखते हुए झारखण्ड की सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना (Mukhyamantri Pashudhan Yojana Jharkhand) शुरू की है, इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों और किसानों को पशुओं की खरीद पर 75 से लेकर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी से निश्चित तौर पर गावों के निचले तबके के लोगों को लाभ होने वाला है।

गाय-भैंस की खरीद पर इस प्रकार से सब्सिडी देती है सरकार

झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आपदा, आगजनी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को सरकार गाय-भैंस खरीदने में सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे वो कुछ कमाई कर पाएं और अपना जीवन यापन कर पाएं। इसके तहत इन लोगों को सरकार 2 गाय या 2 भैंस खरीदने के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके पहले इन पात्र लोगों को मात्र 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है।

गाय-भैंस के अतिरिक्त इन पशुओं की खरीद पर भी सब्सिडी देती है सरकार

झारखंड के पशुपालन निदेशालय के अनुसार, राज्य के लोगों को सरकार बकरी पालन, सूअर पालन, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, ब्रायलर कुक्कुट पालन (ब्रायलर मुर्गी पालन) और बत्तख चूजा पालन के लिए 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। पहले यह सब्सिडी 50% दी जाती थी, लेकिन अब इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है।

मिनी डेयरी के लिए भी मिलेगा अनुदान

राज्य में कोई भी किसान या पशुपालक यदि 5 दुधारू गाय/भैंस या 10 गाय/भैंस के साथ मिनी डेयरी खोलना चाहता है, तो उसे कामधेनु डेयरी फार्मिंग की उपयोजना के तहत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मिनी डेयरी खोलने के लिए सरकार सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों को अब 50 प्रतिशत तक का अनुदान देगी। पहले यह राशि मात्र 25 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। साथ ही यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का किसान या पशुपालक मिनी डेयरी खोलना चाहता है, तो उसे सरकार अब 75 प्रतिशत की राशि सब्सिडी के रूप में देगी। पहले यह राशि 33.33 प्रतिशत थी।

चैफ कटर का वितरण पर भी मिलेगा किसानों को अनुदान

पशुओं के लिए किसान अच्छे से अच्छे चारे का प्रबंध कर पाएं, इसको देखते हुए सरकार ने चारा/घास काटने वाली मशीन यानि चाफ कटर (Chaff cutter) का वितरण पर भी सब्सिडी प्रदान करने का निश्चय किया है। इसके वितरण में सरकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं अन्य वर्गों के किसानों के लिए सरकार हस्तचालित चैफ कटर का वितरण योजना के अंतर्गत 75% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।

डेयरी प्रोसेसिंग के लिए भी अनुदान देगी झारखंड सरकार

ऐसे किसान जो पशुपालन के साथ ही डेयरी प्रोसेसिंग यानि दुग्ध प्रसंस्करण के धंधे में उतरना चाहते हैं, उनके लिए भी झारखण्ड सरकार अनुदान प्रदान करने जा रही है। यह अनुदान मिल्किंग मशीन, पनीर खोवा मशीन, बोरिंग एवं काऊ मैट आदि की खरीद पर दिया जाएगा।

डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए राज्य सरकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसानों और दुग्ध उत्पादक समितियों के मालिकों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा देगी। जबकि सामान्य, पिछड़ा, महिला और अन्य सभी वर्ग के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक समितियों के मालिकों को सरकार 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी।

मधुमक्खी पालन को बनाएं आय का स्थायी स्रोत : बी-फार्मिंग की सम्पूर्ण जानकारी और सरकारी योजनाएं

जब भी हम कभी मधुमक्खी (मधुमक्षी / Madhumakkhi / Honeybee) का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में मधु या शहद (अंग्रेज़ी:Honey हनी) का ख्याल जरूर आता है, जैसे की लोकप्रिय वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था-

"यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएगी तो अगले 3 से 4 वर्षों में मानव प्रजाति भी खत्म हो जाएगी "

इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की आय में बढ़ोतरी और प्रजाति के संरक्षण के लिए कृषि और पशु वैज्ञानिक निरंतर मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 (Economic survey 2021-22) के अनुसार भारत में शहद का मार्केट लगभग 21 बिलियन रुपए का है, जो कि 2027 तक 40 बिलियन रुपए होने का अनुमान है। इतने बड़े वैल्यू मार्केट को सही समय पर सही तकनीक का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है।

क्या होता है मधुमक्खी पालन (Bee-Farming) :

भारत के प्राचीन कालीन इतिहास से ही कई जनजातियां एवं जंगलों में रहने वाले किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, हाल ही में शहद की बढ़ती डिमांड की वजह से इस क्षेत्र में कई युवा किसानों की रुचि भी बढ़ी है।

मधुमक्खी पालन को 'एपीकल्चर' (Apiculture) के नाम से भी जाना जाता है।

वर्तमान में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मधुमक्खियों के लिए अलग-अलग डिजाइन के छत्ते (honeycomb / beehive; बीहाइव) तैयार किए जा रहे हैं और इन्हीं कॉम्ब में मधुमक्खियों को रखा जाता है, जो आस पास में ही स्थित फूलों से शहद इकट्ठा कर छत्ते में जमा करती है, जिसे बाद में एकत्रित कर बाजार में बेचा जाता है।

मधुमक्खी पालन से होने वाले फायदे :

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार मधुमक्खी पालन से ना केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि इस मधुमक्खी पालन वाले स्थान के आसपास स्थित खेत में मक्खियों के द्वारा परागण या पोलिनेशन (Pollination) करने की वजह से खेत से उगायी गयी फसल की उपज भी अधिक प्राप्त होती है।

मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले उत्पाद :

मुख्यतः मधुमक्खी पालन शहद प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है, मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक शहद में कई प्रकार की औषधीय गुण होते हैं और इसे मानवीय शरीर में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है।

मधुमक्खी वैक्स (मोम; Beeswax) :
आपने अपने घर में कई बार मोमबत्ती का इस्तेमाल किया होगा, यह मोमबत्ती मधुमक्खी पालन से ही प्राप्त एक उत्पाद होता है। वर्तमान में बढ़ती मोम की डिमांड भी किसानों को अच्छा मुनाफा दे रही है।

इसके अलावा इस वैक्स का इस्तेमाल कई प्रकार के फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक व्यवसाय में भी किया जाता है।

मधुमक्खी जहर (Bee-Venom) :
जब मधुमक्खियां अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारती है, तो उनके शरीर में पाया जाने वाला वेनम (venom) यानि जहर हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे सूजन और मांसपेशियों में दर्द होता है।

आधुनिक तकनीक की मदद से अब इस इस वेनम को भी मधुमक्खियों से प्राप्त किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल आर्थराइटिस यानी गठिया (arthritis) जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में किया जाता है और जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए होने वाली एपिथेरेपी (Apitherapy) में भी इस उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है।

रॉयल जेली (Royal Jelly) :
मधुमक्खी पालन से ही प्राप्त होने वाला यह उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है और इससे बनने वाली दवाइयों का इस्तेमाल फर्टिलिटी (Fertility) से जुड़े रोगों के इलाज के लिए किया जाता है।

सुपरफूड के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला यह उत्पाद कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा खरीदा जा रहा है।

भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र के कई किसान रॉयल जैली को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।

मधुमक्खी के द्वारा तैयार किया गया छत्ता गोंद (Propolis) :
इसे मधुमक्खियों के घर के रूप में जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब के कुछ आधुनिक किसानों के लिए मधुमक्खी का छत्ता भी आय का अच्छा स्रोत बन कर सामने आया है। इसका इस्तेमाल गोंद बनाने में किया जाता है, जिससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है।

ऊपर बताए गए इन सभी उत्पादों के अलावा भी मधुमक्खियों से कई दूसरे प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जोकि मधुमक्खियों के संरक्षण में किए जा रहे प्रयासों की सुदृढ़ता तो बढ़ाते ही है, साथ ही लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा किसानी परिवार को भी मदद प्रदान करते हैं।

बड़ी ब्रांड की कंपनियों का शहद वर्तमान में पन्द्रह सौ रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है और इसकी मांग भविष्य में और तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं, इसीलिए समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए किसान भाई भी नीचे बताए गए तरीके से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं :

कैसे करें मधुमक्खी की प्रजाति का चयन ?

अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार मधुमक्खी की अलग-अलग प्रजातियों का पालन किया जाता है, ऐसी ही कुछ प्रजातियां निम्न प्रकार है :-

यूरोपियन मधुमक्खी (European Bees) :
इस प्रकार के मधुमक्खी को पालने पर एक कॉलोनी से लगभग 25 से 30 किलोग्राम शहद इकट्ठा किया जा सकता है।

यह मधुमक्खी मुख्यतः पतझड़ मौसम के समय ज्यादा उत्पादन देती है।
भारतीय मधुमक्खी (Indian or Asian Bees) :
मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति ज्यादातर इसी मधुमक्खी को पालते हैं।

हालांकि इस प्रजाति की एक कॉलोनी में 6 से 8 किलोग्राम शहद ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका पालन करना आर्थिक रूप से कम दबाव वाला होता है।

स्टिंग्लेस मधुमक्खी (Stingless Bees) :
कम प्रति व्यक्ति आय वाले किसान भाई दवाइयां बनाने में इस्तेमाल आने वाले शहद और छत्ते के उत्पादन के लिए इस मधुमक्खी का पालन करते हैं।

यह मधुमक्खी एक बेहतरीन पोलिनेटर के रूप में भी काम करती है और इसके छत्ते के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों और फसलों को फायदा पहुंचाती है।

इसके अलावा मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में रहने वाली सभी मक्खियों को अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है, जिनमें रानी मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खी को शामिल किया जाता है।

रानी मधुमक्खी अंडे देती है और ज्यादातर समय कॉम्ब के अंदर ही बिताती है, जबकि ड्रोन मधुमक्खी रानी के साथ मेटिंग करने का काम करते हैं।

इसके अलावा वर्कर श्रेणी की मधुमक्खियां छाते से बाहर निकल कर फूलों के मधुरस या नेक्टर (Nectar) से शहद का निर्माण करती हैं।

कैसे चुनें मधुमक्खी पालन के लिए सही जगह

मधुमक्खी पालन के लिए जगह चुनने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि इनके कृत्रिम छत्तों को उसी स्थान पर लगाएं जहां पर पानी का कोई अच्छा स्रोत उपलब्ध हो, जैसे मानव निर्मित तालाब या नदी और झील का तटीय क्षेत्र।

इसके अलावा छत्ते के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वनस्पति होनी चाहिए, जिनमें सूर्यमुखी, मोरिंगा और कई दूसरे प्रकार के फूलों के पौधे हो सकते हैं।

जगह को चुनने के बाद उसमें कृत्रिम छत्ते लगाने के उपरांत तुरंत इस जगह को बाहर से आने वाले लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

मधुमक्खी विकास क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार किसी सड़क और ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों से मधुमक्खी के छत्तों को हमेशा दूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि निरंतर ध्वनि प्रदूषण वर्कर मधुमक्खी की शहद एकत्रित करने की क्षमता को कम करने के अलावा कई प्रकार की बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है।

कैसे करें मधुमक्खी के छत्ते का चुनाव और क्या हो पूरी प्रक्रिया ?

मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले मधुमक्खी के कृत्रिम छत्ते की आवश्यकता होती है। इस छत्ते का आकार और डिज़ाइन आपके निवेश और बिजनेस की अवधी पर निर्भर कर सकता है। एक एकड़ के क्षेत्र में लगभग 3 से 4 मधुमक्खी के बड़े छत्ते लगाए जा सकते हैं।

इन छत्तों को समय पर निरंतर निगरानी करने के लिए और सुरक्षा के लिए एक बॉक्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बॉक्स में फ्लोर और बॉटम बोर्ड के अलावा लकड़ी के बने हुए फ्रेम होते है, जो कि एक सुपर चेंबर की तरह कार्य करते हैं। यह बॉक्स ऊपर और नीचे से ढका रहता है, जिसमें मधुमक्खियों के जाने के लिए जगह बनाई रहती है।

बड़े स्तर पर व्यवसाय करने के लिए कई दूसरे प्रकार के उपकरण जैसे कि क्वीन गेट, हाउस टूल और शुगर फिटर के अतिरिक्त एक स्मोकर की आवश्यकता होती है।

मधुमक्खी के छत्ते/बॉक्स को हमेशा पीले और हल्के हरे रंग से ही रंग किया चाहिए, जिससे मधुमक्खियों को जगह का आसानी से पता चल जाए, कभी भी मधुमक्खी के छत्ते को लाल या काले रंग से नहीं रँगना चाहिए।

अब इस बॉक्स रूपी छत्ते में बाहर से लाकर मधुमक्खियों को डाल दिया जाता है। भारतीय मधुमक्खियां खासतौर पर पहले से तैयार किए हुए घर में रहना पसंद करती हैं, हालांकि यूरोपीयन मधुमक्खियां कई बार इस तरह तैयार छत्तों को छोड़कर आसपास में ही अपना खुद का छत्ता भी बना लेती हैं।

मधुमक्खी पालन में आने वाली समस्याएं और लगने वाले रोग :

वैसे तो मधुमक्खियां खुद ही एक बेहतरीन पोलिनेटर के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इनमें ज्यादा बीमारियां नहीं होती है, लेकिन बदलते पर्यावरणीय प्रभाव और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से फूलों में पहुंचे दूषित और केमिकल तत्व मधुमक्खियों के शरीर में चले जाते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

वरोआ माइट (Varroa mites) :
यह कीट पिछले कई सालों से मधुमक्खी की कॉलोनियों को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह बड़ी से बड़ी मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

मुख्यतः यह लार्वा और प्यूपा की मदद से प्रजनन करते हैं और धीरे-धीरे मधुमक्खियों के छत्ते तक अपनी पहुंच बना लेते हैं।
इससे ग्रसित हुई मधुमक्खियां के पंख धीरे-धीरे टूटने लगते हैं और उनके शरीर के कई अंगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है।
हॉर्टिकल्चर क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार इस रोग के इलाज के लिए एपिवरोल टेबलेट (Apiwarol tablet) का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे पानी में मिलाकर मधुमक्खी के छाते के ऊपर तीन दिन के अंतराल में चार से पांच बार स्प्रे करना रहता है।

होर्नेट कीट (Hornet pest) :
मधुमक्खी पालन के दौरान यह कीट सबसे ज्यादा हानिकारक होता है और यह मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी पर ही आक्रमण कर देता है और उन्हें पूरी तरीके से कमजोर बना देता है और धीरे-धीरे मधुमक्खियों को मारते हुए उसके छत्ते पर ही अपना कब्जा कर लेता है।
इस प्रकार की कीट से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि उस पूरे छत्ते को ही नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि यह आसपास में ही स्थित दूसरे छत्तों में ना फैले।

हालांकि इसके अलावा भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति में कई दूसरी प्रकार की माइक्रोबियल बीमारियां भी होती है, जोकि बैक्टीरिया के अधिक वृद्धि के कारण होती है। इसके इलाज के लिए एंटीमाइक्रोबॉयल टेबलेट का एक घोल बनाकर उसे कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र में समय समय पर स्प्रे करना चाहिए।

कैसे करें मधुमक्खी की कॉलोनी का अच्छे से प्रबंधन ?

जब भी किसी फूल के पौधे से नेक्टर निकलने का समय होता है उस समय तो मधुमक्खियां अपने आप जाकर खाने की व्यवस्था कर लेती है, लेकिन बारिश और ऑक्सीजन के दौरान इनके भोजन के लिए 20 से 25 किलोग्राम शुगर की आवश्यकता होती है।
मधुमक्खी पालन के दौरान किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रजाति को भूखा नहीं रखना चाहिए और शुगर तथा पोलन सप्लीमेंट को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करके इसमें प्रोटीन के कुछ मात्रा के लिए सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं। इस तैयार पेस्ट को मधुमक्खियों की कॉलोनी के बाहर रख देना चाहिए, जिसे समय मिलने पर कॉलोनी के सभी सदस्य अपने आप भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे।

मधुमक्खी पालन बढ़ाने के लिए किए गए सरकारी प्रयास :

मधुमक्खी पालन व्यवसाय की भविष्यकारी सम्भावनाओं को समझते हुए भारत सरकार और कई स्थानीय राज्य सरकारें लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने 'स्वीट रिवॉल्यूशन' यानी 'मधु क्रांति' (Madhukranti) नाम का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जो मुख्यतः मधुमक्खी उत्पादन व्यवसाय में सक्रिय लोगों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी देने के अलावा उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है।

इसके अलावा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board – NBB) के द्वारा लांच किये गए राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन और मधु मिशन (नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन; National Beekeeping and Honey Mission – NBHM) की मदद से भारत सरकार मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले उत्पाद की गुणवत्ता की बेहतर जांच के लिए स्रोत उपलब्ध करवाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने को मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया है।

भारतीय स्टेट बैंक दुधारू पशु खरीदने के लिए किसानों को देगा लोन

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन यहां दूध की खपत भी बहुत ज्यादा है, इसलिए केंद्र तथा राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी की कोशिश कर रही हैं, ताकि घरेलू जरुरत को पूरा करने के साथ ही दूध का निर्यात भी किया जा सके। जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो सके और भारत सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाए।
इन लक्ष्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत कई नई दूध डेयरी खोली हैं तथा दूध के प्रोसेसिंग के लिए नए प्लांट लगाए हैं।
इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। इसके लिए मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक एमओयू (MOU) साइन किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन उपलब्ध करवाएगा। एमओयू में शामिल किये गए अनुबंधों के अनुसार, अब दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन दिलाने में सहायता करेंगे।
मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक तरूण राठी ने बताया कि दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में जो भी समितियां आती हैं, उनके पात्र सदस्यों को त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत दुधारू पशु खरीदने में मदद की जाएगी। पात्र समिति सदस्य या किसान 2 से लेकर 8 पशु तक खरीद सकता है। इसके लिए प्रत्येक जिले में भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाएं लोन उपलब्ध करवाएंगी।
लोन लेने वाले किसान को प्रारंभिक रूप में 10 प्रतिशत रूपये मार्जिन मनी (Margin Money) के रूप में जमा करना होगा। उसके बाद 10 लाख रुपये तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही किसान को 1 लाख 60 हजार रुपए का नान मुद्रा लोन बिना कुछ गिरवी रखे, त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत दिलवाया जाएगा।

जिस किसान या पशुपालक ने पशु खरीदने के लिए लोन लिया है, उसे यह रकम 36 किस्तों में बैंक को वापस करनी होगी। लोन लेने वाले किसान को समिति में दूध देना अनिवार्य होगा। जिसके बाद समिति प्रति माह दूध की कुल राशि का 30 प्रतिशत, लोन देने के लिए बैंक को भुगतान करेगी। बाकी 70 प्रतिशत किसान को दे देगी। लोन लेने के लिए पात्र किसान को दुग्ध संघ द्वारा जारी किये गए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ फोटो, वोटर आईडी, पेनकार्ड, आधार कार्ड, दुग्ध समिति की सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र तथा त्रि-पक्षीय अनुबंध (संबंधित बैंक शाखा, समिति एवं समिति सदस्य के मध्य) आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। जिसके बाद उन्हें दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रगतिशील किसान

मोती की खेती से बम्पर कमाई कर रहा है बिहार का आईटी प्रोफेशनल

बिहार राज्य के बेगुसराई जनपद में सिंघोला निवासी कुणाल कुमार झा (Kunal Kumar Jha) ने अपने घर में ही छोटी सी जल की टंकी बनाकर मोती की खेती (pearl farming; moti ki kheti) करना शुरू कर दिया है। कुणाल का कहना है कि वह मोती की खेती से प्रतिवर्ष ३ लाख रूपए तक का लाभ प्राप्त करते हैं। रचनात्मक सोच, जुनून और मेहनत के बल पर मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। कुणाल कुमार झा ने भी युवाओं के लिए एक नजीर पेश की है, हालाँकि कुणाल आईटी टेक्निकल के सफल विद्यार्धी रहे हैं, साथ ही प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर चुके हैं।

लेकिन कुणाल अपनी आय की राह स्वयं चुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी की अपेक्षा कृषि को प्राथमिकता दी और कृषि की सहायता से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। घर में अनोखे अंदाज से खेती करने की प्रणाली की बात पुरे बेगूसराय में चर्चा का विषय बन चुकी है। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ चुका है, साथ ही नए नए कृषि उपकरण भी खेती किसानी को बेहतर बनाने के लिए दिनो दिन इजात हो रहे हैं। ऐसे में समझदारी से कृषि करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, कुणाल ने यह बात साबित भी करदी है।

कुणाल किस प्रकार करते है मोती की खेती

कुणाल कुमार झा ने अपने घर में १० बाई १० वर्ग फीट की टंकी से ही मोती की खेती को सुचारु रखा हुआ है, कुणाल मोती को देवताओं का स्वरुप भी प्रदान करते हैं, जो समुद्र में रेती के कारण नहीं बन पाता है। कुणाल प्रभु श्री राम, कृष्ण भगवान एवं गणेश जी जैसे अन्य स्वरूपों की कलाकृति बनाते हैं। यह मोती लगभग १० महीने में बनकर तैयार होता है, कुणाल मोती की खेती रचनात्मक तरीके से करके अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर लेता है।

कुणाल ने कृषि को प्राथमिकता क्यों दी

कुणाल कुमार झा आईटी प्रोफेशनल हैं उन्होंने नौकरी करते समय ही खेती करने का निर्णय लिया था। कुणाल का कहना है कि देश के अधिकतर नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं। युवाओं को आजीविका के लिए उनकी मेहनत से भी कम आय वाली नौकरी करनी पड़ती है और उसके लिए भी उनको अन्य राज्यों के शहरों में नौकरी करने जाना पड़ता है। इससे अच्छा, युवा आधुनिक तकनीक और विवेक का इस्तेमाल करके स्वयं का रोजगार उत्पन्न करें। आज देश में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, युवाओं को अपने नजरिये और सोचने की दिशा को बदलने की बेहद आवश्यकता है।

मोती की खेती का बाजार में कितना दबदबा है

बाजार में मोती की काफी मांग है, गुजरात तक से व्यापारी खुद आकर मोती खरीदकर ले जाते हैं। कुणाल की ये अद्भुत खेती क्षेत्र और परिवार के लोगों को खुशी प्रदान कर रही है। मोती की खेती की चर्चा जोरशोर से आसपास के जिलों में भी हो रही है। कुणाल से मोती की खेती के बारे जानने के लिए काफी दूर से किसान आ रहे हैं, कुणाल खेती की पूरी विधि किसानों के साथ साझा भी करते हैं। कुणाल कुमार झा ने मोती की खेती का महत्त्व भी जिले के किसानों को अच्छी तरह बताया है।

युवक की किस्मत बदली सब्जियों की खेती ने, कमाया बेहद मुनाफा

सब्जियों की खेती के लिए काफी समझ और मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब्जियों की मांग के हिसाब से किसानों को सब्जी उत्पादन करना बेहद आवश्यक होता है, जिससे कि सब्जियों का सही और लाभप्रद मूल्य मिल सके।

देशभर में भिन्न भिन्न जगहों पर सब्जी की मांग उस क्षेत्र की भौगोलिक स्तिथि के अनुरूप होती है। अलग अलग जगहों पर सब्जी एवं अन्य खाद्यान्न पदार्थों की अहम भूमिका होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कश्मीर के शोपियां जिले के मोहम्मद अयूब ने सब्जियों की खेती की और उन सब्जियों को उगाने में प्राथमिकता दी जिन सब्जियों की बाज़ार में अत्यधिक मांग है, और इस वजह से मोहम्मद अयूब काफी मुनाफा कमाते हैं।

मोहम्मद अयूब की सफलता की कहानी

मोहम्मद अयूब जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में सफा नगरी नामक गांव में रहते हैं। आजीविका के लिए सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की तलाश में इधर से उधर प्रयास किया, लेकिन कोई आय का साधन नहीं मिला। उसके बाद मोहम्मद अयूब ने खेती के माध्यम से आय का स्त्रोत बनाने का निश्चय किया और बाजार में कौन सी फसल सबसे अधिक फायदा प्रदान कर सकती है, इस बारे में विचार विमर्श करके अत्याधिक मांग वाली सब्जियों का चयन किया। सब्जियों की अच्छी तरह देखरेख करके अयूब ने बेहतर उत्पादन किया और सब्जिओं के उत्पादन से अच्छा खासा मुनाफा कमाया है।

अयूब प्रति वर्ष कितना मुनाफा कमा लेते हैं ?

मोहम्मद अयूब सब्जियों के उत्पादन से लगभग ६ लाख तक का मुनाफा कमा लेते हैं। उपरोक्त में जैसा कि बताया गया है, अयूब ने अत्यधिक मांग वाली सब्जियों का चयन किया जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा कमाने में सहायता हुई। अयूब खुद की २ अकड़ ज़मीन को किसी भी समय खाली नहीं छोड़ते हैं।

सेब के दाम में भारी गिरावट से सम्बधित अयूब ने क्या कहा ?

इस सन्दर्भ में अयूब ने बोला है कि सेब के अत्यधिक उत्पादन के चलते सेब के दाम में कमी आयी है, लेकिन मूली के उत्पादन से अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कश्मीर की पहचान एक हॉर्टिकल्चर राज्य के रूप में है।

महाराष्ट्र में पिता के अथक परिश्रम से प्रेरित बच्चे ने बनाया कम खर्च वाला ड्रोन

महाराष्ट्र राज्य में एक किसान के बेटे ने अपने पिता को दिन रात खेत में पसीना बहाते देख कर उनकी मेहनत को आसान बनाने का संकल्प लिया और अपनी बुद्धिमता और समझदारी से कम खर्च में, खेत में स्प्रे करने वाला ड्रोन (Drone) का निर्माण कर दिया जो कि किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाला है।

ड्रोन की सहायता से किसान अपने खेतों में कीटनाशकों से बचाव के लिए छिड़काव के साथ ही अपने खेतों की देख रेख भी आसानी से कर सकते हैं। किसानों की हालत आजकल बेहद नाजुक व दयनीय है, क्योंकि किसान की फसल कई सारे कारको पर निर्भर करती है, जिसमें आंतरिक व बाहरी कारक भी सम्मिलित हैं। हाल ही में देश के कई राज्यों की फसल अत्यधिक बारिश के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।

कितने खर्च में तैयार हो जाता है यह ड्रोन ?

महाराष्ट्र में वर्धा जिले, हिंगणघाट शहर के राम कावले ने २.५० लाख रुपये के खर्च में, १५ से २० मिनट में १ एकड़ स्प्रे करने वाला ड्रोन तैयार किया है, जिसकी क्षमता लगभग १० लीटर है। ड्रोन को बनाने के लिए राम कावले ने अपने दादाजी व अन्य रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता ली।

ड्रोन को बनाने के लिए राम कावले ने बहुत परिश्रम किया है, साथ ही अपनी अद्भुत प्रतिभा का भी परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में राम कावले ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ड्रोन की सहायता से किसानों को छिड़काव में आसानी तो होगी ही, साथ ही आधुनिक कृषि उपकरण में भी अपना स्थान दर्ज किया है।

ड्रोन बनाने के लिए राम कावले ने कितनी चुनौतियों का सामना किया ?

किसान की दयनीय हालत से सभी अवगत हैं, उपरोक्त में जैसा बताया है कि किसान की आय कई सारे कारकों पे निर्भर करती है, ऐसे में कृषक परिवार से सम्बंधित व्यक्ति की इस प्रकार की रचनात्मक सोच बेहद सराहनीय है और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत है।

किसानों के हित में राम कावले द्वारा बनाया गया ड्रोन किसानों के बीच काफी चर्चा में है, जिसको तैयार करने के लिए कावले ने आर्थिक और पर्याप्त संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना किया है।

किसने दिया राम कावले को जरूरी मदद का आश्वासन ?

राम कावले के जिले के विधायक सुमीर कुंवर ने कावले को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया, साथ ही कृषि जगत में आधुनिक उपकरणों की खोज व महत्तव के बारे में भी अवगत किया। उनका कहना है कि किसानों को आज आवश्यकता है आधुनिक उपकरणों की, जिससे वह कम से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। राम कावले का इस दिशा में योगदान सराहनीय है।

भंवरपाल सिंह : वकील से लेकर सर्वश्रेष्ठ आलू उत्पादक अवॉर्ड पाने तक का सफर

कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से महुवा गांव, सरसौल ब्लाक, कानपुर जनपद के भंवरपाल सिंह ने सर्वश्रेष्ठ आलू उत्पादक बनकर मिसाल कायम की है।

भंवरपाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील थे, लेकिन माता पिता की मृत्यु के उपरांत वकालत छोड़कर किसानी करने का फैसला किया। शुरुआत में ही उन्होंने आलू की खेती को प्राथमिकता दी एवं एक सफल आलू उत्पादक बनकर समाज व कृषकों के लिए उदाहरण बने। वे प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। आजकल किसानों की हालत बहुत दयनीय है, लेकिन भंवरपाल सिंह ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसानों की खेती करने की रणनीति और समझदारी में कोई तो त्रुटि है, क्योंकि समान परिस्थितियों के होते हुए भंवरपाल जी ने इस स्तर की उपलब्धि हासिल की है।

कैसे आलू की खेती ने भंवरपाल को दिलाया सम्मान ?

आलू एक ऐसी फसल है जिसका मानव जीवन के खानपान से अभिन्न नाता है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियों में आलू का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी नमकीन व चिप्स कम्पनियाँ भी आलू खरीदी की मांग रखती हैं। आलू की अत्यधिक मांग के चलते भंवरपाल स्वयं की भूमि के साथ साथ दूसरों की भूमि भी किराये बतौर लेकर, अनुमानित १२२० एकड़ जमीन पर आलू की खेती करते हैं।

एक एकड़ की अनुमानित पैदावार ४०० से ५०० कुन्तल होती है, साथ ही प्रति हेक्टेयर में लगभग डेढ़ लाख का लाभ अर्जित करते हैं। उपरोक्त गणित के अनुरूप भंवरलाल सिंह प्रतिवर्ष १ करोड़ की राशि मुनाफा के तौर पर कमाते हैं।

भंवरपाल अभी तक कितने अवॉर्ड से सम्मानित हुए हैं ?

भंवरपाल जी ने अब तक कई अवॉर्ड हासिल किये हैं, जिनमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय वर्ष २०१३ में गुजरात वैश्विक कृषि समिट में सम्मानित किया। साथ ही सन २०२० में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भंवरपाल जी की काबिलियत और मेहनत को देखते हुए ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, गाँधी नगर में एक आदर्श किसान के रूप में सर्वश्रेष्ठ आलू के उत्पादन के फलस्वरूप अवॉर्ड से सम्मानित कर चुके हैं। भंवरपाल जी किसानों के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं।

कितने विख्यात हैं भंवरपाल आलू उत्पादक के रूप में ?

भंवरपाल जी की छवि एक उत्तम आलू उत्पादक के रूप में लगभग पुरे उत्तर प्रदेश में है, साथ ही वह तरह तरह के आलू वैरायटी को विभिन्न राज्यों में निर्यात करते हैं, जिसमें कुफरी मोहन, कुफरी सुखाती, कुफरी गंगा, कुफरी नीलकंठो, कुफरी चंद्रमुखी आदि वैरायटी सम्मिलित हैं। भंवरपाल भिन्न भिन्न वैरायटी का उत्पादन करते हैं।

जहां किसान जहरीले बिच्छू को छूने से भी डरते हैं, वहीं एक किसान ने डंक मारने वाले जहरीले बिच्छूओं को ही अपनी कमाई का साधन बना लिया है और आज उन बिच्छूओं से ही लाखों की कमाई कर रहे हैं।

तुर्की के दक्षिणपूर्व स्थित सैनलियुर्फा (Sanliurfa) में पेशेवर किसान मेटिन ओरेनलर ने अपना एक फार्म खोल रखा है। इस फार्म में वह सैकड़ों डंक मारने वाले बिच्छूओं का पालन करते हैं, बाकायदा बिच्छूओं को सुबह-शाम खिलाया-पिलाया जाता है। इसके अलावा विशेषज्ञों की निगरानी में उनकी देखरेख भी होती है। जब बिच्छूओं में अच्छी माला में जहर इकट्ठा हो जाता है तो फार्म के कर्मचारी उनका जहर निकाल लेते हैं, जो बाजार में काफी महंगा बिकता है। अब इसी डंक मारने वाले बिच्छूओं के कारोबार से किसान मेटिन ओरेनलर लाखों की कमाई कर रहे हैं।

बिच्छूओं के जहर से बनता है पाउडर

फार्म स्वामी मेटिन ओरेनलर के अनुसार डंक मारने वाले जहरीले बिच्छूओं से निकलने वाले जहर को एक विशेष प्रकार से बनाए गए प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाता है, और डिब्बों को फार्म की प्रयोगशाला में फ्रीज करके रख दिया जाता है। बाद में उस जहर का पाउडर बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है।

एक बिच्छू में निकलता है कितना जहर ?

ओरेनलर ने अपने फार्म में 20 हजार से ज्यादा एंड्रोक्ट्स तुर्कियंसिस (Androctonus turkiyensis) बिच्छू पाल रखे हैं।

सभी बिच्छूओं को उनकी जरूरत के हिसाब से खाना दिया जाता है, इसके बाद उनका जहर निकाला जाता है। बताया जाता है कि एक बिच्छू से करीब 2 मिलीग्राम जहर निकलता है। इस तरह वह एक बार में करीब 2 ग्राम जहर निकाल लेते हैं।

इंसानों की जान लेने में सक्षम होता है बिच्छू का जहर

बिच्छू का जहर इंसानों की जान लेने में सक्षम होता है, बिच्छू ठंडी व गर्म दोनों तरह की जगहों पर पाया जाता है। वैज्ञानिक अभी तक बिच्छू की 2000 प्रजातियों का पता लगा चुके हैं, जिनमें 40 प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसान की जान ले सकती हैं।

बिच्छू के जहर की कीमत क्या है?

फार्म में बिच्छूओं के जहर का पाउडर बनाकर इसे यूरोप सप्लाई किया जाता है, जिससे अच्छी कमाई होती है। इन दिनों 1 लीटर बिच्छू के जहर की कीमत करीब 10 मिलियन डॉलर है। भारतीय मुद्रा के अनुसार ये राशि करीब 79 करोड़ है, हालांकि ओरेनलर अपनी कमाई के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन वह महीने भर में लाखों रुपए कमा लेते हैं।

मेरी खेती

MERIKHETI.COM